https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

सही मायने में बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमागों में आते रहते हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए उन पर गहराई से तब तक विचार करना चाहिए जब तक वे हमारी अनुभूति में जड़ न जमा लें ।

– गोथे

दोहरा रवैया

कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत द्वारा घोषित एक आतंकी और खालिस्तान समर्थक को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वहां की खुफिया एजंसी एफबीआइ ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को अति वांछित घोषित किया है। इससे संबंधित एक सचित्र पोस्टर भी जारी कर दिया है। एफबीआइ ने उसे भारतीय खुफिया एजंसी 'रा' का एजंट बताया है। उसके खिलाफ न्यूयार्क की एक अदालत में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हालांकि भारत सरकार ने एफबीआइ के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि वह व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि दो भारतीय नागरिकों ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, उसे मारने के लिए निशानेबाजों को पैसे भी दिए थे। इस संबंध में भारत और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों की परस्पर बातचीत भी हुई, मगर अमेरिका अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि इस तरह किसी दूसरे देश के नागरिक उसके देश में घुस कर उसी के नागरिक की हत्या की साजिश रचेंगे, तो यह अक्षम्य अपराध है। जिन दो भारतीय नागरिकों को साजिशकर्ता बताया गया है, उन पर धनशोधन और गलत तरीके से धन की लेनदेन का भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

कनाडा का आरोप है कि उसके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजंसियों के लोग शामिल थे। यहां तक कि उसने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इस साजिश में शामिल बता दिया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा से अपने सभी दूतों को वापस बुला लिया और कनाडा के दूतों को वापस भेज दिया। अब पन्नू मामले को तूल देकर एक तरह से अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है। इन दोनों देशों की अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता एक बात है, मगर उनके ताजा रुख से आतंकवाद को लेकर उनका दोहरा रवैया ही पता चलता है। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। भारत शुरू से अमेरिका की इस मुहिम में साथ खड़ा रहा है। मगर विचित्र है कि भारत ने जिन आतंकियों को वांछित घोषित कर रखा है, उनके खिलाफ न तो कनाडा ने कभी सकारात्मक रुख दिखाया और न अमेरिका ने। जिस पन्नू को लेकर अमेरिका नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का परचम फहरा रहा है, वह भारत का घोषित आतंकी है।

यह कोई नई बात नहीं है कि कई देश अपने यहां आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ दूसरे देशों में भी घुस कर अभियान चलाते रहे हैं। अमेरिका खुद अपने घोषित आतंकियों की पहचान कर दूसरे देशों की जमीन पर उन्हें मार चुका है। वह बड़े गर्व से इसका बखान भी करता रहा है, चाहे वह लादेन रहा हो, अल-जवाहिरी या कासिम सुलामानी। इजराइल भी यही काम करता रहा है। भारत तो उनसे अपने आतंकियों के खिलाफ उनसे कार्रवाई की मांग करता रहा है, उस पर ध्यान देना उन्हें जरूरी नहीं लगता। पन्नू मामले को इतना तूल देकर आखिर अमेरिका ने यही साबित किया है कि दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने वालों के प्रति उसका रवैया नरम है। उसके इस रुख से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और कमजोर होगी।

आतंक का सिलसिला

कश्मीर में पिछले कुछ समय से, बाहरी राज्यों से गए मजदूरों पर, लक्षित आतंकी हमलों का जो दौर शुरू हुआ है और उसमें जैसी निरंतरता देखी जा रही है, वह अब सरकार और वहां तैनात सुरक्षा बलों के लिए एक जटिल चुनौती बन रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक प्रवासी मजदूर का शव मिला था। रोजी-रोटी की तलाश में बिहार से वहां गए मजदूर को दो गोलियां मारी गई थीं। अनुमान है कि दहशतगर्दों ने लक्षित हमले की अपनी रणनीति के तहत उस मजदूर की हत्या कर दी। यों, यह कोई पहली घटना नहीं है, मगर सच यह है कि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों के शिविरों से लेकर प्रवासी मजदूरों तक के घरों पर हमला करने के पीछे उनकी हताशा दिखती है। हालांकि आतंकवादी गिरोहों से किसी तरह के विवेक की उम्मीद करना बेमानी है, मगर हैरानी की बात यह है कि बेहद कमजोर तबके के ऐसे लोगों को भी मार डालने में वे नहीं हिचकते, जो महज रोजी-रोटी की उम्मीद में अपनी जमीन से उखड़ कर वहां पहुंचे होते हैं।

जम्मू-कश्मीर में लक्षित हमलों के रूप में आतंकी हमलों की यह नई प्रकृति है, जिसमें आतंक का दायरा फैल रहा है। निश्चित रूप से यह चिंता की बात है और सुरक्षा बलों के साथ सरकार को आतंकवाद के इस नए चेहरे से निपटने के लिए अलग रणनीति पर काम करने की जरूरत है। इस समस्या के जटिल होते जाने की मुख्य वजह यह रही है कि इसके तार सीमा पार के ठिकानों से संचालित संगठनों से जुड़े हैं। वहीं से मिलने वाले संरक्षण और पोषण का नतीजा है कि कभी सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला करके, तो कभी किसी प्रवासी मजदूर की हत्या कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद वहां एक चुनी हुई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाद यह स्वाभाविक उम्मीद जगी है कि वह अपनी सीमा में आतंकवाद और खासतौर पर लक्षित हमलों पर काबू पाने के मामले में सख्त कदम उठाएगी। यही उसकी कसौटी भी है कि इस दिशा में वह क्या कर पाती है।

तरक्की की मीनारें और गुरबत के दाग

देश ने पचहत्तर वर्ष की आजादी मना ली। अब शतकीय महोत्सव मनाने की ओर बढ़ रहा है। संकल्प है कि विकसित भारत में खुशहाली के सूचकांकों की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा, लेकिन यहां विरोधाभास नजर आ रहा है।

सुरेश सेठ

यह अजब विरोधाभास है कि ज्यों-ज्यों किसी देश में आर्थिक प्रगति होती है, त्यों-त्यों वहां अमीर और अमीर होते चले जाते हैं तथा गरीब और गरीब। यह विरोधाभास सशक्त पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। तीसरी दुनिया के देशों में भी देखने को मिलता है। जहां तक भारत का संबंध है, यह विरोधाभास इस हद तक पहुंच गया है कि हम कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है, जिसमें गरीब बसते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से ऊपर कोई और पुरस्कार या सम्मान नहीं माना जाता। अलग-अलग पांच विधाओं में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से एक विधा है साहित्य। साहित्य जीवन के कितना नजदीक है, यह बात इस बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीन अर्थशास्त्रियों- डारोन एसेमोग्लू, साइमन जानसन और जेम्स ए रोबिन्सन के शोध प्रबंधों से सामने आती है। इन शोध प्रबंधों में आर्थिक तरक्की के साथ-साथ गरीबी और अमीरी के भेद के मिटते जाने के कारणों की विशद चर्चा की गई है। स्पष्ट है कि इस चर्चा का समाधान भी यही शोध प्रबंध दे रहे हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसमें काम करती हुई विभिन्न संस्थाओं के सुधार के साथ ही गरीब और अमीर का भेद मिट जाएगा।

जहां तक दुनिया में शासन का संबंध है, अमीर देशों ने जिन देशों को सैन्य बल से और अब अपने आर्थिक बल से अपना उपनिवेश बना रखा है, वहां की तरक्की का अध्ययन करते हुए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अगर एक स्वस्थ दृष्टिकोण से चलाया जाए, तो गरीबी और अमीरी का भेद अपने आप खत्म हो जाएगा। चाहे इन उपनिवेशों ने शुरू में थोड़ी बहुत तरक्की दिखाई, लेकिन बाद में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवहार पर सत्तारूढ़ दल की वर्चस्ववादी नीतियों के कारण ये देश पिछड़ेपन और गरीबी के रसातल में डूब गए। नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्रियों की यह त्रयी बताती है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और मैक्सिको का लंबा सीमांत देखा जा सकता है। एक गांव ले लीजिए- नोगल्स, जो मैक्सिको में है और पिछड़ेपन के रसातल में डूबा है। सीमा पार होते ही अमेरिका है, जो तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूगोल या संस्कृति किसी इलाके की आर्थिक संपन्नता या विपन्नता तय नहीं करती, बल्कि वे संस्थान तय करते हैं, जिनके अधीन उस देश के नागरिक जी रहे हैं। अमेरिका में स्थिति बेहतर मिली, क्योंकि वहां अमेरिकियों को अपनी शिक्षा और पेशा चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी और अमेरिका का प्रजातांत्रिक ढांचा उन्हें राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दे रहा था।

नोबेल पुरस्कार विजेता इसी प्रश्न से जूझते और बताते हैं कि अपना देश चूंकि सैकड़ों वर्ष तक गुलामी की चक्की में पिसता रहा, और यहां आई विदेशी सत्ता यानी इंग्लैंड ने इस प्रकार की नीतियों का पालन किया, जिसमें हमारी संपदा का शोषण अधिक था, लेकिन देश के प्राकृतिक साधनों, श्रमशक्ति और निवेश उद्यम को सही दिशा देकर विकास का

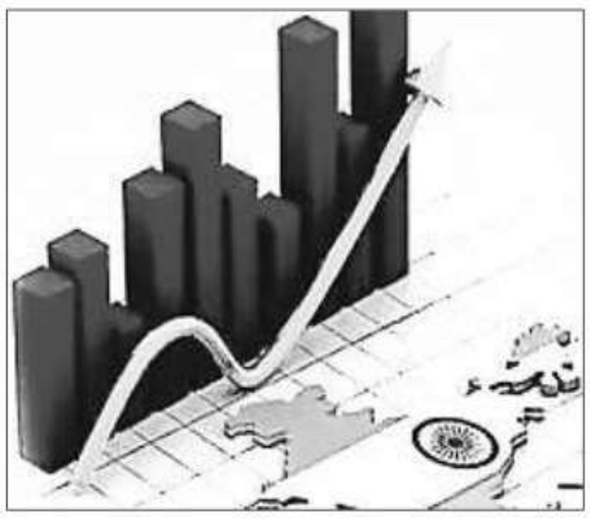

माहौल नहीं बनाया गया था। यही कारण रहा कि जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय हम पिछड़ेपन के कगार पर थे। भारत सरकार ने वर्ष 1951 में इसी पिछड़ेपन के अभिशाप को दूर करने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास का संकल्प लिया। इस संकल्प में निहित था कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी मेहनत के साथ बुनियादी ढांचे को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि देश में एक समावेशी माहौल बनाया जा सके। अमीर और गरीब दो अलग-अलग खाइयों में बंटते नजर न आएं, बल्कि विकास पथ के सहयात्री बन कर देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ।

> आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुंहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महंगाई दस बार रेपो रेट न बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसी हालत में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी यही कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा, तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आजादी रहेगी।

देश ने पचहत्तर वर्ष की आजादी मना ली। अब शतकीय महोत्सव मनाने की ओर बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है कि विकसित भारत में खुशहाली के सूचकांकों की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा, लेकिन यहां भी विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है। एक ओर सरकार कहती है कि देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और वह दुनिया में पांचवीं आर्थिक शक्ति बन गया है। यही नहीं, दो-तीन वर्ष में भारत का संकल्प तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का है और कर्तव्य पथ पर चलते हुए, जब यह देश आजादी का शतकीय महोत्सव मनाएगा, तो यह पूरी तरह से विकसित होगा। मगर जब देश के यथार्थ की ओर देखते हैं, तो यह दावा दिवास्वप्न लगता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में तरक्की हुई है। चुनिंदा धनपतियों की संख्या इस प्रकार बढ़ी है कि उनका देश की प्राकृतिक और भौतिक संपदा के 90 फीसद हिस्से पर कब्जा हो गया है। वहीं देश की अधिकांश आबादी, जो वंचितों और गरीबों की है, वह केवल दस फीसद संपदा पर जीने के लिए अभिशप्त है। इसके कारण संविधान में रखा गया प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्रियों के शोध को पढ़ें, तो कारण साफ नजर आता है कि अपना देश प्रजातांत्रिक अवश्य है, लेकिन यहां व्यवस्था कितनी जर्जर और नकारात्मक हो गई है कि आम लोग अपने जीवन मूल्य को बदलते नजर आ रहे हैं। हालत यह हो गई है कि एशिया में सर्वाधिक खरबपति अगर भारत में हैं, तो भूख से मरते लोगों की संख्या भी अभी आए वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार मध्यवर्ग के देशों से भी कहीं पीछे है।

आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुंहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महंगाई दस बार रेपो रेट न बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसी हालत में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी यही कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा, तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आजादी रहेगी। यह आजादी ही हमारे दीर्घकालिक विकास की नींव रखेगी।

निस्संदेह सरकार देश के लिए बहुत बड़े-बड़े सपने बना कर जनता जनार्दन को भेंट करती है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए स्वस्थ और दोष रहित प्रशासन, शैक्षणिक ढांचे और सामाजिक कदाचार में बेहतरी की निरंतर उम्मीद चाहिए। देश में ऐसा नहीं हो रहा। प्रजातांत्रिक ढांचे के बावजूद हम सड़क पर चलते औसत आदमी की बेहतरी के लिहाज से पिछड़ रहे हैं। इसलिए एक स्वस्थ और दोषरहित प्रजातंत्र की कल्पना इस वर्ष के नोबेल विजेताओं ने की है और इसी का सपना भारत के लोग भी दिन-रात देखते हैं। अब अकादमिक शोध का समर्थन मिल जाने से उन्हें बल मिला है।

उदासी चुंबकीय है

त्रिवंकल तोमर सिंह

दुख एक ज्वार की तरह जीवन में आता है, जिसमें मन का सारा उल्लास टूटे तिनकों की तरह बह जाता है। उदासी मन पर कितने दिन हावी रहेगी, यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक दुख की तीव्रता क्या है, दूसरा इससे बाहर निकलने के लिए कोई कितना प्रयास करता है। दोनों ही बातों में समय लगता है, जैसे कि कोई भी फल स्वाभाविक रूप से पकता है। कहा जाता है कि समय कैसा भी हो, एक अध्यापक की तरह हमेशा कुछ न कुछ पाठ पढ़ा ही जाता है। दुख अगर उदासी के पारावार में डुबो दे रहा है, तो गहराई के दर्शन भी करा देता है। गंभीर और उदास लोगों ने जीवन को जितनी अच्छी तरह से समझा है, उतना खुद में मग्न और सुखी व्यक्तियों ने कभी नहीं।

जीवन मात्र सुख और भोगों में डुबा देने के लिए नहीं है। कोलाहल से तनिक परे हटकर, मेले से थोड़ी दूरी बना कर इस जीवन की सार्थकता या निरर्थकता पर विचार करने का सामर्थ्य उदास लोगों के जिम्मे आ गया। यह अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। रास-रंग में डूबा रहने वाला व्यक्ति कभी दार्शनिक नहीं होता। उदास लोगों के चेहरे पर गंभीरता का सौंदर्य दमकने लगता है। उदास आंखों में जितनी गहराई होती है, उतनी कहीं भी नहीं।

उदास लोगों के पास प्रफुल्लित लोगों की तुलना में बहुत कुछ होता है, जो सुंदर है, प्रेरणादायक है और चुंबकीय है। उदास लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की गंभीरता पकने लगती है। वे मौके-बेमौके अनावश्यक बोलना पसंद नहीं करते। वे निष्प्रयोजन वृथा बात कभी नहीं कहते। उनकी ऊर्जा एक विशेष चिंतन प्रवाह की ओर चलायमान होने लगती है। उदास व्यक्तियों को मौन रहना, अपने दुख के साथ रहना, शोक मनाते रहना पसंद होता है। वे अपने आसपास की भीड़ को देखकर मनन करते रहते हैं कि ये इतने प्रसन्न क्यों हैं! सभी धारा के साथ एक दिशा में बहते जा रहे हों, जिनके लिए प्रसन्नता के मानक एक समान हों, उनमें कोई ऐसा हो जो धारा के विपरीत सोच सके। ऐसे लोगों में एक विरक्ति का भाव उपजने लगता है, उनका चिंतन गहराने लगता है।

हालांकि उदासी की अपेक्षा कोई नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए। यह कोई उचित और आकर्षक ठहराने वाली परिस्थिति नहीं है कि दुख या उदासी कोई महान चीज है। मगर एक भाव जरूर है, जो व्यक्तित्व को, जीवन को प्रभावित करता है। दरअसल, दुख उदासी लाता है तो अंतर्मुखी भी बना देता है। यह दुख का सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया में जितने भी विचारक या दार्शनिक हुए हैं, वे सब अंतर्मुखी रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात बचपन से ही गंभीर थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नहीं, बल्कि उन्हें चुपचाप देखना, उनके क्रिया-कलापों को दूर से निरीक्षण करना पसंद करते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, 'कभी-कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है।' अंतर्मुखी होना कुछ यों है कि नीरवता में प्रकृति की झांझर सुनने का प्रयास करना।

एक बहुत सुंदर कहावत है कि टूटे हुए लोगों ने दुनिया को सबसे अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया है। इसका एक विशेष कारण भी है। टूटे हुए लोगों के हृदय में करुणा के अंकुर फूट पड़ते हैं। उन्हें अपने जैसे दुखी लोगों के साथ एक बंधुत्व का अनुभव होता है। साझा दुख से बढ़कर आसंजक कुछ भी नहीं। सुख स्वार्थी बना सकता है, दुख निस्वार्थ होने की ओर प्रेरित करता है। जो प्रफुल्लित है, सुखी है, स्वयं में मगन है, उसके पास दूसरों का दुख देखने का समय कहां? और अगर देख भी लिया तो उसकी तीव्रता अनुभव करने लायक संवेदना कहां? जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। करुणा एक शक्तिशाली संवेदना है, जो यह भाव देती है कि जैसे मैं दुखी रहा, वैसे दूसरों को दुखी नहीं रहने दूंगा। यह हृदय में सेवा की इच्छा को पल्लवित करती है।

उदास लोगों के पास एक विचित्र प्रकार का चुंबकत्व आ जाता है। उनकी गंभीरता आकर्षित करती है। उनका चिंतन प्रवाह दार्शनिक हो जाता है, जिसमें गोते लगाने से कुछ बेहद संघनित तात्त्विक दर्शन के मोती प्राप्त हो जाते हैं। हम अगर ऐसे लोगों के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, तो पाएंगे कि जाने कितने घंटों के घोर चिंतन के बाद जो नवनीत उनके पास इकट्ठा हुआ है, वह कितना समृद्ध है, मूल्यवान है। उनके शब्दों के अर्थ कितने गहरे होते हैं। उनके जीवन के अनुभव का सारा रस उनकी वाणी को सराबोर कर देता है।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जिन लोगों ने दुख सहा, उससे लड़ाई लड़ी, ईश्वर से दुखी होकर प्रश्न पूछे, स्वयं ही उत्तर खोजने की दिशा में चल दिए, वे उदास थे, दुख को समझने की चुनौती उठाने वाले लोग थे, अवसादी या मानसिक रोगी नहीं। अगर अवसाद या निराशा उनके जीवन में आई होगी तो उन्हें कमजोर नहीं बना सकी होगी। थोड़े दिनों में उन्हें इन बादलों के पार देखना पड़ा होगा। दुख तोड़ देता है तो हताशा जन्म लेती है, वहीं दुख कुछ लोगों के जीवन में एक फीनिक्स पक्षी की तरह आता है, वे शून्य पर सिमट जाएं तो भी पुनर्जीवित होते हैं, और अच्छे से लड़ाई लड़ने के लिए, दुनिया को कुछ देकर जाने के लिए। प्रसिद्ध विचारक विक्टर ह्यूगो ने एक सुंदर बात कही है- 'मेलनकली इज द हैप्पीनेस आफ बीइंग सैड।' मतलब उदासी दुखी होने का सुख है।

दुनिया मेरे आगे

> सुख स्वार्थी बना सकता है, दुख निस्वार्थ होने की ओर प्रेरित करता है। जो प्रफुल्लित है, सुखी है, स्वयं में मगन है, उसके पास दूसरों का दुख देखने का समय कहां? और अगर देख भी लिया तो उसकी तीव्रता अनुभव करने लायक संवेदना कहां? जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।

संवाद के मायने

हाल ही में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। यह बैठक की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह थी कि जयशंकर पाकिस्तान में थे। पाकिस्तानी नागरिक उनके आने से बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। फिर भी, पाकिस्तानी इसे नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत का एक मौका मान रहे थे। इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के आम लोगों में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की इच्छा बढ़ रही है। भले ही पाकिस्तान के शासक इस मुद्दे पर कुछ भी सोचें, लेकिन आम लोग बातचीत के पक्ष में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि लोगों की यह इच्छा पूरी न हो, लेकिन यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान के नागरिक भारत से वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। वे भारत के साथ व्यापार शुरू करके अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं।

– चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

साइबर जाल

साइबर अपराध का बढ़ता दायरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। आजकल सोशल मीडिया मंच के जरिए विमान में बम रखे जाने की झूठी खबर देकर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं देकर विमानन कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजंसियों के सामने संकट पैदा किया जा रहा है। किसी भी तरह की सूचना मिलने के बाद विमान को पास के हवाईअड्डे पर उतार कर उसकी सघन जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देरी होती है। वहीं यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लिहाजा झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। फर्जी ई-मेल आइडी और अन्य सोशल नेटवर्किंग आइडी के जरिए सूचना भेजना सामान्य बात हो चुकी है। आज भी कई स्थानों पर बिना पूरी जांच के सिम कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

– हिमांशु शेखर, गया

दवा के जोखिम

आजकल छोटी-मोटी बीमारियों में गोलियों की जरूरत आम बात है। कई लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज अपनी समझ और अनुभव के आधार पर कर लेते हैं। आज दवा बाजार में नकली दवाइयां जानलेवा साबित हो सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक या लगातार सेवन से जो रपट सामने आई है, वह चिंताजनक है। रपट के अनुसार शरीर में रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति लगातार प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर रहे हैं। इससे दवाओं का असर क्षीण होता जा रहा है। आइसीएमआर के अध्ययन में आई इस जानकारी के बाद लोगों को अपने रोग और उनके इलाज के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे बीमारियों की वजह अनियमित दिनचर्या भी है जो आजकल सुविधाभोगी लोगों में अधिक नजर आती है। नियमित व्यायाम या खुद काम करने की क्षमता को नकारने से भी शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता गंवा बैठता है और फिर उसे एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। अच्छा हो कि लोग शारीरिक परिश्रम करें।

– अमृतलाल मारू 'रवि' इंदौर

दांव पर रिश्ता

आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने और भारत में नियुक्त कनाडा के छह राजनयिकों के निष्कासन की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भारत की उदारता को कायरता समझने की भूल ट्रूडो को वैश्विक स्तर पर भरी पड़ने जा रही है। भारत ने कितनी कुर्बानियों से पंजाब के अलगाववादी आंदोलन पर काबू पाया, कनाडा समेत पश्चिम के तमाम देश वाकिफ हैं। विडंबना देखिए कि कनाडा ने एक आतंकी के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की। मगर ट्रूडो को कौन समझाए कि जिस आतंकी के लिए वे रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं, उसके सिर पर भारत सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। अब तक भारत ने धीरज का परिचय दिया है, क्योंकि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो अपने यहां चुनाव के कारण गंदी राजनीति कर रहे हैं।

– हर्षवर्द्धन, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

असमी जनता को अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6ए को उचित ठहरा कर मूल असमी जनता के अधिकारों तथा मानवाधिकार चिन्ताओं में संतुलन स्थापित किया है। एक उल्लेखनीय फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता कानून, 1955 की धारा 6ए को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। एक के मुकाबले चार के बहुमत से भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन प्राविधानों को स्वीकृति दी जो 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच बांग्लादेश से भारत आए थे। यह निर्णय असम में आप्रवास पर लंबी चली बहसों के बाद आया है। धारा 6ए को 1985 में 'असम समझौते' के बाद लागू किया गया था। यह समझौता भारत सरकार तथा असम के आंदोलनरत समूहों के बीच सहमति का परिणाम था जो अवैध आप्रवास की समस्या से निपटना चाहते थे। इस प्रकार 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आए लोग भारतीय कानून के अंतर्गत नागरिक नहीं माने जाएंगे, बल्कि अवैध आप्रवासी होंगे। असम समझौते का लक्ष्य प्रवासियों के मानवीय सरोकारों तथा मूल असमी जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक हितों के बीच संतुलन बनाना था। 25 मार्च, 1971 की कटआफ डेट का संबंध 'आपरेशन सर्चलाइट' शुरू होने से है, जब पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी-पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। इसके कारण भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। बहुमत के फैसले में प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6ए संविधान के अनुच्छेद 6 व 7 में गारंटी किए गए मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के आप्रवासियों को नागरिकता देते हैं।

अदालत ने कहा कि यह विधायन असम में जनसंख्या संरचना के यथार्थ तथ विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों को संबोधित करना चाहता है। इसीलिए राज्य द्वारा दो कटआफ डेट रखना तार्किक व न्यायोचित है। लेकिन धारा 6ए को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम में आप्रवास कानूनों का समुचित क्रियान्वयन न होने पर चिन्ता प्रकट की। वास्तव में सीमा पर कठोरता न बरतने तथा बाड़बंदी अधूरी होने के कारण लगातार आप्रवासी आ रहे हैं जिनसे जनसंख्या संरचना संबंधी चुनौतियां बढ़ती हैं। 'विदेशी ट्राइब्यूनल' जैसी वर्तमान व्यवस्थायें प्रभावी रूप से अवैध आप्रवासियों की पहचान कर उनको वापस भेजने में सक्षम नहीं हो सकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का असम के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। धारा 6ए को वैध ठहराने वाला यह फैसला याचिकाकर्ताओं की चिन्ताओं को भी स्वीकार करता है जिनका तर्क है कि आप्रवासी कानूनों को लागू करने के कारण असम की जनसंख्या संरचना तथा संस्कृति में परिवर्तन आए हैं। यदि सीमा पर घुसपैठ पर नियंत्रण तथा अवैध आप्रवासियों की समय पर पहचान कठोरता से लागू की जाती है तो असम में जनसंख्या संरचना में परिवर्तन की दूरगामी समस्याओं से निपटा जा सकता है। दूसरी ओर धारा 6ए को अवैध घोषित करने से अनेक निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता जो असम में दशकों से रह रहे हैं। इससे वे प्रभावी रूप से 'राज्यहीन' हो जाते और व्यापक मानवीय संकट को जन्म देते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तारीखों के बीच बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आए लोग अपना नागरिकता अधिकार बनाए रखेंगे। इस प्रकार उनको बड़े पैमाने पर विस्थापन तथा अशांति की आशंका से मुक्ति मिलेगी।

बांग्लादेश सरकार के संदिग्ध इरादे

आशंकायें बढ़ने तथा चुनावों का समय अस्पष्ट बने रहने के कारण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दूरगामी लक्ष्य संदिग्ध है। इनको अनदेखा करना कठिन होता जा रहा है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने न केवल पार्टी के उभार का विमर्श ठंडा कर दिया है, बल्कि इसने गठबंधन राजनीति के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता भी उजागर की है। हरियाणा में पराजय के कारण देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 'इंडिया' गठबंधन में सहयोगियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने हालिया हरियाणा चुनाव में गठबंधन सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके कारण दस साल सत्ता में रहने के कारण पैदा 'सत्ता-विरोधी भावनाओं' के बावजूद भाजपा को तीसरी बार विजय प्राप्त कर सरकार बनाने का अवसर दे दिया है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अधिकांश एक्ज़िट पोलों ने कांग्रेस की स्पष्ट विजय का अनुमान लगाया था, पर इसके बावजूद भाजपा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 48 जीतने में सफल हुई। भाजपा की इस भारी विजय का अनुमान संभवत: पार्टी नेताओं को भी नहीं था। यदि हरियाणा में कांग्रेस एक्ज़िट पोल अनुमानों के अनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल होती तो इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में उत्साह पैदा होता तथा देश भर में उसकी छवि में और व्यापक सुधार होता। लेकिन इसके एकदम विपरीत कांग्रेस हाल में अपने आंतरिक टकरावों के कारण पांचवां विधानसभा चुनाव हार गई है। इसके पहले वह पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देख चुकी है।

कांग्रेस की हरियाणा में इस पराजय से अब यह निश्चित नहीं है कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी भविष्य में भाजपा के खिलाफ मुकाबले के लिए एकजुट होंगे। ऐसे में बहस हो रही है कि यदि कांग्रेस का हरियाणा में आम आदमी पार्टी-आप से गठबंधन होता तो क्या वह चुनाव जीतने में सफल होती। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति तथा 'इंडिया' के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, हरियाणा में कांग्रेस की पराजय का प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। हरियाणा चुनाव परिणाम का तत्काल प्रभाव आगामी दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा समझौतों पर पड़ सकता है। इन चुनाव परिणामों के बाद आप ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा ही कर दी है।

तीसरा, यह अनिश्चित है कि क्या कांग्रेस और आप का भविष्य में कोई गठबंधन होगा क्योंकि आप ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अपने लचीलेपन तथा सुलह-समझौते की नीति के कारण 'इंडिया' ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारना था ताकि भाजपा-विरोधी वोटों में विभाजन को रोका जा सके। गठबंधन ने विवादास्पद मुद्दों को पीछे छोड़ कर अपने कामकाज में अच्छा प्रबंधन किया था। 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों ने मोटेतौर से भाजपा को हराने का लक्ष्य सामने रखा था और वे एक सीमा तक सफल भी हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहुमत घटा और वह जदयू व टीडीपी की सहायता से ही सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की पराजय ने गठबंधन के भीतर स्थिति एकदम बदल दी है। इस पराजय के कारण अब 'इंडिया' में गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस पर बढ़त मिल गई है। गठबंधन सहयोगी अब संभवत: ज्यादा कठोर दृष्टिकोण अपनायेंगे जिससे कांग्रेस को झुकने पर मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, अब तक किसी ने यह नहीं कहा है कि 'इंडिया' गठबंधन समाप्त हो गया है।

इसके उलट परिणाम आने के अगले दिन समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने अपने बयान से संकेत दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया समूह बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा।' लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी-आप ने कहा है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जबकि उसने तीन महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

'इंडिया' समूह में अन्य गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह अति-विश्वास से भरी थी तथा उसने सीट-साझा के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या दूनी कर ली थी और वह उत्साह से भरी थी, लेकिन हरियाणा में पराजय के बाद वह कमजोर हुई है और उसे भारी झटका लगा है। अधिकांश एक्ज़िट पोलों ने हरियाणा में कांग्रेस की शानदार विजय की भविष्यवाणी की थी क्योंकि भाजपा दस साल की सत्ता-विरोधी लहर का सामना कर रही थी और जनता का एक हिस्सा उसके कामकाज से निराश था। लेकिन भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से न केवल हरियाणा में लगातार तीसरी बार विजय पाई, बल्कि उसका यह प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा।

किसी पार्टी ने अब तक इस ग्रामीण-प्रभुत्व वाले राज्य में लगातार तीसरी बार विजय पाई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना-उद्धव तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा के बीच सीट-साझे पर बातचीत जारी है। हरियाणा में पराजय के बाद कांग्रेस को सीट-साझा फार्मूले के प्रति ज्यादा विनम्रता दिखानी चाहिए तथा उसे चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित करने की शिवसेना की मांग पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। जहां तक हरियाणा विधानसभा चुनाव का सवाल है, आप को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिली और उसे लगभग केवल 1.78 प्रतिशत वोट ही मिले। लेकिन यदि कांग्रेस ने आप से गठबंधन किया होता तो ये वोट निश्चित रूप से 'इंडिया' को मिलते। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस ने छोटी पार्टियों तथा उनके द्वारा किए जा रहे गठबंधन प्रयासों को अनदेखा किया। तृणमूल कांग्रेस, आप, शिवसेना-उद्धव, नेशनल कान्फ्रेंस, राजद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा अन्य ने कांग्रेस की आलोचना की है कि वह अपनी गलतियों के कारण हरियाणा में पराजित हुई।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' ने अपने संपादकीय में बुधवार को कहा, 'किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा में भाजपा सरकार फिर आ जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अति-आत्मविश्वास तथा स्थानीय कांग्रेस नेताओं का घमंड पार्टी की पराजय का कारण बना।' ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में सीट-साझा के लिए लोकसभा चुनाव का फार्मूला दुहराना जरूरी हो गया है। अब अधिकांश सहयोगियों के साथ सीट-साझे में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहेगा। 'इंडिया' गठबंधन में व्याप्त वर्तमान सोच से कांग्रेस के अपने सहयोगियों के साथ संबंध प्रभावित होंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व पराजय से स्पष्ट है कि अब विपक्ष हालिया विधानसभा चुनावों में पराजय के और झटके झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को मुख्यत: उन 286 सीटों पर ही ध्यान देना चाहिए जहां वह भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ 'स्ट्राइक रेट' 29 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जबकि यह 2019 में केवल 8 प्रतिशत था। इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में कांग्रेस ने केवल 286 सीटों पर भाजपा से मुकाबला किया, जबकि इन सीटों की संख्या 2014 में 370 थी।

कांग्रेस को 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपने साझीदारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण ही विजय मिली थी। वर्तमान समय में गठबंधन को व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। उसे यह अवश्य समझना चाहिए कि कोई साझीदार चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके लिए जरूरी है। कांग्रेस ने अतीत में अनेक 'चिंतन शिविर' आयोजित किए हैं, पंचमढ़ी और शिमला इनके अच्छे उदाहरण है। वर्तमान समय की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित व अभूतपूर्व पराजय के बाद कांग्रेस ऐसा ही एक और चिंतन शिविर आयोजित करे।

पीएम मोदी की एसियान तक पहुंच

भारत की विदेश नीति के हितों के लिए हिंद-प्रशांत की केंद्रीयता के बारे में स्पष्ट संदर्भ दिए गए।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओ पीडीआर की यात्रा साझा हितों और समान लक्ष्यों के बारे में भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश थी। पीएम मोदी ने आसियान सदस्य देशों के साथ संबंधों को उन्नत करने के लिए दस सूत्री कार्य एजेंडा योजना तैयार की, जिसमें प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार, लोगों से लोगों के बीच संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और वैश्विक दक्षिण देशों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह ऐसे समय में हुआ है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए (पिछले 9 वर्षों में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री द्वारा पहली बार की गई यात्रा)। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने उल्लेख किया दस साल पहले, मैंने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में, इस पहल ने भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित किया है, उन्हें नई ऊर्जा, दिशा और गति प्रदान की है। आसियान केंद्रीयता को महत्व देते हुए, हमने 2019 में इंडो-पैसिफिक महासागर पहल शुरू की।

भारत की विदेश नीति के हितों के लिए हिंद-प्रशांत की केंद्रीयता के बारे में स्पष्ट संदर्भ दिए गए। भारत ने वर्तमान सरकार की विदेश नीति प्राथमिकताओं के तहत हिंद-प्रशांत को केंद्र बिंदु के रूप में रखा है। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों में से एक, क्वाड में शामिल हो गया है और आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) के तहत अमेरिका

और एशिया के कई देशों के साथ आर्थिक साझेदारी ढांचे में भी प्रवेश किया है। क्वाड भले ही एक सुरक्षा गठबंधन न हो, लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है। भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चेयरमैन महामहिम श्री सोनेक्से सिफानडोन (लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री भी) के बयान में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने में कामयाब रहा। बयान में कहा गया, हमने दक्षिण चीन सागर में और उसके ऊपर से उड़ान भरने की शांति, सुरक्षा, स्थिरता, सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने और बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की। हमने आपसी विश्वास और भरोसे को बढ़ाने, विवादों को जटिल बनाने या बढ़ाने वाली गतिविधियों के संचालन में आत्म-संयम बरतने और शांति और स्थिरता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचने की आवश्यकता की पुष्टि की और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की बात कही जो स्थिति को और जटिल बना सकती हैं। हमने 1982 के यूएनसीएलओएस सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता की भी पुष्टि की। हमने दावेदारों और अन्य सभी राज्यों द्वारा सभी गतिविधियों के संचालन में आत्म-संयम के महत्व पर जोर दिया, जिसमें दक्षिण चीन सागर में पार्टियों के आचरण पर 2002 की घोषणा (डीओसी) में उल्लिखित गतिविधियां भी शामिल हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती हैं और दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा सकती हैं।

हमने डीओसी के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व को रेखांकित किया और दक्षिण चीन सागर (सीओसी) में एक प्रभावी और ठोस आचार संहिता की वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो 1982 के यूएनसीएलओएस सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। इस बीच, जैसा कि अपेक्षित था, भारत ने एससीओ मेजबान देश पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में भाग नहीं लिया। पाकिस्तान के साथ संबंध लगभग एक दशक से खराब चल रहे हैं, और यह तब और बढ़ गया जब भारत ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया। पाकिस्तान स्थित कुछ आतंकवादी हमलों और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ने सुनिश्चित किया कि संबंध ठंडे रहे।

इस बीच, कोविड के बाद के युग में पाकिस्तान की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। यद्यपि विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा को एक सद्भावनापूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन दीर्घावधि में आर्थिक द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के बीच मानवीय सेतु ही पाकिस्तान के लिए एकमात्र रक्षक होगा।

आप की बात

आप में घबराहट

हरियाणा की हार से आम आदमी पार्टी-आप बहुत घबराई हुई है। एक ओर तो वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना विस्तार करना चाहती है और इसके लिए गठबंधन की राजनीति को तैयार है। लेकिन हरियाणा में हुई करारी हार से घबराकर उसने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव में भाग न लेने का फैसला किया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार तथा कुछ प्रदेशों में विधायक होने के बावजूद इसके वो एक प्रदेश में हार से इतनी विचलित हो गई कि दो प्रमुख प्रदेशों में चुनाव लड़ने से ही इंकार कर रही है। चुनाव न लड़ने का उसने यह बहाना बनाया है कि उसे दिल्ली में चुनाव जीतना है और वह इसके लिए सारी ताकत लगाएगी। हालांकि, सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने से वह प्रसन्न है, पर इससे उसके सभी प्रमुख नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के दाग मिटने वाले नहीं हैं। हरियाणा की जनता ने केजरीवाल को ईमानदारी का सार्टीफिकेट देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। यदि राज्य में एक भी सीट मिल जाती तो केजरीवाल डींग हांकते फिरते। लेकिन अब आप महाराष्ट्र व झारखंड में मैदान में उतर कर ऐसा कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। वैसे भी कांग्रेस से गठबंधन टूटने के कारण उसे महाराष्ट्र और झारखंड में सफलता या बेहतर प्रदर्शन की कोई खास उम्मीद नहीं थी।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

आप्रवासियों का भय

अनेक राजनेताओं का सबसे पहला दुश्मन होता है आप्रवासी। इस मुद्दे को भुनाकर चुनाव जीतने के लिए अनेक पार्टियां आप्रवासियों के लिए दंडात्मक नियम बनाते व उसे लागू करती हैं। ग्रेट ब्रिटेन की पिछली कंजरवेटिव सरकार ने आप्रवासियों से मुक्ति पाने के लिए अफ्रीकी देश रवांडा से समझौता किया था। इसके तहत ब्रिटेन के अवैध आप्रवासियों को रवांडा स्थानांतरित किया जाना था। लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी। अब तक केवल 4 लोगों को ही रवांडा भेजा जा सका। ऐसी ही मुश्किलों का सामना इटली भी कर सकता है। रोम की एक आव्रजन अदालत ने फैसला दिया कि शिविर में भेजे 12 प्रवासियों को वापस लाया जाए क्योंकि उन्हें वापस भेजना असुरक्षित है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील का फैसला किया है। स्पष्ट है कि जहां कुछ राजनेता मूल निवासियों को आप्रवासियों का भय दिखा कर चुनावी सफलता पाते हैं, वहीं आप्रवासियों के मानवाधिकारों और उनके संकट को अनदेखा किया जाता है। रोजी-रोटी, सुरक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में लोग अपने प्रियजनों व मातृभूमि को छोड़ कर पलायन पर मजबूर होते हैं। उनके कष्टों पर सारी दुनिया को विचार करना चाहिए।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

चीन की महत्वाकांक्षा

भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड-ओबीओआर का पूरी दृढ़ता से विरोध किया है। इस प्रकार भारत शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ का ऐसा एकमात्र देश है जिसने इस विवादास्पद परियोजना का समर्थन नहीं किया है। इसका कारण स्पष्ट है। ओबीओआर में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है जो कश्मीर के पाकिस्तान कब्जे वाले हिस्से से होकर गुजरता है। इसलिए भारत शुरू से ही इस योजना का विरोध करता आ रहा है। हालांकि, पाकिस्तान में उस क्षेत्र की जनता भी ओबीओआर का भारी विरोध कर रही है। पाकिस्तान के अनेक भागों में एक प्रकार से मुक्ति आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों का मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है और उनके क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन चीन-पाकिस्तान मिल कर लूट रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चीनी अधिकारियों तथा परियोजना में काम करने वाले इंजीनियरों पर हमले भी किए हैं। लेकिन पैसे-पैसे के लिए मुहताज पाकिस्तान अपने आका चीन को खुश करने के लिए चीनी परियोजना की रक्षा के लिए विशेष सैनिक बल तैयार करने पर भारी खर्च कर रहा है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से भारत के लिए चिन्ताजनक है।

-मनमोहन राजावत, शाजापुर

डीएनए कंप्यूटर

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डीएनए कंप्यूटर बनाने में शुरुआती सफलता प्राप्त की है जो डीएनए के जैविक अणुओं यानी न्यूक्लिक एसिड की श्रृंखला से सब तरह की कंप्यूटिंग कर सकता है। उसके कामों में डेटा स्टोर करने, पढ़ने, मिटाने, ट्रांसफर करने और फिर से लिखने के अलावा इन कार्यों को प्रोग्राम लायक बनाना और दोहराना शामिल है। उल्लेखनीय है कि डीएनए कंप्यूटर सैकड़ों कंप्यूटरों में संग्रहीत डेटा को पेंसिल के आकार वाली संरचना में संरक्षित कर सकता है। हालांकि, अभी इस कंप्यूटर के विकास में बहुत काम बाकी है। मगर यह उम्मीद है कि डीएनए कंप्यूटर से चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार होगा और कई असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। डीएनए कंप्यूटर की सारी जानकारी चार डिग्री संटीग्रेड पर 500 वर्षों तक तथा इससे कम तापमान पर और लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। डीएनए कंप्यूटर के माध्यम से मानव को और अधिक स्वस्थ, मजबूत, दीर्घजीवी और सक्षम बनाया जा सकेगा।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 211

जीएसटी में अगला कदम

कोविड-19 महामारी की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में देरी हुई। अप्रत्यक्ष कर सुधार 2017 में लागू किया गया था और उस समय यह वादा किया गया था कि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। राज्यों को मुआवजा देने के वास्ते फंड जुटाने के लिए जीएसटी की उच्चतम दरों वाले स्तर पर एक मुआवजा उपकर लगाया गया। सामान्य परिस्थितियों में मुआवजा उपकर 2022 में समाप्त हो जाना था। बहरहाल महामारी के दौरान कर संग्रह पर बुरा असर हुआ और यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए उधारी ली जाएगी और उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि इसके लिए जुटाए गए कर्ज तथा उसके ब्याज को चुकता किया जा सके। ऐसे में महामारी के दौरान लिए गए 2.7 लाख करोड़ रुपये की राशि को चुकता करने के लिए उपकर लिया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जनवरी 2026 तक इसे चुकाने का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि भविष्य की दिशा तय की जाए और समय पर जरूरी कानूनी बदलाव पूरे कर लिए जाएं।

मंत्रियों का एक समूह बनाया गया ताकि वह भविष्य की राह सुझा सके। जैसा कि इस समाचार पत्र ने गत सप्ताह लिखा, राज्य सरकारों ने मुआवजा उपकर को जीएसटी दर में समाहित करने का सुझाव रखा है। राजस्व वाले नजरिये से देखा जाए तो उपकर को उच्चतम जीएसटी दर में समाहित करने से राजस्व संग्रह और करदाताओं पर बोझ दोनों बरकरार रहेंगे। फिलहाल उपकर के रूप में संग्रहीत राजस्व का इस्तेमाल कर्ज को चुकाने के लिए किया जा रहा है। विलय के बाद इसे सामान्य जीएसटी संग्रह के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता है। उपकर से हासिल होने वाला संग्रह 2023-24 में 1,44,554 करोड़ रुपये था।

हालांकि हालात इतने भी आसान नहीं रहने वाले हैं और मंत्री परिषद जिसे 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है उसे कई संभावित परिणामों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए उपकर सीमित समय के लिए लगाया गया था और फिर असाधारण परिस्थितियों में उसमें इजाफा किया गया। ऐसे में क्या उसे स्थायी रूप से कुछ चीजों पर लगने वाली उच्च कर दर में मिला देना उचित होगा? इतना ही नहीं विभिन्न वस्तुओं पर उपकर का स्तर भी अलग है। उपकर को आधार दर में शामिल करने से जीएसटी प्रणाली में स्लैब बढ़ सकते हैं। अब यह स्वीकार्य है कि दरों की बहुलता से कारोबार और कर अधिकारियों दोनों के लिए जटिलता उत्पन्न होती है और स्लैब की तादाद कम करने की आवश्यकता है। एक अन्य मंत्री परिषद दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है। गत सप्ताह बैठक में इस मंत्री परिषद ने यह अनुशंसा की थी कि पैकेटबंद पानी, साइकिल, कलाई घड़ी और जूतों जैसी वस्तुओं पर जीएसटी कर दर में बदलाव किया जाए। मंत्री परिषद को मार्जिन में छेड़छाड़ से आगे बढ़कर ढांचागत बदलाव के तरीकों पर विचार करना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण होगा कि मंत्री परिषद समन्वय करें और अपनी अनुशंसाओं को जीएसटी परिषद के निर्णयों के साथ सुसंगत बनाएं।

परिषद का लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्लैब को अधिक से अधिक तीन तक सीमित किया जाए। कुछ जरूरी वस्तुओं के लिए कम कर दर और विलासिता वाली या नुकसानदेह वस्तुओं के लिए अधिक दर होनी चाहिए। अन्य सभी वस्तुओं को बीच की एक दर में शामिल किया जा सकता है जिसमें अपवाद की गुंजाइश सीमित हो। उपकर को भी उच्चतम दर में शामिल किया जाए लेकिन केवल सीमित वस्तुओं पर। कुल मिलाकर जीएसटी ढांचे को राजस्व निरपेक्ष स्तर पर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष 2023-24 में उपकर सहित कुल संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग उतने ही हिस्से के बराबर था जितना जीएसटी के पहले जुटाया जाता था। बिना उपकर के संग्रह में कमी आएगी। ऐसे में जरूरत यह है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार किया जाए और उसे सहज बनाकर राजस्व संग्रह बढ़ाने की दिशा में बढ़ा जाए।

बिनय सिन्हा

विदेशों में बसे सिख उपद्रवियों से परेशान न हो भारत

सिख अलगाववादी उपद्रव कर रहे हैं तो उनके मेजबान देशों को चिंता करने की जरूरत है। अगर उनके गिरोह आपसी लड़ाई में पास-पड़ोस को असुरक्षित बनाते रहें तो क्या भारत के लिए चिंतित होने की बात है?

बड़े और पुराने खतरे दोबारा सिर उठा रहे हैं और पीढ़ियों से दफन प्रेत फिर उठ रहे हैं तो सेना को हटाना या कम करना कैसे सही ठहराया जा सकता है? हम पंजाब और सिखों की बात कर रहे हैं।

आप पूछ सकते हैं कि जंग के हालात आखिर कहां हैं? पंजाब खामोश है और शायद उत्तर भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक शांत है और कानून सम्मत ढंग से काम कर रहा है। कम से कम वहां हिंदी प्रदेशों से तो बेहतर ही हालात हैं। सिखों ने लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनावों में जमकर मतदान किया और ताकतवर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को खारिज कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना जो कांग्रेस या भाजपा से भी अधिक बाहरी है। फिर दिक्कत कहां है? चुनौती कहां है? हम किन गंभीर खतरों की बात कर रहे हैं? क्या हलचल मची है और जंग कहां है?

सत्ता में होने या पूरी तरह नियंत्रण रखने पर बड़ी चुनौती यह होती है कि लोगों को लगने लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। हर सत्ता तंत्र के भीतर एक डॉन कुहाते (मिगुएल दी सर्वांते का उपन्यास नायक जिसे हिंदी में तीसमार खां कहा जाता है) होता है, जो अपने साथी सांचो पांजा के साथ मिलकर भीमकाय और दुष्ट पवनचक्की से निपटने निकल पड़ता है। मगर उपन्यास में यह सब 1605 में होता है और अब 1605 नहीं है। मामला तब ज्यादा पेचीदा हो जाता है, जब पवनचक्की ब्रिटिश कोलंबिया में हो। तब दुष्ट दानवों से लड़ रही सेना को वापस बुलाना पड़ता है क्योंकि जिन लोगों, जमीन और राजनीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे सब यहीं हैं: अमृतसर में, जो दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। वहां कोई जंग या झड़प नहीं हो रही है। वहां की आबादी नाखुश और हताश है, वह भारत छोड़ना चाहती है जो अब लगभग असंभव हो गया है।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

अलगाववादी जो बयान देते हैं, उनकी परेड में जो अपमानजनक झांकियां निकाली जाती हैं या जो नारे, पोस्टर और असॉल्ट राइफल के साथ सेल्फी होती हैं, वे भी भारत की समस्या नहीं हैं। वैसे मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हरदीप सिंह निज्जर बनाना रिपब्लिक वाली भगवा टी-शर्ट पहनकर क्या जताना चाह रहा है? इन सब में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग शामिल हैं। अगर वे परेशानी का सबब हैं तो जहां रहते हैं, उन देशों के लिए हैं क्योंकि वे हथियारबंद हैं और उनकी अंडरवर्ल्ड की अपनी दुनिया है। महत्वपूर्ण बात है कि यह सब अमेरिका में नहीं केवल कनाडा में हो रहा है।

गुरपतवंत सिंह पन्नुन भारत की आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है मगर वह सोच-समझकर बोलता है। बात करते समय वह वकालत की अपनी पढ़ाई का बढ़िया इस्तेमाल करता है। उसके होर्डिंग पर लिखा होता है, 'भारत को खत्म कर दो!' या 'भारत को कुचल डालो।' किंतु नीचे बारीक अक्षरों में लिखा हो, 'गोली से नहीं वोट से।' कनाडा में हालात अधिक बुरे हैं बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों में गड़बड़ कुछ कम है।

यह सब देखकर गुस्सा आ सकता है मगर क्या वे सब वाकई इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि हम अहम राजनियक संबंधों को ताक पर रखकर उनसे उलझें, वह भी तब जब हमारा पड़ोसी ऐसा है? खासकर उत्तरी पड़ोसी ऐसा है? एक समझदार महाशक्ति के पास अपनी दोस्ती और खतरों को आंकने तथा कोई भी कदम उठाने का सही समय भांपने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी समय जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो, सबसे पहले उसी पर प्रतिक्रिया देना निरी मानवीय प्रकृति है। फिर भी राष्ट्रों, समाजों तथा निजी एवं व्यावसायिक जीवन के अनुभव हमें बताते हैं कि गहरी सांस ली जाए और गुस्से को शांत होने दिया जाए तो अगली सुबह हम खुद से ही पूछते हैं: क्या इतनी सी बात के लिए मैं जंग करने जा रहा था? या रिश्ता तोड़ने जा रहा था? नौकरी छोड़ने जा रहा था? किसी को नौकरी से निकालने जा रहा था? ताकतवर लोग और राष्ट्र गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देते और गुस्से में कोई काम नहीं करते। शोरशराबा करने वाले इन अलगाववादियों में से कोई नहीं मानता कि कोई चमत्कार होगा और संप्रभु सिख देश बन जाएगा। इनमें से अधिकतर तो पंजाब में पंचायत चुनाव जीतने या 100 हथियारबंद लोगों को अपने साथ जुटा लेने की ताकत भी नहीं रखते। उन्हें ऐसे लोग भी माना जा सकता है, जो कभी हमारी तरह भारतीय थे मगर अब उनमें से ज्यादातर कनाडाई हो गए हैं और पाकिस्तानियों से उनका बचा-खुचा पैसा खर्च करा रहे हैं। वे उसी पैसे पर जी रहे हैं। भारत और उसका मजबूत खुफिया तंत्र भी पाकिस्तान को इसी तरह जवाब दे सकता है और देता रहा है।

भारत, अमेरिका और यहां तक कि कनाडा भी देखेंगे कि समय के साथ उनके विवाद खत्म हो जाएंगे चाहे उनके तरीके अलग-अलग क्यों न हों। संप्रभु देशों खासकर जिनके बीच बहुत कुछ साझा हो, के रिश्ते अधिक समय तक टूटे नहीं रहते। अमेरिका और भारत पहले ही पन्नुन मामले को अलग रखकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं बदलेगा कि सिख प्रवासियों की बड़ी और प्रभावशाली आबादी दोनों देशों में रहती है। कनाडा में कई सीटों पर चुनाव के लिहाज से उनका बहुत महत्त्व है। यह तथ्य भी नहीं बदलेगा कि दोनों जगह इस कट्टर तबके को आईएसआई से रकम मिलती रहेगी।

इसी पखवाड़े में इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी होगी और उनकी शहादत के साथ ही सिखों के नरसंहार को भी 40 साल पूरे हो जाएंगे। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी 40वीं बरसी है। भिंडरावाले के रहते हुए पंजाब में जो अशांति थी, उससे कहीं ज्यादा खूनखराबा उसने भिंडरावाले के बाद के एक दशक में देखा और तब जाकर वहां शांति कायम हुई। उसके बाद से तीन दशक तक पंजाब में पूरी तरह शांति रही है। मगर अब गुस्सा और हताशा पनप रहे हैं। इसकी मूल वजह पंजाब की कमजोर होती आर्थिक स्थिति है। वहां यह धारणा भी गहराती जा रही है कि राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता में पंजाब का पुराना कद घट गया है। मेरा यह कहना अजीब लग सकता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक सिख ने भारतीय वायु सेना की कमान संभाली है। लेकिन केंद्र की सत्ता अब पूरी तरह भाजपा के हाथ में है, जिसे सिख सबसे कम पसंद करते हैं। पंजाब में भाजपा के पास सिख नेता नहीं है और शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था।

अकाली दल के साथ रिश्ते खत्म करने की राजनीतिक वजह जो भी रही हो, यह कदम देश के हित में नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि पंजाब में चुनौती है सिख और हिंदू विभाजन। इसका सही जवाब था सिखों और हिंदुओं के दलों यानी अकाली और भाजपा में गठबंधन। इस गठजोड़ के टूटते ही सब बिखर गया। अकाली अब वहां लोकप्रिय नहीं हैं और कट्टरपंथी उनके धार्मिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। इसे पंजाब में 'पंथिक' कहा जाता है और पंथिक राजनीति में निर्वात खतरे की बात है। और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात तो न ही करें। पंजाब में अगर कोई कहता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो सिख राष्ट्र की मांग पर सवाल कैसे उठाया जाएगा? वैसे यह केवल कहने की बात है। अमृतपाल सिंह लोकतांत्रिक राजनीति में आ गए हैं और उनको बंदी बनाए जाने पर ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ।

कठिन प्रश्न यह है कि सिख पंथ, उसके बड़े गुरुद्वारों, संसाधनों और संस्थाओं पर किसका नियंत्रण है? यह काम निर्वाचित संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, जिसके लिए केवल धर्मपालक सिख ही मतदान कर सकते हैं। आखिरी बार इसका चुनाव चुनाव 2011 में हुआ था और चुनाव के लिए पंजीकरण की अभी जारी प्रक्रिया में पात्र सिख मतदाताओं की संख्या आधी हो गई है क्योंकि धार्मिक सिख घटते जा रहे हैं।

इससे असुरक्षा और चिंता बढ़ी है। केंद्र की शंका ने हालात और बिगाड़े हैं। 40वीं बरसी पर कुछ नारे और पोस्टर दिख सकते हैं लेकिन कोई बगावत नहीं होने वाली है। क्या आप उन सभी को यूएपीए और रासुका के तहत बंद कर देंगे? अगर नहीं तो समुद्र के पार बैठे कुछ सौ लोगों के साथ जंग क्यों छेड़ी जाए? यही वजह है कि हमें अपने जवान बैरक में वापस बुलाने चाहिए।

टाटा: कारोबार में असहज विचारों को सम्मान

दिवंगत रतन टाटा के साथ हमारा पहला संपर्क सुखद नहीं था। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी और हमने स्वच्छ हवा के अधिकार का अभियान शुरू कर दिया था। डीजल को हवा में घुलने वाले सूक्ष्म कण पीएम 2.5 के उत्सर्जन का जिम्मेदार बताया जा रहा था। 1990 के दशक के मध्य में यह सब कुछ नया था क्योंकि विज्ञान पता लगा रहा था कि ईंधन और वाहन की गुणवत्ता सुधरने से प्रदूषण फैलाने वाले उन सूक्ष्म कणों का प्रसार अप्रत्याशित रूप से कैसे बढ़ेगा, जो हमारे फेफड़ों की गहराई में जमा हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने और मेरे दिवंगत सहयोगी अनिल अग्रवाल ने डीजल के खतरों के बारे में लिखा था। तुरंत ही हमें टाटा मोटर्स की तरफ से मानहानि का नोटिस मिल गया, जिसमें बतौर मुआवजा कुछ रकम भी मांगी गई थी।

यह तब की बात है जब रतन टाटा ने कार बनाने का अपना कारोबार शुरू ही किया था। उनकी कंपनी ईंधन के नए विकल्प डीजल पर दांव लगा रही थी, जिससे उसे पेट्रोल से चलने वाली कार बना रही मारुति सुजूकी और दूसरी कंपनियों पर बढ़त हासिल हो सकती थी। बहरहाल न तो हम पीछे हटने वाले थे और न ही वह। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और मुकदमा लंबा चला। मुकदमा खिंचा तो मुझे महसूस हुआ कि रतन टाटा वास्तव में यह मानकर मुकदमा लड़ रहे थे कि उनका मुकाबला कर रही पेट्रोल कार कंपनियों के कहने पर ही हम यह मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जब साबित हो गया कि हमारा अभियान पीएम 2.5 के बारे में नई वैज्ञानिक खोजों और बतौर वाहन ईंधन डीजल के सेहत पर होने वाले असर के कारण था तब माहौल बदल गया।

ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स डीजल कार की अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजना से पीछे हट गई। ऐसा भी नहीं है कि हमने डीजल वाहनों के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दी। असल में हमने विपरीत विचारों को स्वीकार करने की पुरानी और भली लोकतांत्रिक परंपरा निभाई। दिल्ली में ऑटो एक्सपो के दौरान जब रतन टाटा ने नैनो कार की अपनी दुलारी परियोजना शुरू की तो उन्होंने मेरा नाम लेते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस किफायती कार पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कितनी अद्भुत और विनम्रता भरी बात थी।

जमीनी हकीकत
सुनीता नारायण

मेरा दूसरा अनुभव और भी व्यक्तिगत मगर उतना ही भावुक करने वाला है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब मैं एक भोज में शरीक हुई, जहां धनी और ताकतवर लोगों का जमावड़ा था। वहां रतन टाटा लोगों को समझा रहे थे कि कैसे उनकी वाहन कंपनी देश की आबादी के हरेक तबके के लिए कार बना रही है। उन्हीं दिनों उन्होंने ब्रिटेन का मशहूर जगुआर ब्रांड खरीदा था, जो संपन्न तबके के लिए कार बनाता था और उसी समय उन्होंने पहली बार कार खरीदने जा रहे लोगों के लिए नैनो भी पेश की थी।

मैंने उन्हें बीच में रोककर कहा कि वह कुछ भूल रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में चिंता नजर आई क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे भीतर बैठी एक्टिविस्ट असहज करने वाली बात ही कहेगी। लेकिन मैंने कहा कि वह भूल रहे हैं कि टाटा मोटर्स बसें भी बनाती है और उनमें कारों के मुकाबले हजारों ज्यादा लोग आते-जाते हैं। मैंने यह भी कहा कि उनकी बसें आधुनिक (लो-फ्लोर बसें शुरू ही हुई थीं) हैं और स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) से चलती हैं। सबने इस बात की तारीफ की और फिर दूसरे आम मुद्दों पर बात होने लगी। मुझे भी लगा कि बात खत्म हो गई।

लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिन बाद टाटा मोटर्स के एक शीर्ष अधिकारी मुझसे मिलने आए। मुझे लगा कि वह हमारे डीजल विरोधी अभियान के सिलसिले में आए होंगे। उन्होंने कहा कि वह टाटा के कार कारोबार नहीं बल्कि बस कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने रतन टाटा से क्या कहा था। मैंने भी सवाल किया कि वह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तब उन्होंने मुझे पूरी बात समझाई। असल में भोजन के समय मैंने उनके बॉस से जो कहा था, उसके बाद उनके पास एक फोन आया। फोन पर पूछा गया कि वह कौन सा शानदार काम कर रहे हैं, जिसकी तारीफ सुनीता नारायण ने भी की। मुझे बताया गया कि उसकी वजह से उनके बॉस यानी रतन टाटा को परिवहन में हो रहे बदलाव और लोगों को लाने-ले जाने में आधुनिक बसों की भूमिका में ज्यादा दिलचस्पी हो गई।

आज इतना सब कुछ मैं यह दिखाने के लिए नहीं लिख रही हूं कि है कि ऐसी महान शख्सियत के साथ मेरी बातचीत थी। मैं बताना चाहती हूं कि उनकी महानता का कारण था दूसरों को सुनने की क्षमता और असहज होने पर भी दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की क्षमता। मैं यह सब इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि मैंने उद्योग की दूसरी बड़ी हस्तियों को भी देखा है। मुझे याद आता है कि हमारे काम पर सबसे आक्रामक और आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आई थी। यह प्रतिक्रिया तब आई थी, जब हमने अपने अध्ययन में खुलासा किया था कि उनके उत्पादों में कीटनाशक मिले हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में यह कहते हुए हमें सिरे से खारिज कर दिया कि वे गलत नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे अमेरिका की कंपनियां हैं। यह हद से ज्यादा अहंकार था। हमें दूसरी सबसे खराब प्रतिक्रिया कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों से मिली है। हमें अब भी खाद्य पदार्थ में विषैले तत्वों के खिलाफ अपने काम पर धमकी मिलती रहती है, डराया-धमकाया जाता है और मुकदमे भी होते हैं। कोई यह समझता ही नहीं कि हमारा काम निजी नहीं है बल्कि कारोबार के स्याह पक्ष से जुड़ा है और हम उसमें संतुलन चाहते हैं।

इसलिए जब हम रतन टाटा के निधन पर शोक मान रहे हैं तो हमें उस गुजरे वक्त के लिए भी शोक मनाना चाहिए, जब उनके जैसी कारोबारी हस्ती ने दुनिया पर राज किया, जब व्यक्तिगत जीवन में संयम और सादगी के मूल्यों को तवज्जो दी जाती थी और जब कारोबार का मतलब केवल मुनाफा या निजी फायदा नहीं बल्कि जनहित की रक्षा करना था।

उम्मीद है कि जब हम रतन टाटा को श्रद्धांजलि दें तो अपनी दौलत का बेशर्मी के साथ प्रदर्शन करने की आज के रसूखदार लोगों के स्वभाव की भी अस्वीकार करें। साथ ही हम यह विचार भी वापस लाने की शपथ लें कि असहमति वास्तव में मतभेद नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि यह विचार भी हुआ करता था।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवॉयरनमेंट से जुड़ी हैं)

आपका पक्ष

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता पर प्रश्नचिह्न

लेख 'एक नई शुरुआत' में भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर सार्थक चर्चा की गई है। भारत की ओर से कई बार संबंधों को सकारात्मक आयाम देने की पहल हुई परंतु हर बार इसका प्रतिकार आतंकवादी हमलों, करगिल युद्ध और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर घात लगा कर हमलों से हुआ और हमारी सेना ने दो बार सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, वहां उनकी वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में रहती है। भारत से सीधे युद्ध करने के बजाय पाकिस्तान पिछले चार युद्धों में पराजय को दोहराने के डर से आतंकवादियों को सैन्य और लॉजिस्टिक सहायता देकर भारत के साथ छद्म युद्ध कर रहा है। भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी के लिए खूनी संघर्ष बहुत लंबे समय से हो रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान की ओर से कोई सार्थक वार्ता संभव नहीं है। पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे से कश्मीर वापस लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ किस दायरे में हो सकती है, यह भी प्रश्नचिह्न है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सूत्रधार है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से एससीओ बैठक के दौरान मिले थे

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या बड़ी समस्या

भारत की बढ़ती जनसंख्या देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही है। संसाधनों का अभाव बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे इन संसाधनों की कमी और उन तक पहुंच में असमानता बढ़ सकती है, बढ़ती आबादी के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना भी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने से सामाजिक असंतोष और अपराध बढ़ सकते हैं। वहीं प्रदूषण, वन कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं और बढ़ती आबादी के कारण शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, जिससे शहरीकरण की समस्याएं जैसे कि भीड़भाड़, यातायात जाम और स्लम क्षेत्रों का विकास हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सरकार को इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

राजधानी में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण

देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। ठंड की दस्तक के साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। हर साल प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं लेकिन हालात जस की तस ही रहती है। पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा में जब तक पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती तब तक राजधानी के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड और ओमान की नौसेना का युद्धपोत अल सीब रविवार को भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'नसीम अल-बहर' में शामिल हुए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कितने भी उतार-चढ़ाव आएं, जिंदगी से मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में भी मुश्किलें आईं, पर प्यार बना रहा।

- स्वर कोकिला लता मंगेशकर

खुशी की गाइड

शुक्रिया कहना सेहत के लिए अच्छा है...

हेल्थ हार्वर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका

अपने जीवन के प्रति शुक्रिया के अहसास से भरे होने का दूसरा नाम है- कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। यह एक ऐसी सकारात्मक और रचनात्मक शक्ति है, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हेल्थ हार्वर्ड के शोध में स्वास्थ्य पर कृतज्ञता के सकारात्मक प्रभावों की खोज की गई, जिसमें बेहतर भावनात्मक और सामाजिक वेल-बीइंग, नींद की गुणवत्ता, अवसाद का कम जोखिम और हृदय-स्वास्थ्य के अनुकूल मार्कर शामिल हैं। नए डेटा से पता चलता है कि इससे जीवन की अवधि भी बढ़ सकती है।

• जुलाई 2024 में प्रकाशित इस स्टडी के लिए 49,275 महिलाओं से बातचीत की गई थी। उनकी औसत आयु 79 वर्ष थी। उनकी रैंकिंग इस प्रकार के कथनों पर सहमति के आधार पर बनाई गई थी कि 'मेरे पास जीवन में बहुत कुछ है, जिसके लिए मैं आभारी हूं,' और 'अगर मुझे उन सभी चीजों की फेहरिस्त बनानी पड़े, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूं, तो यह बहुत लंबी सूची होगी' आदि। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं की कृतज्ञता का स्कोर ऊंचा था, वे हृदय रोग समेत मृत्यु के अनेक कारणों से अपनी रक्षा करने में सफल रही थीं।

• शोधकर्ताओं का कहना है कि कृतज्ञता के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि लगभग कोई भी इसे कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास की सकारात्मक चीजों को पहचान सकता है और दूसरों को उसके जीवन में जो अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद दे सकता है। कृतज्ञता लोगों को खुश महसूस कराती है और इस खुशी का कोई खर्च भी नहीं है!

सकारात्मक-संकल्प

निवेश की डायरी बनाएं

आजकल निवेश हो या खर्च, सारा काम एप के जरिए ही होता है। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध कहता है कि निवेश व खर्च का हिसाब-किताब डायरी में हाथ से लिखा जाए, तो उसका फायदा मिलता है। जब कोई चीज लिखना शुरू कर देते हैं, तो निर्णयों में गंभीरता ज्यादा आती है। आप निवेश लक्ष्यों को लेकर एकदम स्पष्ट रह पाते हैं और जोखिम भरे निर्णय लेने से पहले सटीक आकलन कर पाते हैं। इसके लिए अपने सारे निवेश, बीमा पॉलिसी, आपात स्थिति के लिए लिया रिस्क कवरेज की जानकारी लिखकर रखें। साथ ही संबंधित व्यक्ति का फोन नंबर, वेबसाइट, पॉलिसी के ऑनलाइन दस्तावेज की जानकारी भी लिखकर रखें।

टेक्नोलॉजी के रूप में रिकॉर्ड रहता है, लेकिन हाथ से लिखकर रखने के अपने फायदे हैं।

जीवन-सूत्र

स्वामी ज्ञानवत्सल
प्रेरक वक्ता और विचारक

हम भी सुबह उठकर काम शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते-होते प्रभु को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी शक्ति, बल, बुद्धि दी, उस हिसाब से मैंने अपना कर्म पूरी क्षमता से करने का प्रयत्न किया है। अब आपकी जो इच्छा हो, मुझे फल देना।

जो नियंत्रण में नहीं, उसकी चिंता छोड़ें

अगर दुनिया में ऐसी सौ चीजें हैं, जिन पर आपका नियंत्रण है और जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो हजारों ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं और जो आपके लक्ष्यों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन सरकार की पॉलिसी बदल गई तो? आपने सोचा कुछ और हो कुछ गया तो? बात वही है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। अनगिनत चीजें ऐसी हैं, जो आपके बस में नहीं हैं, लेकिन आपने अपने लिए जो सपने संजोकर रखे हैं, वो उन पर गहरा असर डाल सकती हैं। यही कारण है कि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया था कि आप अपनी ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहो, लेकिन उसका फल क्या होगा, यह मुझ पर छोड़ दो।

आपके पूर्व के जो कर्म हैं, आपने जिस भावना से वह कर्म किया है, आपका जो स्वार्थ उसमें था, आप जिस चीज में धक्का मारकर आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना? उसी हिसाब से अंतिम परिणाम भी सामने आता है। अगर इस बात को समझ लोगे तो कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी एंग्जायटी नहीं होगी, कभी नींद की

हम अपने मन के परिणाम पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में तमाम तरह की नकारात्मकताओं का अनुभव करते हैं।

गोली नहीं खानी पड़ेगी।

प्रमुख स्वामी महाराज वल्लभ विद्यानगर में थे, तब एक इंजीनियरिंग कम्पनी के जनरल मैनेजर उनको मिलने के लिए आए। बोले, स्वामी जी, मैंने आपको हर क्रिया में सुबह से शाम तक देखा है, कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, स्ट्रेस नहीं देखा। कभी आपके चेहरे पर चिंता की लकीर तक नहीं दिखाई दी। ये कैसे हो सकता है? हम तो एक कम्पनी चलाते हैं, 90 करोड़ का टर्नओवर है, तब भी अगर शाम को शराब न पीएं तो नींद नहीं आती है। आप हमेशा तरोताजा दिखाई देते हैं। इसकी युक्ति क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भी सुबह उठकर काम शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते-होते प्रभु को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी शक्ति, बल, बुद्धि दी, उस हिसाब से मैंने अपना कर्म अपनी पूरी क्षमता से करने का प्रयत्न किया है। ये रहा वो कार्य। अब आपकी जो इच्छा हो, मुझे फल देना, कल सुबह देखेंगे। स्वामी जी ने कहा, ये सोचकर हम सो जाते हैं। नींद आ जाती है। स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होते।

और हम लोग क्या मानते हैं? मैंने इतना पुरुषार्थ किया है ना, अब इतना परिणाम तो आना ही चाहिए। हम अपने मन के परिणाम पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में तमाम तरह की नकारात्मकताओं का अनुभव करते हैं। हां, लक्ष्य को सामने रखना चाहिए कि आज से इतने-इतने दिन बाद मुझे ऐसा-ऐसा करना है। उसके हिसाब से योजना भी बनानी चाहिए और कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो सोचा था, वो नहीं मिला, कम मिला, तो उस समय ये समझ, ये रवैया काम आता है। जो मिले, उसे स्वीकार करना होता है, और बहुत ही कृतज्ञता के भाव के साथ स्वीकार करना होता है, तब कोई भी मुश्किलें पैदा नहीं होंगी।

प्रेरक प्रसंग

जब मनोविज्ञान से बच्चे का पता चला

ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट सिग्मंड फ्रायड (1856-1939) को साइकोएनालिसिस के विकास का श्रेय दिया जाता है। पढ़िए उनके जीवन का ये चर्चित प्रसंग।

साल 1890 के आसपास की बात है। छुट्टी का दिन था। सिग्मंड फ्रायड अपनी पत्नी मार्था बर्नेस और अपने बच्चे के साथ नजदीक के एक पार्क में घूमने गए। तीनों पार्क में अच्छा समय बिता रहे थे। जब लौटने की बारी आई तो देखा कि बच्चा गायब था। दोनों आपस में इतने खो गए थे कि बच्चे का ख्याल ही नहीं रहा। बच्चे को न पाकर मार्था घबरा गईं, मगर फ्रायड को जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी पत्नी थोड़ी गुस्से में आकर बोलीं, 'आप खामोश क्यों हैं, देखिए न बच्चा कहां गया?'

फ्रायड ने धीरज बंधाते हुआ कहा, 'इतना मत घबराओ, बच्चा मिल जाएगा।'

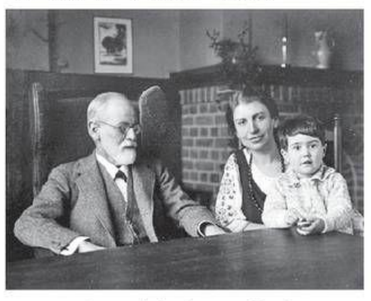

'क्या बिना खोजे ही?' पत्नी की आवाज में अब खीझ थी।

'हां, बिना खोजे ही', उसी धैर्य के साथ फ्रायड ने कहा और पूछा, 'क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था?'

पत्नी थोड़ी देर सोचती रहीं। उसे याद आया कि उसने बच्चे को फव्वारे के पास जाने से मना किया था। यह सुनकर फ्रायड बोले 95 फीसदी तो यही उम्मीद है कि बच्चा फव्वारे के पास होगा। और वाकई बच्चा फव्वारे के पास बैठा पानी की धार को मंत्रमुग्ध भाव से देख रहा था।

सीधा-सा नियम है...

फ्रायड की पत्नी को जिज्ञासा हुई कि आखिर उन्हें यह कैसे पता लगा कि बच्चा फव्वारे के पास ही होगा। मनोविश्लेषक फ्रायड ने बताया कि बच्चे वहीं जाते हैं, जहां उन्हें जाने से मना किया जाता है। वह उस काम को जानबूझकर करेंगे, जिसे करने से उन्हें मना किया जाता है। फ्रायड ने इस रहस्योद्घाटन के बाद जोड़ा कि मनोविज्ञान का यह सीधा-सा नियम बच्चों पर ही नहीं हम बड़ों पर भी समान रूप से लागू होता है।

संघर्ष की कहानी

सरफराज खान, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

वजन के कारण आलोचनाएं झेली, अब टेस्ट क्रिकेट के स्टार हैं

मुंबई में जन्मे सरफराज खान का क्रिकेट करिअर उतार-चढ़ावों से भरा रहा। ज्यादा वजन के कारण मैच से बाहर निकाले गए, क्रिकेट अकेडमी भी छोड़नी पड़ी। पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर भी सोए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रविवार को न्यूजीलैंड के साथ हुए टेस्ट मैच में भारत भले हार गया हो, लेकिन मैच की दूसरी इनिंग में सरफराज के 150 रनों की पारी ने उन्हें हीरो बना दिया। आइए उनके संघर्ष और सफलता की कहानी जानते हैं...

26 साल के सरफराज खान का जीवन संघर्ष की जीती-जागती मिसाल है। बचपन से क्रिकेटर बनने का सपना संजो रहे सरफराज ने महज 12 साल की उम्र में अपनी असाधारण प्रतिभा से खेल जगत को चौंका दिया। लेकिन अपनी फिटनेस और विवादों के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अपने वजन के कारण बॉडी शेमिंग भी झेली। पर पूर्व क्रिकेटर और कोच रहे उनके पिता नौशाद एक मजबूत दीवार की तरह उनके साथ डटे रहे। अभावों और मजबूरियों के बीच सरफराज कई रातें रेलवे स्टेशन पर भी सोए।

संघर्ष : मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कैंप से बाहर कर दिया था...

महज 12 साल की उम्र में हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 439 रनों का रिकॉर्ड बनाकर सरफराज चर्चा में आ गए। उनके प्रदर्शन के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) में एंट्री मिली, लेकिन उम्र के विवाद के कारण उन्हें कैंप से बाहर कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का सोच लिया था। यह संघर्ष आगे भी जारी रहा, जब

तस्वीर 19 अक्टूबर 2024 की है, जब बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में शतक लगाने के बाद सरफराज जश्न मना रहे हैं।

मुंबई रणजी टीम ने फिटनेस में कमी के कारण उन्हें बाहर कर दिया था। 2015 में एमसीए ने अनुशासनहीनता के कारण उनकी मैच फीस भी रोक दी थी। नतीजतन सरफराज ने उत्तर प्रदेश टीम से खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि चार साल बाद वह मुंबई टीम में लौट आए थे।

प्रतिभा : रणजी में सर्वाधिक रन बनाए, इरानी ट्रॉफी भी जिताई

अंडर-19 टीम में चयन के बाद उन्होंने शतक लगाए। 2019-20 रणजी ट्रॉफी में 150 से ज्यादा की औसत से 900 रन बनाकर एकबार फिर उन्होंने खेलप्रेमियों को चौंकाया। 2021-22 में 982 रन बनाकर वे टॉप स्कोरर बने। उनके योगदान की बदौलत शेष भारत 2022 में इरानी ट्रॉफी और मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा।

सफलता: जब गावस्कर ने भी इनके चयन की वकालत की

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सरफराज को टेस्ट टीम में शामिल नहीं करने पर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए थे। आखिरकार 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। इसमें उन्होंने 62 और 68 (नाबाद) रन बनाए। अब न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट में उन्होंने 195 गेंदों में 150 रन की पारी खेली।

दैनिक भास्कर अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

ऑटोमोबाइल

अमेरिका में 11% बढ़ी ईवी की बिक्री, टेस्ला सबसे आगे

जैक इविंग

अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले 2024 की तीसरी तिमाही में बिक्री में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 9 प्रतिशत है। कुछ एनालिस्ट को उम्मीद है कि यह हिस्सेदारी वर्ष के अंत तक दस प्रतिशत हो जाएगी। 2023 में यह 8 प्रतिशत थी। जनरल मोटर्स की इक्विनॉक्स, शेवरले ब्लेजर सहित अन्य किफायती मॉडल के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को सहारा मिला है। तीसरी तिमाही में जीएम के इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वैसे, टेस्ला अब भी जीएम से पांच गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचती है। जीएम की सीइओ मैरी बारा का कहना है, कंपनी अमेरिका में 2035 तक कम्बशन एंजिन (पेट्रोल, डीजल, गैस) कारों की बिक्री बंद करने के लक्ष्य पर कायम है। कंपनी को साल के अंत तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर मुनाफा कमाने की उम्मीद है। © The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

हैलोवीन की खरीदारी पर खर्च पांच गुना बढ़ा

97000 करोड़ रु. से अधिक खर्च करेंगे ग्राहक इस साल अमेरिका में हैलोवीन फेस्टिवल की खरीदारी पर। यह खर्च बीस साल में पांच गुना बढ़ा है।

1850 करोड़ रु. चंदा दिया है, तीन व्यवसायियों ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को। इसमें टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने सबसे ज्यादा 630 करोड़ रुपए दिए हैं।

4 करोड़ 10 लाख किताबें बेची हैं, टिकटॉक की चीनी कंपनी बाइटडांस के बुकटॉक एप ने 2024 में अब तक।

समरनीति • अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक 15 अक्टूबर को इजराइल में हमले का अभ्यास हुआ, बाइडेन को भी इस बात की जानकारी

अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा इजराइल

जूलियन बार्नस, रोनेन बर्गमैन, डेविड सांगेर

मिडिल ईस्ट में इजराइल की योजनाओं से अमेरिका चिंतित है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार इजराइल ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से इजराइल की फौजी हलचल का पता लगा है। अमेरिका के जासूस उपग्रहों की सूचनाओं का विश्लेषण करने वाली नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के दो दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है। ये दस्तावेज शुक्रवार को टेलीग्राम एप पर जारी हुए हैं। ईरान समर्थक अकाउंट्स में इन पर चर्चा हो रही है।

दस्तावेजों में सैटेलाइट फोटो का ब्योरा है। इनसे आने वाले दिनों में ईरान पर इजरायली हमले के संबंध में काफी जानकारी मिलती है। हालांकि, इस माह ईरानी हमले के जवाब में इजराइली कार्रवाई की संभावना पहले से जताई जा रही है। एक दस्तावेज में ईरान पर इजराइली हवाई हमले की तैयारियों का जिक्र है। इनसे लगता है कि ऐसे हमले की रिहर्सल हो रही है। दूसरे दस्तावेज में ईरान द्वारा जवाबी हमले की स्थिति में इजराइल

गाजा की सीमा पर हलचल करता एक इजराइली टैंक।

के अपने हथियारों को शिफ्ट करने का ब्यौरा है।

खुफिया जानकारी के लीक होने की गंभीरता पर अधिकारियों की राय विभाजित है। दस्तावेजों में सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाई गई हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है, यदि कुछ अन्य दस्तावेज सामने नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि नुकसान सीमित होगा। कुछ अधिकारियों का कहना है, अपने सहयोगी युद्धक योजनाओं का खुलासा करना गंभीर समस्या है। अमेरिकी अधिकारी आपसी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि दस्तावेज विश्वसनीय हैं। वैसे, नेशनल जियोस्पेशियल एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ऑफिस ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, जानकारी निचले स्तर से लीक हुई है।

बाइडेन और नेतन्याहू के बीच सहमति बन चुकी है

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से शुक्रवार को जर्मनी में पूछा गया कि क्या उन्हें इजराइली हमले की जानकारी है? क्या वे जानते हैं किन ठिकानों पर हमला होगा? बाइडेन ने हां, हां तो कहा पर ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। इससे संकेत मिलते हैं कि बाइडेन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हमले के लक्ष्यों पर सहमति है। बाइडेन ने इजराइल से परमाणु ठिकानों और तेल संस्थानों पर हमला नहीं करने के लिए कहा है।

हवाई हमले और बचाव अभियान की रिहर्सल

- दस्तावेजों में 15 अक्टूबर को इजराइल की सैनिक एक्सरसाइज को ईरान पर हमले की तैयारियां बताया है। उड़ते विमानों में फ्यूल भरने और बचाव अभियान की रिहर्सल की गई।
- 29 सितंबर को यमन पर हुए हमले के बराबर फोर्स का उपयोग इस अभ्यास में किया गया। ड्रोन्स से ईरान की निगरानी करने की बात है।
- दस्तावेजों में इजराइल द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और अन्य एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल की तैयारियों का जिक्र है।
- इससे पहले अप्रैल 2023 में एक अमेरिकी नेशनल गार्ड्स के निचले स्तर के एक अधिकारी टैक्सिएरा ने बहुत बड़े पैमाने पर खुफिया जानकारियां लीक की थीं।

© The New York Times

ओपिनियन कॉलम • ट्रम्प की नीतियों से अमेरिकी बिजनेस को भारी नुकसान

नीतियों और फैसलों के मामले में अस्थिर हैं डोनाल्ड ट्रम्प

एडिटोरियल बोर्ड, द न्यूयॉर्क टाइम्स

अमेरिका के इतिहास में कारोबारी जगत मानता रहा है कि हर पार्टी का राष्ट्रपति कानून का शासन तो बनाए ही रखेगा। संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं अदालतों की आजादी का सम्मान भी करेगा। अमेरिका के मूल्य हैं कि कोई भी जीते अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्यम आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन, मौजूदा चुनाव में अमेरिका के बिजनेस लीडर निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। इस बार बिजनेस जगत का माहौल अलग है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प की नीतियां अमेरिकी बिजनेस वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह साबित होगी। इस चुनाव में स्थिरता दांव पर लगी है।

ट्रम्प चुनावों की वैधानिकता से इनकार कर चुके हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों की संवैधानिक सीमाओं को तोड़ते हैं। अपने दुश्मनों को सजा देने धमकियां तक देते हैं। वे लोकतंत्र पर हमला करते हुए अमेरिकी संपन्नता की बुनियाद पर भी प्रहार कर रहे हैं। संकुचित नीतियों पर वोटिंग से अमेरिकी बिजनेस के हितों की अनदेखी होगी। कई प्रमुख बिजनेसमैन ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं। उनके समर्थन के कारण समझ पाना लगभग नामुमकिन है।

पिछले कार्यकाल में भी ट्रम्प ने सरकारी नीतियों को बदला था

बिजनेस लीडर्स अक्सर कहते हैं कि वे टैक्स और सरकारी नियम में अनिश्चितता से नफरत करते हैं। ट्रम्प तो अस्थिरता के प्रतीक हैं। उन्होंने चार साल राष्ट्रपति रहते हुए अचानक सरकारी नीतियों को बदला है। ऐसा पक्षपात और सनक के कारण किया गया। कुछ व्यवसायी अनुमान लगा रहे होंगे कि वे ट्रम्प के फैसलों को बदलवा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को निराशा होगी। ट्रम्प ने उन सलाहकारों को हटा दिया है जो उनके किसी फैसले का विरोध कर सकते थे।

दूसरी ओर अमेरिकी बिजनेस लीडर्स कमला हैरिस की नीतियों पर संदेह कर सकते हैं। दरअसल, वे नहीं जानते हैं कि हैरिस कैसे सरकार चलाएंगी। वे उनकी चिंता पर ध्यान देंगी भी या नहीं। यह बिजनेस लीडर्स ट्रम्प को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, ट्रम्प वफादारों को इनाम देने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सप्ताह फिर याद दिलाया है कि यह चुनाव अलग है। रिपब्लिकन प्रत्याशी ने 2024 का चुनाव नतीजा मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। यह धमकी ताजा संकेत है कि ट्रम्प अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो सरकार की ताकत का नए और खतरनाक तरीके से उपयोग करेंगे।

परंपरागत नीतियों की दृष्टि से ट्रम्प अमेरिकी बिजनेस और यहां के बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाएंगे। उनके कई प्रस्ताव बिजनेस के हित में नहीं हैं। उन्होंने आयात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा पहले से ही की है। इससे विदेशी सप्लाई पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। दूसरी ओर महंगाई भी बढ़ सकती है। विदेशियों को बाहर भेजने से कामगारों की कमी हो जाएगी। उनकी प्रस्तावित टैक्स कटौतियों से सरकारी खर्च अरबों रुपए बढ़ जाएगा। ट्रम्प संकट के समय भी नाकाम रहे हैं। कोविड महामारी के बीच उनकी सरकार कोविड महामारी से निपटने में विफल साबित हुई थी। अगर अमेरिकी लोकतंत्र को बचाना है तो कारोबारियों और अन्य अमेरिकियों को खुलकर ट्रम्प का विरोध करना चाहिए।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी • दोनों कंपनियों में असहमति पनप रही

माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की पार्टनरशिप कमजोर पड़ रही

केड मेट्ज, माइक इसाक, एरिन ग्रिफिथ

दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की भागीदारी में दरार नजर आने लगी है। माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक लगा चुकी है। शुरुआत में सीईओ सत्या नडेला और धन लगाना चाहते थे। लेकिन ओपन एआई के बोर्ड द्वारा सीईओ सैम आल्टमैन को पिछले साल नवंबर में थोड़े समय के लिए बाहर करने के बाद स्थिति बदल गई। नडेला और माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ खींच लिए हैं।

कुछ माह तक ओपन एआई ने अधिक धन और अपने एआई सिस्टम्स चलाने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर मांगा। लेकिन, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नहीं किया। किसी समय आल्टमैन ने ओपनएआई-माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप को टेक्नोलॉजी में बेस्ट ब्रोमांस कहा था। इधर, दोनों कंपनियों के रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं। ओपन एआई को इस साल 42 हजार करोड़ रुपए से अधिक घाटा होने की संभावना है। ओपन एआई पर वित्तीय दबाव, उसकी स्थिरता पर चिंता और दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के बीच असहमतियों से पांच साल पुरानी पार्टनरशिप में खिंचाव पैदा हो गया है। यह तनाव नई एआई कंपनियों के लिए चुनौती है। वे पैसे और कंप्यूटिंग ताकत के लिए दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर निर्भर हैं।

पिछले एक साल से ओपन एआई अधिक कंप्यूटिंग पावर हासिल करने के लिए सौदे को नया रूप देने की कोशिश कर रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी चिंतित हैं कि वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के मामले में ओपन एआई पर बहुत अधिक निर्भर है। नडेला ने आपसी बातचीत में कहा था कि नवंबर में आल्टमैन को बाहर किए जाने से वे स्तब्ध रह गए थे। मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई की प्रतिस्पर्धी कंपनी इंफ्लेक्शन का अधिकतर स्टाफ 5400 करोड़ रुपए खर्च कर हासिल कर लिया था। इंफ्लेक्शन के पूर्व सीईओ मुस्तफा सुलेमान भी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए हैं। आल्टमैन सहित ओपन एआई के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सुलेमान का माइक्रोसॉफ्ट में काम करना पसंद नहीं है।

© The New York Times

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 21 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

बेहतर बैलेंस

टर्म इंश्योरेंस, वरिष्ठ नागरिक और पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर रेट कम करने के साथ बीस लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी घटाने के सुझाव दिए गए हैं। दिल्ली में जीएसटी के मंत्री समूह की बिहार के उपमुख्यमंत्री व वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री ने इस पर सहमति जताई। इसमें जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा को लेकर चर्चा हुई। टैक्टर को शून्य टैक्स पर लाने और अन्य कृषि उपकरणों पर टैक्स हटाने की भी अनुसंशा की गई। महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। दस हजार से कम कीमत वाली साइकिल पर

जीएसटी बारह से घटा कर पांच फीसद करने का सुझाव आया। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी के तहत रोजमर्रा की जरूरी चीजों को कर से छूट दी जा सकती है या सबसे कम स्लैब में रखा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नुकसानदेह वस्तुओं व लग्जरी आइटम को सबसे ऊंचे स्लैब में किया जा सकता है। जीएसटी करों की संरचना पांच स्लैबों में यानी आवश्यक वस्तुओं के लिए 0%, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए 5%, मानक वस्तुओं के लिए 12%, अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के लिए 18% और विलासिता व नुकसानदेह वस्तुओं पर 28% की दरें निश्चित की गई हैं। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र व राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमीयर पर जीएसटी लगाकर 8,262.94 करोड़ का राजस्व एकत्र किया था। स्वाथ्य पुनर्बीमा प्रीमियर से 1,484 करोड़ से अधिक का कर वसूला था। आम आदमी तेजी से स्वास्थ्य बीमा कराने के प्रति जागरूक होता जा रहा है। उसे बीमा के प्रति आकर्षित करने के लिए यह कदम सकारात्मक साबित हो सकता है। पूरे देश में समान व्यापक व संतुलित कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए नामित किया है जिसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। सितम्बर में ही सरकार ने जीएसटी से 1.73 करोड़ रुपये का संग्रह किया है, जो अगस्त में 1.75 करोड़ था। प्रतीत होता है, इसी के मद्देनजर ये सुझाव लिए गए जो जनता को सुकून देने वाले साबित हो सकते हैं। जिन चीजों पर कर बढ़ाने की बात हुई, उनके खरीदारों की जेब पर बढ़ी हुई कीमतों का अधिक असर नहीं होता। दोनों में बैलेंस रखना ही इन सुझावों की नेक-नीयति कही जा सकती है।

पूछताछ में समझदारी जरूरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परिपत्र जारी करके अपने अधिकारियों खासकर जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय पर बुलाए गए लोगों से 'बेवक्त' पूछताछ न करें और उन्हें कार्यालय में घंटों इंतजार न कराया जाए। परिपत्र बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्देश के आलोक में जारी किया गया है, जो अदालत ने 64 वर्षीय एक याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत में बताया था कि ईडी ने उसे तलब करके रात भर हिरासत में रख कर पूछताछ की। उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए

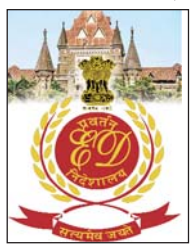

कहा कि एजेंसी के इस कृत्य से उस व्यक्ति की नींद बाधित हुई जो उसका बुनियादी मानवाधिकार है। ईडी का यह कृत्य अस्वीकार्य है, और उसे अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने के बाद किसी को बयान दर्ज करने बुलाया जाए तो वक्त-बेवक्त का ध्यान रखा जाए। हाल के वर्षों में एजेंसियों की पूछताछ को लेकर ऐसे संकेत गए हैं कि पूछताछ के नाम पर आरोपी का उत्पीड़न किया जाता है। विपक्ष इस बात को काफी जोर-शोर से उठाता भी रहा है कि जांच एजेंसियों को उत्पीड़न का जरिया बना दिया गया है जबकि एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं। किसी को परेशान करने जैसे आरोप अतिरेकी प्रतीत होते हैं, लेकिन ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी एक विश्वसनीयता और रुतबा है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालिया वर्षों में विपक्ष ने खासा मुखर होकर आरोप लगाए हैं कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करके जांच एजेंसियों के जरिए उत्पीड़न कराया जा रहा है। मजे की बात यह कि विपक्ष की किसी पार्टी से जुड़ा कोई आरोपी जमानत पर बाहर आता है, तो समझाया जाने लगता है कि जेल से छोड़ा जाना ही बेगुनाही का सबूत है जबकि ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि जमानत पर बाहर आने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि व्यक्ति को आरोप-मुक्त कर दिया गया है। जब इस प्रकार से विमर्श चलाए जाने का माहौल बन गया हो तो एजेंसियों के लिए जरूरी हो जाता है कि अपना आचरण विवेकपूर्ण बनाए रखें। ऐसा न लगे कि पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति का उत्पीड़न किया जा रहा है जबकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं होता।

परिधि/ राजीव मंडल

'दुर्भाग्य' से परे सोचना होगा

अंधविश्वास से जुड़ी दो तस्वीरों को हमें देखना-समझना चाहिए। पहली तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की है। यहां के सियासी गलियारे में यह घनघोर तरीके से माना जाता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है, उसकी सत्ता चली जाती है। उदाहरण के लिए 1995 में बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस औद्योगिक शहर आए और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। इसी तरह सितम्बर 1999 में कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री यहां का दौरा किया, मगर सत्ता उनकी नहीं रही। हालांकि इस अंधविश्वास को गुरुर के साथ तोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अंधविश्वास के बारे में बात करते हुए सीएम योगी ने कहा था, 'मैं अब नोएडा आता रहूंगा। मैं ऐसे टोटकों में भरोसा नहीं करता। लोग हमें वोट देते रहेंगे ताकि हम नोएडा आते रहें।' अच्छी बात है कि योगी दूसरी बार भी सत्ता में लौटे हैं।

अब आते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। यह बिहार का दृश्य है। यहां उप मुख्यमंत्री को आवंटित होने वाला सरकारी आवास भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया है। कहते हैं कि यहां रहने वाला लीडर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। तेजस्वी यादव इसका उदाहरण हैं। इस टोटके को फिलहाल कोई चुनौती नहीं देता दिखता है। तेजस्वी के बाद आए भाजपा नेता सम्राट चौधरी भी अंधविश्वास के शिकार हैं। बस उन्होंने चालाकी ये की कि वास्तुशास्त्र के दोष होने की आड़ में उन्होंने इस आवास के दरवाजे को अस्थायी तौर पर बंद करवा दिया। दरअसल, यहां दो नेताओं की सोच मायने रखती है। दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर दोनों की सोच में भारी अंतर दिखता है। एक खम ठोंककर कहता है कि मुझे टोटके की परवाह नहीं। वहीं दूसरे नेता अंधविश्वास को मानते हैं, भले इसे स्वीकारते नहीं हैं। वो इसे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और यह दलील देते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सवोल यही कि क्या विकास की बात करने वाले या विकास की दुहाई देने वाले नेताओं को ऐसा सोचना चाहिए? अगर टोटके वाली बात वाकई सच होती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते। दरअसल, शिक्षा और जागरूकता के अभाव में ही लोग अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। इस दकियानूसी सोच को दरकिनार करने की जरूरत है। क्योंकि 'इंसान बिना मुहूर्त के जन्मता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है। फिर भी हर कार्य के लिए मुहूर्त पूरी जिंदगी तलाश्ता है।

क्या सही से खर्च होते हैं पैसे

विकास कार्य

विनीत नारायण

बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपया प्रांतीय सरकारों को देती आई है। जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े प्रांत सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं पर इस विषय के जानकारों को कागजी आंकड़ों से गुमराह नहीं किया जा सकता। आज हम उपग्रह कैमरे से हर राज्य की जमीन का चित्र देख कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहां-जहां सूखी जमीन को हरी करने के दावे किए गए, वो सब कितने सच्चे हैं।

दरअसल, यह कोई नई बात नहीं है। विकास योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपया इसी तरह वर्षों से प्रांतीय सरकारों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन अब पुराना पड़ गया कि केंद्र के भेजे एक रुपये में से केवल 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सूचना का अधिकार कानून भी जनता को यह नहीं बता पाएगा कि उसके इर्द-गिर्द की एक गज जमीन पर पिछले 70 वर्षों में कितने करोड़ रुपये का विकास किया जा चुका है। सड़क निर्माण हो या सीवर, वृक्षारोपण हो या कुंडों की खुदाई, नलकूपों की योजना हो या बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा का अभियान की अरबों-खरबों रुपया कागजों पर खर्च हो चुका है। पर देश के हालात कछुए की गति से भी नहीं सुधर रहे। जनता दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है और नौकरशाही, नेता और माफिया हजारों गुना तरक्की कर चुके हैं। जो भी इस क्लब का सदस्य बनता है, कुछ अपवाद को छोड़कर, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल और अदालतें उसका बाल भी बाकां नहीं कर पाते। जिले में योजना बनाने वाले सरकारीकर्मी योजना इस दृष्टि से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और कमीशन तगड़ा मिल जाए। इन्हें हर दल के स्थानीय विधायकों और सांसदों का संरक्षण मिलता है। इसलिए ये नेता आए दिन बड़ी-बड़ी योजनाओं की अखबारों में घोषणा करते रहते हैं। अगर इनकी घोषित योजनाओं की लागत और मौके पर हुए काम की जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। यह काम मीडिया को करना चाहिए था। पहले करता भी था। पर अब नेता पर कॉलम सेंटीमीटर की दर पर छिपा भुगतान करके बड़े-बड़े दावों वाले अपने बयान स्थानीय अखबारों में प्रमुखता से छपवाते रहते हैं। जो लोग उसी इलाके में ठोस काम करते हैं, उनकी खबर खबर नहीं होती पर फर्जीवाड़े के बयान लगातार धमाकेदार छपते हैं। इन भ्रष्ट

अफसरों और निर्माण कंपनियों का भांडा तब फूटता है जब लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद अरबों रुपये की लागत से बने राजमार्ग या एक्सप्रेस-वे गुणवत्ता की कमी के चलते या तो धंस जाते हैं, या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी धांधली सड़क मार्गों पर ही होती है। ऐसा भी देखने को मिला है जब रेल की पटरियां भी धंस गईं और रेल दुर्घटना हुई।

उधर जिले से लेकर प्रांत तक और प्रांत से लेकर केंद्र तक प्रोफेशनल कंसलटेंट का एक बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है। यह कंसलटेंट सरकार से अपनी औकात से दस गुनी फीस वसूलते हैं, और उसमें से 90 फीसद तक काम देने वाले अफसरों और नेताओं को पीछे से कमीशन में लौटा देते हैं। बिना क्षेत्र का सर्वेक्षण किए, बिना स्थानीय अपेक्षाओं को जाने, बिना प्रोजेक्ट की सफलता का मूल्यांकन किए केवल खानापूर्ति के लिए डीपीआर (विस्तृत कार्ययोजना) बना देते हैं। फिर चाहे जेएनआरयूएम हो या मनरेगा, पर्यटन विभाग की डीपीआर हो या ग्रामीण विकास की, सबमें फर्जीवाड़े का प्रतिशत काफी ऊंचा रहता है। यही वजह है कि योजनाएं खूब बनती हैं, पैसा भी खूब आता है, पर हालात नहीं सुधरते। आज के सूचना क्रांति के दौर में ऐसी चोरी पकड़ना बायें हाथ का खेल है। उपग्रह सर्वेक्षणों से हर परियोजना के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखी जा सकती है और काफी हद तक चोरी पकड़ी जा सकती है। पर चोरी पकड़ने का काम नौकरशाही का कोई सदस्य करेगा तो अनेक कारणों से सच्चाई छिपा देगा। निगरानी का यही काम देश भर में अगर प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों या व्यक्तियों से करवाया जाए तो चोरी रोकने में पूरी नहीं तो काफी सफलता मिलेगी। ग्रामीण विकास के मंत्री ही नहीं, बल्कि हर मंत्री को तकनीकी क्रांति की मदद लेनी चाहिए। योजना बनाने में आपाधापी को रोकने के लिए सरल तरीका है कि जिलाधिकारी अपनी योजनाएं वेबसाइट पर डाल दें और उन पर जिले की जनता से 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव दर्ज करने को कहें। जनता के सही सुझावों पर अमल किया जाए। केवल सार्थक, उपयोगी और ठोस योजनाएं ही केंद्र सरकार और राज्य को भेजी जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन की साप्ताहिक प्रगति के चित्र भी वेबसाइट पर डाले जाएं जिससे उसकी कमियां जागरूक नागरिक उजागर कर सकें। इससे जनता के बीच इन योजनाओं पर हर स्तर पर नजर रखने में मदद मिलेगी और अपना लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर बाबा रामदेव या अन्ना हजारे जैसे लोगों को सरकारों के विरुद्ध जनता को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आज हर सरकार की विश्वसनीयता, चाहे वो केंद्र की हो या प्रांतों की, जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है और अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़ जाएगी। देश और प्रांत की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देश भर में जिस भी अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठन ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो, उसकी सूचना जनता के बीच, सरकारी पहल पर, बार-बार, प्रसारित की जाए। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्विक शक्तियां बढ़ेंगी और देश का सही विकास होगा। अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लक्ष्यपूर्ति के साथ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन घोषणाओं के चलते किए गए ये दावे गुणवत्ता के पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं? चूंकि ऐसी योजनाओं में भ्रष्टाचार तों अपने पांव पसारता ही है? ऐसे में जनहित का दावा करने वाले नेता क्या वास्तव में जनहित करे पाएंगे?

(लेख में विचार निजी हैं)

> पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन पुराना पड़ गया है कि केंद्र के भेजे एक रुपये में से केवल 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सूचना का अधिकार कानून भी जनता को नहीं बता पाएगा कि उसके इर्द-गिर्द की एक गज जमीन पर 70 वर्षों में कितने करोड़ रुपये का विकास किया जा चुका है। जिले में योजना बनाने वाले सरकारीकर्मी योजना इस दृष्टि से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और कमीशन भी तगड़ा मिल जाए

■ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इंडस्ट्रीज की बाबत किए गए एक सर्वे से पता चला है कि देश में सबसे अधिक कारखाने तमिलनाडु (देश में कुल कारखानों का 15.66 प्रतिशत) में हैं। इसके बाद गुजरात (12.25) और महाराष्ट्र (10.44), उत्तर प्रदेश (7.54) और आंध्र प्रदेश (6.51 प्रतिशत) क्रमवार हैं

■ स्टैटिस्टक्स एंड प्रोग्राम इम्लिमेंटेशन मिनिस्ट्री के वार्षिक सर्वे ऑफ इंडस्ट्री (एएसआई)-2022-23 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक करोड़ 85 लाख कर्मचारी कार्यरत थे

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

टीवी न्यूज

चैनल्स की इज्जत लगातार कम हुई है। ये कई बार बहुत परेशान करता है। न्यूज चैनल में काम करते हुए मैं एक बात ईमानदारी से मानता हूं कि चैनल को एंकर ड्राइव करने लगे हैं। जिस दिन चैनल एंकर ड्रिवेन होने के बजाय खबर ड्रिवेन हो जाएंगे, चैनल्स के सुनहरे दिन वापस आ जाएंगे।

सुकेश रंजन, पत्रकार
@RanjanSukesh

विमर्श डॉ. सी.पी. राय

मुट्ठी भर ने ही बदला है इतिहास

सैकड़ों साल पहले ही भारत में लिख दिया गया था 'कोउ नृप होय हमें का हानि'। इससे भारत की मिट्टी का मूल चरित्र सिद्ध होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने मुगल राज स्थापित होने के बाद यह लिखा था, राम के युग में ही संपूर्ण जनता किसी गलत के खिलाफ खड़ी हो गई हो ऐसा तो नहीं दिखा। चाहे राम को राजा बनने से रोकना हो या सीता की अग्नि परीक्षा। विस्तार में जाना विवाद पैदा कर सकता है।

कृष्ण युग में कंस हत्याएं करता जा रहा था पर कहां कोई आवाज उठी कि यह गलत है। अशोक के काल में भी कहां जनता ने कुछ भी कहा। जनता हमेशा ताकत और सत्ता की अनुगामिनी ही बनी रही वरना सैकड़ों की तादाद में आते थे विदेशी लुटेरे और लूट कर चले जाते थे भारत को। कोई आता तो खेती करता किसान हल-बैल लेकर किनारे खड़े होकर तमाशा देखता और बाकी लोग भी। लड़ता सिर्फ वो था जिसे लड़ने के पैसे मिलते थे और ज्यादातर वो भी सेनापति के घायल होने या मर जाने पर भाग खड़े होते या विजेता से मिल कर उनके लिए लड़ने लगते।

भारत पर आक्रमण करने वाला या राज करने वाला कोई भी बड़ी फौज लेकर नहीं आया था। सबकी लड़ाई और राज भारतीय लोगों के दम पर ही चले। भारत के नागरिक पर जुल्म या हत्या सब यहीं के लोगों ने किया या तो डर कर या बिक कर और विदेशियों को बुलाकर लाने वाले भी भारतीय थे, रास्ता बताने वाले या कमजोरी बताने वाले भी भारतीय थे। जब सोमनाथ को लूटा जा रहा था तो वहां के सारे पंडे और दर्शनार्थी बैठ कर पूजा करने लगे कि अभी भगवान का प्रकोप होगा और सब लुटेरे भस्म हो जाएंगे। पर वो करने की बजाय उन्होंने अपने थाली-लोटे से भी आक्रमण कर दिया होता तो सोमनाथ नहीं लुटा होता, भगवान की मूर्ति और मंदिर की शक्ति का भ्रम भी बना रहता और लुटेरे टुकड़ों में मुर्दा पड़े होते और उससे भी बड़ा काम यह हुआ होता कि आइंदा कोई भी भारत पर आक्रमण करने से पहले सौ बार सोचता कि भारत का या उसके किसी भी हिस्से का हर आदमी अपने राज या जमीन के लिए लड़ने को खड़ा हो जाता है।

आगे भी पूरा देश तो कभी खड़ा नहीं हुआ, बल्कि थोड़े से

लोग खड़े हुए किसी भी लड़ाई में वो आंदोलन चाहे आजादी का रहा हो और चाहे आपातकाल से पहले का। जिन लोगों ने भी हिंसा का रास्ता अपनाया उनके साथ कम लोग खड़े हुए । गांधी जी इस मिट्टी की तासीर को अच्छी तरह समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और इस रास्ते से वो लाखों या करोड़ों को जोड़ने में कामयाब हुए पर वो भी पूरे देश को नहीं जोड़ पाए। अंग्रेजों के समय भी पूरी जनता तो इसी कोऊ नृप वाले भाव की थी तो बहुत से लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, बहुत से प्रशंसक थे तो हाथों में हथियार लेकर जलियांवाला बाग से होकर पूरे देश में गोली लाठी चलाने वाले, आजाद को गोली मारने वाले, भगत सिंह को फांसी लगाने वाले और सुभाष की सेना पर गोली बरसाने वाले सब तो भारतीय ही थे। केवल आदेश देने वाला अंग्रेज होता था और मुखबिरी कर आजादी के लिए लड़ने वालों की पकड़वाने वाले भी भारतीय ही थे। सभी के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में मुकदमा लड़ने वाले भी भारतीय थे और गवाही देने वाले भी भारतीय ही थे।

आज भी वही हालत है जो भारत की तासीर है। आज भी सोमनाथ की तरह देश का बड़ा हिस्सा मंदिर में अपना सुख और भविष्य देख रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जरा किसी धार्मिक स्थल को कुछ हो जाए, किसी के चित्र या प्रतिमा से कुछ हो जाए या दो जानवरों में से किसी का कुछ हो जाए तो निकलते हैं पर फिर भी मुट्ठी भर और बच-बच कर कि कोई खतरा तो नहीं और नहीं है तथा सामने वाला कमजोर या कम है तो कायरता पूरी ताकत से क्रूरता दिखाती है और चीख की आवाज भी बुलंद होती है।

आज फिर भारत आजादी बनाम गुलामी, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, संविधान बनाम प्रधान की इच्छा, कानून बनाम सता की लाठी के बीच झूल रहा है। अधिकांश कोऊ नृप होय वाले हैं, तो बहुत से अज्ञात कारणों से प्रशंसक हैं तो बहुत से गली-गली में मुखिबर और बहुत से लाठी बंदूक और कानून की किताब के साथ इनके साथ खड़े हैं, तो बहुत से चाहे कलम से या कला से, जुबान से या आंखों की भाषा से लडाई भी लड़ रहे हैं सच की, ईमान की, लोकतंत्र की संविधान की और अंत में यही जीत जाएंगे सारे जुल्म के बावजूद क्योंकि हमेशा ही ये मुट्ठी भर लोग ही जीते हैं। इतिहास तो यही बताता है। बस, देखना इतना है कि वो एक कौन होगा इस युद्ध का नायक और क्या कोई संपूर्ण भारत को कभी निकाल सकेगा चाहे जिसके खिलाफ चाहे जब और चाहे जो भी गलत हो? क्या कोई बदल पाएगा ये आवाज 'कोऊ नृप होंय हमे का हानी' से 'को नृप होय ये हम ही जानी' में।

महानता श्रीराम शर्मा आचार्य

मानवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो तो यह मानकर नहीं चला जा

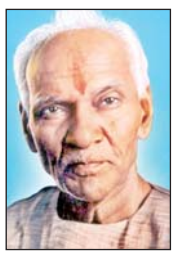

सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिधि है। उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवन यापन को भी सब कुछ न मान कर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी जो इस ब्रह्मांड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेने वालों पर अपनी उच्चस्तरीय अनुकंपा बरसाती है। मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्त्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिसे थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है। इस अध्यात्म विकास के तत्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वार मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत खुलता है। इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है। प्रकृति का अनुशासन मानने के लिए भी बाधित रहता है। प्रकृति पर परमात्मा का स्वामित्व है। मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता आप है। प्रकृति की कठपुतली मात्र नहीं है। अन्य प्राणियों की तरह मात्र निर्वाह ही उसकी एकमात्र आवश्यकता नहीं है वरन व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सज्जा को अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी विशिष्ट उद्देश्य है। जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुतः मनुष्य नर-पशु ही रहता है और इन्द्रिय लिप्साओं तथा मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्त्व समझ पाता है और न उसे चेतना की पृथकता, विशिष्टता संबंधी कुछ ज्ञान होता है। विकास की दृष्टि से पेड़ की ऊंचाई एक सीमा तक बढ़ती जाती है। यह सीमा पूरी होने पर उसका फैलाव एवं मोटाई की अभिवृद्धि होती है तथा फल-फूल लगने लगते हैं। योनियों की दृष्टि से हाथी, सिंह आदि का विस्तार तथा प्रभाव बढ़ा-चढ़ा है पर शारीरिक संरचना और मानसिक स्तर की दृष्टि से मनुष्य ही मूर्धन्य है। इसीलिए उसे सृष्टि का शिरोमणि कहा जाता है। सुख साधन उसके पास असीम मात्रा में हैं। अस्त्र-शस्त्रों सहित रण कौशल में उसकी प्रवीणता है। समाज गठन और शासन तंत्र का निर्माण उसी का अनुपम कौशल है। पदार्थ विज्ञान में उसने असाधारण उन्नति की है।

रीडर्स मेल

शरीफ का पॉजिटिव संकेत

पाकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ओर्गनाइजेशन (एससीओ) की शिखर बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस कुशल डिप्लोमेसी से सकारात्मक माहौल को जन्म दिया है, वह पाकिस्तान के साथ मधुर संबंधों का सबब भी बन सकता है। यद्यपि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए पहले भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। पीएम नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने का जो आह्वान किया है वह पॉजिटिव संकेत है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे दोस्ती की तरफ बढ़ा कदम माना गया। यह भी सकारात्मक संदेश है जबकि एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिरकत करनी चाहिए थी। बावजूद इसके पीएम नवाज शरीफ ने इसे तूल न देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को पॉजिटिव डवलपमेंट के रूप में स्वीकारा। बेशक, यह पहलकदमी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है बशर्ते आतंकवाद पर पीएम नवाज शरीफ शिकंजा कसने में कामयाब रहें। उम्मीद करें पाकिस्तान का निजाम इस मोर्चे पर खरा उतरेगा और लोगों में भरोसा पैदा कर पाएगा।

माम चंद सागर, ई मेल से

बड़ी बहस का मुद्दा बने शराबबंदी

सुशासन बाबू के बिहार राज्य में छपरा, सीवान, गोपालगंज में शराब पीने से अब तक 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 40 लोग अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजा की घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनका परिवार संभल पाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल, देश में शराबबंदी बड़ी बहस का मुद्दा होना चाहिए। बिहार राज्य में शराब की बिकी पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके अवैध शराब की बिक्री रोकने में सरकार नाकाम रही है। इसकी रोकथाम के लिए कारगर और ठोस उपाय करने होंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस दुखद घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने सरकार को घेरा है और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया है लेकिन जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष, दोनों की है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संवाद का माहौल तो बने

पाकिस्तान के साथ बातचीत की हर बार जमीन तैयार की जाती है, लेकिन सार्थक बातचीत नहीं हो पाती। आखिर हो भी कैसे/ दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अडिग हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान नेकदिली से हाथ बढ़ाए, भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो कश्मीर का मुद्दा और अब साथ ही धारा 370 का मुद्दा अपने जीते जी छोड़ नहीं सकता। उनकी भी मजबूरी है। अगर सत्ता में रहना होगा तो कश्मीर कश्मीर कहना होगा। वरना गद्दी छोड़नी होगी। पाकिस्तान की जनता तो जानती है कि भारत से संबंध सुधारने में ही उसकी भलाई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री अलग थी, लेकिन वो केमिस्ट्री उनके छोटे भाई के साथ नहीं बन पाई। भारत तो संबंध सुधारना चाहता है तभी तो विदेश मंत्री को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भेजा।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-34, अंक 67 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

THE HINDU

सहभागी

भारत को अंतरराष्ट्रीय हत्याओं पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिकी

न्याय विभाग द्वारा एक भारतीय खुफिया और

टी अर्धसैनिक अधिकारी के खिलाफ अमेरिकी-खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में दूसरा अभियोग, इस मामले में एक और गंभीर मोड़ का संकेत देता है जिसने भारत-अमेरिका संबंधों पर लंबे समय तक छाया डाली है। विकास यादव के खिलाफ अभियोग को गिरफ्तारी वारंट के साथ सार्वजनिक रूप से जारी किया गया और एफबीआई के "मोस्ट वांटेड" डेटाबेस में उनकी लिस्टिंग की गई - पहली बार जब कोई भारतीय ओ-

इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मामले की जांच कर रहे एक उच्च स्तरीय भारतीय सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के सहयोग पर "संतुष्टि" व्यक्त की। अब चिंता का कारण है: जेल में बंद व्यवसायी निखिल गुप्ता के खिलाफ अभियोग को पीछे छोड़ते हुए दूसरा अभियोग, 2023 में कनाडाई खालिस्तान कार्यकर्ता हरदीप निज्जर की हत्या के कनाडाई मामले से जुड़ा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं लगता कि अभियोग कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने के समय पर लगाया गया है, जिससे कूटनीतिक तूफान खड़ा हो गया है और "फाइव आइज़" द्वारा भारत से कनाडा के साथ जांच में सहयोग करने का आग्रह करने वाले बयान भी सामने आए हैं। इन बयानों में दोहरे मापदंड की बू आती है, यह देखते हुए कि इन देशों का अंतरराष्ट्रीय हत्याओं का रिकॉर्ड रहा है, भारत को कानून को बनाए रखने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन यह निश्चित रूप से इस बारे में सवाल उठाता है कि क्या ये सहयोगी भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार के रूप में विश्वसनीय हैं।

नई दिल्ली को खुद को गुमराह नहीं करना चाहिए और यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अमेरिका और कनाडा में मामलों को उनकी जांच एजेंसियों द्वारा जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा कनाडा के आरोपों को नकारने और अमेरिकी आरोपों को सहानुभूतिपूर्वक सुनने के बीच का अंतर अमेरिका में मुकदमे की प्रगति के साथ अस्थिर साबित हो सकता है। यह स्पष्ट करना भारत के हित में है कि क्या वह मानता है कि श्री यादव एक "दुष्ट" एजेंट थे या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे, जब उन्होंने कथित तौर पर प्रवासी सदस्यों के खिलाफ महीने में "2-3" अनुबंध हत्याओं का वादा किया था। जबकि विदेश मंत्रालय ने तब से पुष्टि की है कि वह "अब सरकार के लिए काम नहीं करता है", अभियोग का दावा है कि वह भारत के कैबिनेट सचिवालय द्वारा नियोजित था,

चाहे सच्चाई अक्षमता या मिलीभगत में हो, सरकार के खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों की छवि धूमिल हुई है। अगर सरकार उस पर मुकदमा चलाने या उसे अमेरिकी एजेंसियों को सौंपने की कार्यवाही करती है, तो उसे भविष्य में होने वाले अभियानों में शामिल अन्य गुर्गों के मनोबल पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।

सबसे बढ़कर, सरकार को अंतरराष्ट्रीय हत्याओं पर अपनी नीति के बारे में अधिक पारदर्शी होना चाहिए। यदि वह ऐसे ऑपरेशनों की अनुमति नहीं देती है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यह समय है कि इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं की अधिक विस्तृत जांच की जाए और साथ ही इसके राजनयिक संबंधों का अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाए।

राज्यपाल बनाम सरकार

श्री रवि को अनावश्यक रूप से विवादों में पड़ने के कारण वापस लिया जाना चाहिए

ए तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल के बाद राजनीतिक दुश्मनी बढ़ गई है।

एमके स्टालिन के खिलाफ़ एक बार फिर से चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, इस बार प्रसार भारती के एक कार्यक्रम में राज्य गान के विकृत गायन के कारण। 1970 से सरकारी समारोहों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाने वाला तमिल थाई वज़्थु को दिसंबर 2021 में राज्य गान घोषित किया गया। इसके बाद एक न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा कोई वैधानिक या कार्यकारी आदेश नहीं है जिसके तहत गीत बजने पर उपस्थित लोगों को खड़े होने की आवश्यकता हो, जबकि एक ऋषि इसके गायन के दौरान बैठे रहे। राज्यपाल की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में, 'द्रविड़ भूमि' की प्रशंसा करने वाले 55 सेकंड के इस राष्ट्रगान में एक छंद स्पष्ट रूप से छूट गया था। हालाँकि इसे अनजाने में किया गया बताया गया, लेकिन मंच पर इसे सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिकांश राजनीतिक दल इस चूक को अस्वीकार कर रहे थे।

श्री स्टालिन ने पूछा कि क्या श्री रवि एक "राज्यपाल" या "आर्यन" बन रहे हैं और जानना चाहा कि क्या राज्यपाल, "जो द्रविड़ एलर्जी से पीड़ित हैं", राष्ट्रगान से "द्रविड़" शब्द को हटाने का प्रस्ताव देंगे।

राज्यपाल ने इस पर नाराजगी जताई और "आर्यन" संदर्भ को "नस्लवादी" बताया। इस तरह की व्याख्या वास्तव में राज्यपाल के सिद्धांत के खिलाफ जाती है कि आर्यों और द्रविड़ों की अवधारणा मुख्य रूप से एक भौगोलिक, "नस्लीय नहीं" विभाजन थी; उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया था कि अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे "नस्लीय" बना दिया था। श्री रवि ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने मुख्यमंत्री के उच्च संवैधानिक कार्यालय की गरिमा को कम किया है। सच है, उन्हें सीधे गायकों द्वारा एक छंद को छोड़ने से जोड़ना दूर की कौड़ी थी। हालांकि, श्री रवि ने लगातार 'द्रविड़' अवधारणा को एक "पुरानी विचारधारा" से जोड़ा है जिसने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो "अलगाववादी भावना" को बढ़ावा देता है, और "एक भारत" के विचार को पसंद नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की दो-भाषा नीति के परिणामस्वरूप भाषाई रंगभेद हुआ है। प्रसार भारती के कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले 50 सालों में तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़हर भर दिया गया है। ऐसे विचारों से यह धारणा बनती है कि वे द्रविड़ से जुड़ी किसी भी चीज़ के संदर्भ के ख़िलाफ़ थे। फिर भी, श्री स्टालिन द्वारा श्री रवि पर सीधे आरोप लगाकर विवाद में पड़ना अनुचित था। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि राज्यपाल और सरकार के बीच की खींचतान में शासन व्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। राजनीतिक सक्रियता के प्रति उनके झुकाव और सरकार की नीतियों के प्रति उनके विरोध को देखते हुए, श्री रवि को बदलने का समय आ गया है। उनके और मुख्यमंत्री के बीच समीकरण सुधार से परे हैं। यह स्थिति राज्य के लिए अस्वस्थ है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़तरे में डालती है।

पुनः द्विध्रुवीय होती जा रही दुनिया में भारत के विकल्प

शशि थरूर

चौथा कार्यकाल
कांग्रेस सदस्य
संसद (लोकसभा)
सभा) से
तिरुवनंतपुरम, 'पैक्स' सहित 26 पुस्तकों के लेखक

इंडिका: भारत और
21वीं दुनिया
शताब्दी', और
के अध्यक्ष
संसदीय
बाह्य वायु पर स्थायी समिति

एल पिछले महीने, जब भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की मुलाकात ब्रिक्स राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एक संभावना फिर से पैदा हुई। क्या चीन के साथ हमारा कूटनीतिक जुड़ाव, जो जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ के बाद से तनावपूर्ण हो गया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी, सुधरने वाला है? भारत इस सवाल का सामना ऐसे समय में कर रहा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंध फल-फूल रहे हैं, जिसमें अमेरिका भारत को इंडो-पैसिफिक में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक उपयोगी भागीदार के रूप में देखता है। तो, क्या भारत को एक बार फिर द्विध्रुवीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण विकल्प का सामना करना पड़ेगा?

दो राष्ट्रों के बीच मतभेद लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं मेरा उत्तर एक योग्य हाँ होगा। हाँ, क्योंकि दो प्रमुख शक्तियाँ, अमेरिका और चीन, फिर से वैश्विक आधिपत्य के लिए होड़ कर रहे हैं; लेकिन योग्य, क्योंकि यह वह द्विध्रुवीयता नहीं है जिसे हम शीत युद्ध के दौरान जानते थे। आखिरकार, अमेरिका और चीन के एक-दूसरे के साथ कई संबंध हैं जो अमेरिका और यूएसएसआर के नहीं थे: अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेशक है, चीन के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड हैं, अमेरिका किसी भी अन्य एशियाई देश की तुलना में चीन में अधिक पर्यटक भेजता है, और अमेरिका में किसी भी अन्य राष्ट्रीयता के छात्रों की तुलना में अधिक चीनी छात्र हैं। ये दो शक्तियां हैं जो एक-दूसरे के प्रति मतभेद रखती हैं, लेकिन उनके पास कूटनीतिक संवाद और आर्थिक सहयोग के कई रास्ते हैं जो शीत युद्ध के दौरान मौजूद नहीं थे।

वह एक ऐसा युग था जब अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने उपग्रह देशों को अपने-अपने शिविरों में संगठित किया, "लोहे के पर्दे" से अलग हो गए, और अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा की। इस द्विध्रुवीयता का अंत वैश्वीकरण के आगमन के साथ हुआ, जिसने "एकध्रुवीय क्षण" की शुरुआत की, जो कुछ दशकों तक चला और जिसमें वाशिंगटन ने राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में बेरोकटोक वैश्विक प्रभुत्व का आनंद लिया।

लेकिन अमेरिका किसी भी मामले में निर्विरोध नहीं रहा। इन क्षेत्रों में लंबे समय तक कोई भूमिका नहीं रही। 2008-09 के वित्तीय संकट के आसपास, बीजिंग का भूत उभरने लगा। पिछली चौथाई सदी में चीन के "शांतिपूर्ण उदय" ने, इसके उद्योगों में अमेरिकी निवेश और निर्मित वस्तुओं में तेजी से बढ़ते निर्यात व्यापार से प्रेरित होकर, वैश्विक व्यवस्था को फिर से बदल दिया है।

चीन ने अमेरिका को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। अग्रणी विनिर्माण और औद्योगिक दिग्गज, आर्थिक आकार में इसका मुकाबला कर रहा है और इसके अधिशेषों को पार कर रहा है, साथ ही 5G जैसी नई तकनीकों में इसे चुनौती दे रहा है। इसलिए, दशकों तक बिना किसी चुनौती के अमेरिकी आधिपत्य के बाद, एक और महत्वाकांक्षी आधिपत्य उभरा है, जिसके पास हर क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने और शी जिनपिंग के नेतृत्व में एक नई मुखरता तैनात करने के संसाधन हैं। अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति विकसित कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए शीत युद्ध के दौरान "रोकथाम" का इस्तेमाल किया था। फिर भी, जिस तरह आज की चीन-अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट रूप से

भारत स्वयं को नवीकृत राजनीतिक व्यवस्था में मोहरा बनने की अनुमति नहीं दे सकता।

चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा

शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता से भिन्न, ऐसी रणनीति की रूपरेखा और उस पर भारत की प्रतिक्रिया भी अतीत से भिन्न होनी चाहिए।

अमेरिका और चीन आपस में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कुल आर्थिक अलगाव के विपरीत। इसके अलावा, चीन की आर्थिक ताकत वैश्विक आधिपत्य के लिए उसके दावे को सोवियत संघ से भी अधिक मजबूत बनाती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और इसलिए, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए चीन की अपरिहार्यता ही वह कारण है कि कुछ पर्यवेक्षक चीन-अमेरिकी द्विध्रुवीयता का वर्णन करने के लिए "शीत युद्ध" लेबल का उपयोग नहीं करना चुनते हैं, इसके बजाय "प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व", "शीत सह-अस्तित्व" या "शंकुधारी सह-अस्तित्व" जैसे शब्दों को प्राथमिकता देते हैं। इसे मान्यता देते हुए अमेरिकी बयानबाजी चीन से "अलग होने" - संबंधों के विच्छेद का सुझाव देने से - "जोखिम कम करने" में बदल गई, जिसका अर्थ है शत्रुतापूर्ण अलगाव से बचते हुए जोखिमों को कम करना।

इससे भी अधिक, जैसे-जैसे महाशक्तियाँ उभर रही हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका और यूएसएसआर सैन्य दृष्टि से लगभग बराबर थे। लेकिन चीन लगभग बराबरी के करीब पहुंच गया है और अब, कुछ क्षेत्रों में, अमेरिका से आगे निकलने की धमकी दे रहा है। पेंटागन के अनुसार, पिछले दशक में चीनी नौसेना ने युद्ध-बल वाले जहाजों की संख्या में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जिसका कारण टन भार के हिसाब से दुनिया के शीर्ष जहाज-उत्पादक देश के रूप में चीन की स्थिति है।

अमेरिकी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना की दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना बनने की क्षमता को स्वीकार किया है। फिर भी, सैन्य टिप्पणीकारों का मानना है कि कम से कम 2027 में पीएलए की शताब्दी तक, चीन और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना रहेगा। शीत युद्ध के विपरीत, आज हमारी दुनिया में दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच छद्म युद्ध नहीं चल रहे हैं। न ही बीजिंग या वाशिंगटन में इसके लिए कोई खास इच्छा है। ऐसे में शीत युद्ध स्तर की द्विध्रुवीयता की कल्पना करना, यथास्थिति और वैश्विक व्यवस्था के लिए चीन द्वारा उत्पन्न खतरे दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना है।

विचारधारा के बारे में नहीं यूएसएसआर के साथ टकराव में, अमेरिका ने साम्यवाद पर पूंजीवाद की प्रधानता और एकल-पक्षीय अधिनायकवाद पर उदार लोकतंत्र की प्रधानता स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा। हालाँकि, चीन-अमेरिकी प्रतिस्पर्धा विचारधारा के बारे में नहीं है, हालाँकि अमेरिकी इसे अन्यथा चित्रित करना पसंद करते हैं। दुनिया को साम्यवाद में बदलने का एक वैचारिक उत्साह चीन को उत्साहित नहीं करता है, जो वास्तव में केवल अपने लिए वैश्विक आधिपत्य हासिल करने में रुचि रखता है। 2021 से, वाशिंगटन ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के साथ निरर्थक प्रयोग किया है, उम्मीद है कि वह अपने सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्वी को लोकतंत्र की वकालत करने के साथ वश में करने की अपनी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन यूरोपीय लोग भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के "लोकतंत्र बनाम निरंकुशता" के द्विआधारी में विश्वास नहीं कर रहे हैं।

अमेरिका की अपने सभी निहित स्वार्थों को दुनिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए धर्मयुद्ध के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति असफल साबित हुई है। इसलिए, इस खेल को खेलने के बजाय, चीन इसे "पश्चिमी शैली के लोकतंत्र" के रूप में उपहास करने का विकल्प चुन रहा है, जो बीजिंग का तर्क है कि आम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए है।

पूंजीवाद का.

चीन-अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता को जो बात विशिष्ट बनाती है, वह यह है कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी देश रूस कभी भी कार्रवाई से दूर नहीं रहता। रूस आज के उभरते द्विध्रुवीय माहौल में एक खतरनाक भूमिका निभा सकता है; अपने आकार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परमाणु हथियारों के विशाल भंडार के कारण, यह अधिकांश मध्यम शक्तियों से आगे है। इसलिए, कई लोग तर्क देते हैं कि अमेरिका की द्विध्रुवीयता चीन के साथ नहीं बल्कि चीन और रूस की धुरी है।

उदाहरण के लिए, प्रोफेसर जोसेफ जो हमारी दुनिया को "ढाई शक्ति वाली दुनिया" के रूप में परिभाषित करते हैं, जहाँ रूस "अपनी 'उपयोगी शक्ति' की कमी के कारण अमेरिका और चीन के साथ पूर्ण समानता से पीछे रह गया है।" इटली से छोटी अर्थव्यवस्था और चीन के केवल एक-चौथाई सैन्य बजट के साथ मास्को तीसरे ध्रुव से बहुत दूर है: लेकिन यह बीजिंग का जूनियर पार्टनर है, यह तथ्य रूस के यूक्रेनी दुस्साहस के लिए चीन के समर्थन में प्रकट होता है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पश्चिम से भयभीत न होने के संकल्प को दर्शाता है। हालाँकि चीन के पास कोई सहयोगी नहीं है, केवल ग्राहक हैं, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ उसका उभरता हुआ गठजोड़ अभी भी ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक की चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है।

इंडो-पैसिफिक का नया कैनवास इस भू-राजनीतिक मंथन का सबसे बड़ा परिणाम एक बिल्कुल नए कैनवास का निर्माण रहा है: इंडो-पैसिफिक, एक शब्द जिसमें तीन अतिव्यापी घटनाक्रम शामिल हैं। ये हैं चीन का लक्ष्य एक ब्लू वाटर नेवी बनाना - एक दुर्जेय नौसैनिक बल जो उच्च समुद्र पर संचालन और शक्ति प्रक्षेपण करने में सक्षम हो - और एक अंतरमहाद्वीपीय आर्थिक दिग्गज बनना, भारत का चीन के लिए एक संभावित प्रतिसंतुलन के रूप में उभरना, और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रतीत होने वाले अपरिहार्य शक्ति परिवर्तन की रूपरेखा को आकार देने में अमेरिका की भूमिका: अटलांटिक से हिंद और प्रशांत महासागर तक।

अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना बहुचर्चित क्वाड एक "स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक" के दृष्टिकोण से प्रेरित है, और हाल ही में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के "स्क्वाड" द्वारा इसे और बढ़ाया गया है। इसके अलावा AUKUS भी है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जिसके माध्यम से अमेरिका और यूके ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में सहायता करते हैं। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पारंपरिक गठबंधनों और भू-राजनीतिक थिएटरों के पुनर्गठन का प्रतीक है।

इंडो-पैसिफिक चीन और अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं के टकराव का केंद्र बनकर उभर रहा है, ऐसे में अमेरिका और क्वाड के साथ भारत के गहरे होते रिश्ते चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरे हुए हैं। हम यह नहीं भूल सकते कि चीन से ज़मीनी खतरा सिर्फ़ हमें है, क्वाड के दूसरे सदस्य नहीं।

इसलिए, हमें चीन-भारत सीमा पर यथास्थिति बहाल करके अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ चीनियों के साथ आर्थिक रूप से बातचीत करने, अपनी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने और अपनी शर्तों पर अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत इस नए द्विध्रुवीय मुकाबले में खुद को मोहरा बनने की इजाज़त नहीं दे सकता।

बदलती दुनिया में आवश्यक व्यावसायिक प्राथमिकताएँ

चंद्रजीत बनर्जी

महानिदेशक,
परिसंघ
भारतीय उद्योग

एफ हाल के दिनों की अनेक आवश्यकताओं को देखते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना दिख रही है। इस वर्ष स्थिर हो गए हैं, हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम अभी भी बने हुए हैं। वर्ष की पहली तिमाही में जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने अलग-अलग विकास दर प्रदर्शित की, जिनमें से कुछ अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ीं, जबकि अन्य को असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस परिदृश्य में, दुनिया के व्यवसायों में विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने और विकासात्मक लाभों के व्यापक प्रसार से लाभ उठाने की क्षमता है।

पिछले तीन वर्षों में बी-20 प्रक्रिया का नेतृत्व उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किया गया है, और इस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका को सौंपे जाने के साथ, वैश्विक दक्षिण के लिए एक अभूतपूर्व एजेंडा को गति मिली है। उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों के व्यवसाय एक साथ आए हैं और प्रमुख प्राथमिकताओं और नीतिगत कार्रवाइयों की पहचान की है जो समावेशी वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाएगी।

साथ ही, विकास के प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यवसायों को भी विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुरूप कुछ कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी।

समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना समतामूलक विकास एक सर्वोच्च अनिवार्यता बनी हुई है, क्योंकि विश्व समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहता है।

इसे सक्षम करने के लिए कौशल विकास और शिक्षा शामिल है जो श्रमिकों को सशक्त बनाने और बदलते औद्योगिक परिदृश्यों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का निर्माण करने की दिशा में काम करेगी। व्यवसायों को श्रमिकों - विशेष रूप से महिलाओं - को कौशल प्रदान करने और कौशल बढ़ाने के लिए अनुरूप कार्यक्रम प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करना और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करना शामिल है।

बी-20 ब्राजील द्वारा वित्तीय पहुंच और विविधता तथा समावेशन नीतियों के साथ-साथ अनुरूपित ऋण समाधान पर जोर दिया गया है। भारत में, संयुक्त भुगतान इंटरफेस और डिजिटल पहुंच के अभिसरण ने वित्तीय लेन-देन को बदल दिया है, जिसमें ऐतिहासिक जन धन योजना के तहत 530 मिलियन से अधिक खाते खोले गए हैं।

इस तरह की सफलता से कई सबक मिलते हैं

उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी वृद्धि और विकास एक वास्तविकता बन सकता है, यदि पहचाने गए प्रमुख नीतिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

इसी तरह, भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीका को जी-20 में शामिल करने से महाद्वीप में नए अवसरों का खजाना खुल गया है। वैश्विक व्यवसायों के लिए अफ्रीका में अपने पदचिह्नों का विस्तार करना महत्वपूर्ण है, ताकि न केवल इसके तेजी से विकास और युवा जनसांख्यिकी का लाभ उठाया जा सके, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महाद्वीप के समावेश का समर्थन भी किया जा सके।

बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सतत खाद्य प्रणालियां और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना स्थिरता प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए फोकस का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है।

चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव सहित असंख्य कारकों ने वैश्विक खाद्य संकट को और बढ़ा दिया है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, अपशिष्ट को कम करने और सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा। व्यवसाय टिकाऊ पद्धतियों की वकालत करके, बुनियादी ढाँचे और कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे कि सटीक खेती में निवेश करके और खाद्य सुरक्षा पर प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

दूसरा, लचीले वैश्विक व्यापार प्रवाह को तेज करना वैश्विक विकास के लिए आवश्यक है, फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और अनुचित व्यापार व्यवहार टैरिफ और अन्य बाधाओं को बढ़ा रहे हैं जो व्यापार की पारदर्शिता को बाधित करते हैं। विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों को अनुचित व्यापार प्रथाओं की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए, जबकि पर्यावरणीय उपायों के लिए सहमत अंतर-संचालन वर्गीकरण स्थिरता के उद्देश्य से औद्योगिक और व्यापार नीतियों में व्यवसायों के लिए अधिक स्पष्टता ला सकता है।

तीसरी प्राथमिकता, जिसका नेतृत्व व्यवसायों को करना चाहिए, वह है सामान्य भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित डिजिटल परिवर्तन और नवाचार।

व्यवसायों को स्वास्थ्य सेवा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन में जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए एआई का उपयोग करना चाहिए। व्यवसायों के लिए समकालीन मुद्दों पर दबाव डालने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने में युवाओं को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। निवेश और

सामाजिक तकनीक स्टार्टअप के लिए परामर्श, अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) प्रतिभा को विकसित करने जैसे काम कॉर्पोरेट्स द्वारा मिशन मोड में किए जाने चाहिए।

स्थिरता मिशन चौथी प्राथमिकता है व्यवसायों के लिए। जैसे-जैसे दुनिया नेट-ज़ीरो संक्रमण की ओर बढ़ रही है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जलवायु नीतियाँ व्यवसायों को कार्बन शमन की दिशा में काम करने में सक्षम बना सकती हैं। नेट ज़ीरो लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सभी उद्यमों और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए धन की उपलब्धता आवश्यक है। अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण और जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन के अधिक उपयोग को व्यवसायों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योग को भी सर्कुलर इकोनॉमी विकल्पों के बारे में जागरूक होना चाहिए और अपने सामान्य संचालन में बोर्ड भर में संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

उच्चतम मानकों का लक्ष्य सबसे ऊपर, उच्चतम मानकों के कॉर्पोरेट प्रशासन को व्यवसायों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसमें बड़े वैश्विक कॉर्पोरेट और छोटे और मध्यम उद्यम शामिल हैं। नैतिक संचालन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अनुपालन और नियामक प्रणालियों में स्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं से आगे बढ़ना निजी उद्योग की जिम्मेदारी है। इससे समुदाय, सरकारों और व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करने में सुविधा होगी। आज विश्वास को दुनिया भर में विकास प्रक्रिया और व्यापार करने में आसानी के लिए आंतरिक माना जाता है।

ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बी20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट के माध्यम से काम करेंगे जिसकी परिकल्पना भारत के बी20 नेतृत्व के दौरान की गई थी और अब यह आगे बढ़ रहा है। लगातार जी-20 प्रेसीडेंसी देशों की भागीदारी के साथ, संस्थान नीतिगत सुझावों में संरेखण बनाए रखेगा, उपरोक्त क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्रवाई एजेंडा शुरू करेगा और परिणामों की निगरानी करेगा। जैसे ही बी20 सिफारिशें जी-20 समूह के सामने पेश की जाती हैं, दुनिया के व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि हमारी आम वैश्विक आकांक्षाएं फलित हों।

संपादक के नाम चिठी

अब जबकि जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल ने साफ़ कर दिया है कि यह

केंद्र सरकार को इस क्षेत्र के लोगों के 'संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और उनकी पहचान की रक्षा करने' के अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

अगर 'मूल रूप में राज्य का दर्जा' का मतलब 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख' है, तो भी इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। अगर केंद्र को लगता है कि सुरक्षा और मजबूत स्थिति के मुद्दे हैं, तो वह इस पर विचार कर सकता है।

लद्दाख के मामले में भौगोलिक बाध्यताओं से नई राज्य सरकार को अवगत कराया जाना चाहिए।

पीआरवी राजा,
पंडालम, केरल

शांति की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं हमास के याह्या सिनवार के खात्मे से पश्चिम एशिया में स्थिति और खराब होगी। हमास बदला लेना चाहेगा, पीछे नहीं हटेगा

ऐसा लगता है कि गाजा और लेबनान को धूल में मिला देने की चाहत रखने वाले इजरायल के साथ शांति की कोई उम्मीद नहीं है।

रोहित वरोन एसएस, चेन्नई

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंता बढ़ातीं धमकियां

बम होने की झूठी धमकियों के कारण इस सप्ताह 94 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बाधित हुई हैं. शनिवार को 30 और रविवार को 24 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी. इन उड़ानों को या तो बीच में उतारना पड़ा या उनका रास्ता बदला गया. हालांकि जांच में कोई बम बरामद नहीं हुआ है, पर ऐसी धमकियों से विमानों के परिचालन में मुश्किलें बढ़ गयी हैं. यात्रियों एवं कर्मियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. जांच के लिए विमानों को हवाई अड्डों के सुरक्षित इलाकों में ले जाना पड़ रहा है. जांच के दौरान यात्रियों को विमान में ही बैठे रहना पड़ रहा है. उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को भी हवाई अड्डों पर देर तक रुकना पड़ रहा है. तमाम हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया गया है. सभी धमकियां सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों, विशेष कर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी गयी हैं. दिल्ली एवं अन्य महानगरों की पुलिस इन मंचों के संपर्क में हैं. कुछ संदिग्धों को चिह्नित भी किया गया है. दिल्ली पुलिस के साइबर सेल और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस भी जांच में सहयोग दे रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल पहचान को छुपाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में अकाउंट खोल कर धमकियां दी जा रही हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. दोषियों को हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगाने के संबंध में भी चर्चा हो रही है. भारत उन देशों में है, जो विमानों के अपहरण और आतंकी हमलों के भुक्तभोगी रहे हैं. इसलिए ऐसी धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है तथा समुचित सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं. आशा है कि जांच से दोषियों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें दंडित किया जायेगा. इन घटनाओं ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को और बढ़ा दिया है. उल्लेखनीय है कि हमारे देश में साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे अपराधों में घरेलू अपराधी भी शामिल हैं और बाहर के भी. साइबर सुरक्षा के मौजूदा उपाय अपेक्षित रूप से कारगर साबित नहीं हो रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे को आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षण मुहैया कराया जाना चाहिए. साथ ही, सोशल मीडिया के मंचों, मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा से जुड़ी कंपनियों तथा शासकीय विभागों के बीच बेहतर समन्वय समय की मांग है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब, वीपीएन आदि के दुरुपयोग को लेकर जो चिंताएं जतायी जा रही हैं, उनके समाधान पर जोर देने की जरूरत है. यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं इन धमकियों का उद्देश्य उड्डयन क्षेत्र के विकास को बाधित करना तो नहीं है.

ऐसी धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है तथा समुचित सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला के सामने अनेक चुनौतियां

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर 28 अरब डॉलर के राज्य जीडीपी के साथ देश में 21वें स्थान पर है. उमर की प्राथमिकताएं जम्मू-कश्मीर में अधिक निवेश लाना, हस्तशिल्प और पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है. उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा किया है. उम्र उनके पक्ष में है. कश्मीर सभी भारतीयों का है, ठीक उसी तरह, जैसे भारत सभी कश्मीरियों का है.

आप अब्दुल्ला से कश्मीर को अलग कर सकते हैं, पर आप अब्दुल्ला को कश्मीर से नहीं निकाल सकते. पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर के नये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया- 'मैं वापस आ गया हूं.' मानो एक कश्मीरी श्वार्जनेगर टर्मिनेटर की भूमिका में है, जिसने अपने सियासी दुश्मनों को मिटा दिया है. ब्रिटेन में जन्मे 54 वर्षीय तीसरी पीढ़ी के अब्दुल्ला का पोस्ट एक आनुवांशिक निष्कर्ष था. अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शेरवानी और पायजामा पहनने की परंपरा का पालन किया, जो स्थानिकता, आनुवंशिकता और निरंतरता का संकेत था. उनकी राजनीतिक विरासत यह रेखांकित करती है कि वे केंद्रशासित प्रदेश (यानी स्वयं) के लिए अधिक शक्ति मांगें और पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन करें तथा यह भी कि जम्मू-कश्मीर अन्य राज्यों से अलग है. उमर भी अब अलग हैं. अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद वे भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं. शायद सत्ता से बाहर रहने ने उन्हें व्यावहारिक बनाया है. उन्होंने यह समझ लिया है कि उन्हें और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नयी राजनीतिक वास्तविकता के साथ जीना होगा.

उन्होंने एक नया कश्मीर संभाला है, जहां वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और कश्मीरियत को जल्दी बहाल किया जाना चाहिए. अब्दुल्ला परिवार ने हमेशा कश्मीर के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की है. हालांकि वे घाटी के बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से डोगरा राजवंश की जगह ली है, लेकिन जम्मू में भगवा विचारधारा का बोलबाला है. आगे की गति और राजनीतिक शांति के लिए दोनों को मिलना होगा. इसके लिए उमर को अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए. कश्मीर में 1990 से अब तक एक लाख से अधिक नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं. इस बार मतदाताओं ने उमर को विकास और सम्मान के लिए बड़ा जनादेश दिया है. अपनी आधुनिक छवि और मुखर रवैये के बावजूद अब्दुल्ला जूनियर का सिंहासन कांटों से भरा है. उन्हें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कार्यक्रम आधारित शासन सुनिश्चित करना चाहिए, जो अब तक मरणासन्न था. जम्मू-कश्मीर को किसी भी चीज से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता की जरूरत है. यह शायद एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 1951 से अब तक आठ मुख्यमंत्रियों के मुकाबले 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है. यहां केंद्र सरकार का शासन सबसे अधिक समय रहा है. उमर के दादा शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ने नेहरू के आदेश पर गिरफ्तार होने से पहले लगभग पांच साल तक शासन किया था. इसके बाद, दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों बख्शी गुलाम मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद सादिक ने छह से दस साल तक जम्मू-कश्मीर पर शासन किया.

तीनों अब्दुल्लाओं के नाम सबसे लंबे समय तक इस राज्य पर शासन करने का रिकॉर्ड है- कुल मिलाकर 34 साल. शेख अब्दुल्ला पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद चार अलग-अलग कार्यकालों में 17 साल से अधिक समय तक मंत्री रहे. शासन करने की कला उनकी रगों में है. परिवार सत्ता के व्याकरण और वैभव को जानता और समझता है. उमर ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कुछ फायदों के साथ की है, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं. न केवल उनकी पार्टी को अपने दम पर लगभग बहुमत प्राप्त है, बल्कि वह अलगाववादी दबाव को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकती है. त्रिशंकु विधानसभा की कोशिश कर रहीं लगभग सभी छोटी पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है. महबूबा मुफ्ती की पार्टी निर्णायक रूप से हार गयी और अब वह घाटी का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती है. अब्दुल्ला ने घाटी में लगभग तीन-चौथाई सीटों पर और जम्मू में लगभग आधा दर्जन सीटों पर कब्जा कर लिया. यहीं पर समस्या है. उमर की कट्टर प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने जम्मू क्षेत्र में न केवल 29 सीटें जीतीं, बल्कि उसने सबसे अधिक वोट प्रतिशत (25.69) भी हासिल किया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस (23.47) से अधिक है. कांग्रेस ने 12 प्रतिशत वोट के साथ मात्र छह सीटें जीती हैं.

उमर ने कुछ अच्छी बातों के साथ दूसरी पारी की शुरुआत की है. अपने दादा और पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए उन्होंने एक आदिवासी हिंदू को उपमुख्यमंत्री बनाकर जम्मू क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिया है. शेख के मंत्रिमंडल में एक-तिहाई कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू शामिल थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू क्षेत्र से भी सम्मानजनक संख्या में सीटें जीतती थी. इस बार जम्मू ने राज्य के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे को बदलने की केंद्र सरकार की पहल के लिए मतदान किया. केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, पर अनुच्छेद 370 की वापसी की संभावना नहीं है. अब्दुल्ला परिवार को यह एहसास हो गया है. मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उमर ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया- 'अनुच्छेद 370 को भूल जाओ और अन्य राज्यों को हासिल शक्तियों के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए लड़ो. हम जानते हैं कि आप इसे उस सरकार से वापस नहीं पा सकते, जिसने इसे छीन लिया है. इसलिए इसे अभी के लिए अलग रख दें.' अब मोदी को राज्य की सभी शक्तियों को वापस कर उदारता दिखानी चाहिए, जो 2019 और उसके बाद के प्रशासनिक आदेशों द्वारा छीन ली गयी थीं. जाहिर है कि उनका प्रयास अपने संघर्षग्रस्त राज्य का बेहतर प्रबंधन करना होगा, जो मोदी सरकार के साथ टकराव का विकल्प चुनने पर संभव नहीं हो सकता. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे केंद्र पर दबाव डालेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए. उन्हें यह ध्यान में रखने की सलाह दी गयी है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, जिन्होंने सीधे मोदी से मुकाबला करने की कोशिश की.

वैचारिक युद्धों को सुशासन का भाग्य तय नहीं करना चाहिए. उमर प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवारों में से एक बनने की भ्रामक महत्वाकांक्षा से बाधित नहीं हैं. उनके लिए केंद्रीय शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास को बढ़ाना समझदारी होगी. केंद्र सरकार ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उदारता से आवंटन किया है. वर्तमान में जम्मू-कश्मीर 28 अरब डॉलर के राज्य जीडीपी के साथ देश में 21वें स्थान पर है. उमर की प्राथमिकताएं जम्मू-कश्मीर में अधिक निवेश लाना, हस्तशिल्प और पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है. उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा किया है. उम्र उनके पक्ष में है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश की प्रगति में रोड़ा बनता मधुमेह

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

एक सर्वे में डरावने तथ्य सामने आये हैं कि मधुमेह की चपेट में आये लोगों में से 14.4 फीसदी को किडनी और 13.1 को आंखों की रोशनी जाने का रोग लग जाता है, 14.4 प्रतिशत मरीजों के पैरों की धमनियां जवाब दे जाती हैं, जिससे उनके पैर खराब हो जाते हैं तथा लगभग 20 फीसदी लोग दिल की किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं. इतना ही नहीं, 6.9 प्रतिशत लोगों को न्यूरो यानी तंत्रिका से संबंधित दिक्कतें भी होती हैं.

मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और आइसीएमआर के शोध के अनुसार, चिप्स, कुकीज, केक, फ्राइड फूड और मेयोनीज जैसी चीजों के सेवन से डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. रिसर्च में कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से भारत डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है. भारत की कोई 8.29 करोड़ वयस्क आबादी का 8.8 प्रतिशत हिस्सा मधुमेह की चपेट में है. अनुमान है कि 2045 तक यह संख्या 13 करोड़ से अधिक हो जायेगी. यह वह काल होगा, जब बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ेगी. मधुमेह वैसे तो खुद एक रोग है, पर इससे मरीजों की जेब भी खोखली हो रही है और मानव संसाधन की कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लोगों ने एक साल में डायबिटीज या उससे उपजी बीमारियों पर सवा दो लाख करोड़ रुपये खर्च किये, जो हमारे सालाना बजट का 10 फीसदी है. बीते दो दशक में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह रोग फिलहाल चिकित्सा जगत के लिए महज कमाई का जरिया है. दर्जनों किस्म के डायबिटीज मॉनिटर, हजारों किस्म की आयुर्वेदिक दवाएं और नुस्खे बेचे जा रहे हैं. लंदन में यदि किसी को मधुमेह है, तो पूरे परिवार का इलाज निशुल्क है. भारत में ऐसा कोई संवेदनशील नजरिया नहीं हैं.

एक अनुमान है कि एक मधुमेह मरीज को औसतन 4,200 से 5,000 रुपये दवा पर खर्च करने पड़ते हैं. यह रोग ग्रामीण, गरीब बस्तियों और तीस साल तक के युवाओं को भी शिकार बना रहा है. डायबिटीज खराब जीवन शैली से उपजने वाला रोग है, तभी बेरोजगारी, अधिक भौतिक सुख जोड़ने की अंधी दौड़ खून में शर्करा की मात्रा बढ़ा ही रही है, कुपोषण, घटिया गुणवत्ता वाला पैक्ड भोजन भी मरीजों की संख्या बढ़ाने का बड़ा कारक है. लेह-लद्दाख पहाड़ी इलाका है, जहां लोग खूब पैदल चलते थे, मेहनत करते थे, सो कभी बीमार नहीं होते थे. पिछले कुछ दशकों में वहां बाहरी प्रभाव और पर्यटक बढ़े. बाहरी दखल के चलते यहां चीनी का इस्तेमाल होने लगा. अब वहां डायबिटीज जैसे रोग घर कर रहे हैं. दवा कंपनी सनोफी इंडिया के एक सर्वे में डरावने तथ्य सामने आये हैं कि मधुमेह की चपेट में आये लोगों में से 14.4 फीसदी को किडनी और 13.1 को आंखों की रौशनी जाने का रोग लग जाता है, 14.4 प्रतिशत मरीजों के पैरों की धमनियां जवाब दे जाती हैं, जिससे उनके पैर खराब हो जाते हैं तथा लगभग 20 फीसदी लोग दिल की किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं. इतना ही नहीं, 6.9 प्रतिशत लोगों को न्यूरो यानी तंत्रिका से संबंधित दिक्कतें भी होती हैं.

अमेरिकी मानक संस्थाओं ने भारत में रक्त में चीनी की मात्रा को कुछ अधिक दर्ज करवाया है, जिससे प्री-डायबिटीज वाले भी दवाओं के फेर में आ जाते हैं. यह सभी जानते हैं कि एक बार डायबिटीज हो जाने पर मरीज को जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है. मधुमेह नियंत्रण के साथ-साथ रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं लेना आम बात है. किडनी बचाने की दवा भी लेनी पड़ती है. जब इतनी दवा लेंगे, तो पेट में बनने वाले अम्ल के नाश के लिए भी दवा जरूरी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए कोई मल्टी-विटामिन भी अनिवार्य है. एक साथ इतनी दवाओं के बाद लीवर पर असर पड़ेगा ही. इसमें शुगर मापने वाली मशीनों व दीगर जांचों को तो जोड़ा ही नहीं गया है. दूरस्थ अंचलों की बात तो जाने दें, महानगरों में ही हजारों ऐसे लैब हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट संदिग्ध रहती है. प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत इलाज की निशुल्क व्यवस्था में मधुमेह जैसे रोगों के लिए जगह नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जरता की बानगी सरकार की सबसे प्रीमियम स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस यानी केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा है, जिसके तहत पत्रकार, पूर्व सांसद आदि भी आते हैं. इसके तहत पंजीकृत लोगों में चालीस फीसदी डायबिटीज के मरीज हैं और वे हर महीने केवल नियमित दवा लेने जाते हैं. मरीज डॉक्टर के पास जाता है और उसे किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है. विशेषज्ञ कई जांच लिखता है और मरीज को फिर अपनी डिस्पेंसरी में आकर जांच कराना होता है. फिर विशेषज्ञ के पास जाना होता है. इस प्रक्रिया में कम से कम पांच दिन लगते हैं, लंबी कतार झेलनी होती है. बहुत से मरीज इससे घबरा कर नियमित जांच भी नहीं करवाते. जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में तो जांच से ले कर दवा तक का खर्च मरीज को खुद वहन करना होता है.

आज भारत मधुमेह को ले कर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है. जरूरत है कि इस पर सरकार अलग से नीति बनाये. स्टेम सेल से डायबिटीज के स्थायी इलाज का व्यय महज सवा लाख से दो लाख रुपये है, पर सीजीएचएस में यह इलाज शामिल नहीं है. इस पद्धति को सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए. बाजार में मिलने वाले पैक्ड और अन्य खाद्य सामग्री की कड़ी पड़ताल हो, योग और कसरत को बढ़ावा देने के अधिक प्रयास हों. ऐसे प्रयास युवा आबादी की कार्यक्षमता बढ़ाने और इस बीमारी से बढ़ती गरीबी के निदान में सकारात्मक कदम हो सकते हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

अपने यहां आने वाले प्रवासियों को अल्बानिया भेज रहा इटली

इटली ने अपने यहां आने वाले अनियमित प्रवासियों की पहली खेप अल्बानिया भेजी है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे एक नया, साहसी और अभूतपूर्व निर्णय बताया है. इटली ने अगले पांच वर्षों में अल्बानिया में दो प्रवासी प्रसंस्करण केंद्रों पर 730 मिलियन डॉलर खर्च करने का वादा किया है. इन केंद्रों में केवल वयस्क पुरुषों को रखा जायेगा. महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर और बीमार लोग इटली में ही रह सकेंगे. विदित हो कि मेलोनी ने नवंबर 2023 में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के साथ पांच वर्ष के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था. इसके तहत इटली के तटरक्षकों द्वारा हर महीने समुद्र से पकड़े जाने वाले करीब 3,000 प्रवासियों को अल्बानिया भेजा जायेगा. शरण मांगने के उनके आवेदनों पर जब तक विचार होगा, वे अल्बानिया में बने असाइलम प्रोसेसिंग सेंटरों में रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के कानून के तहत, प्रवासियों को शरण के लिए आवेदन करने का अधिकार है. हालांकि, इटली समेत कई यूरोपीय देश अनियमित तरीके से आने वाले प्रवासियों और शरणागतों की बड़ी संख्या को अपने लिए बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं. ऐसे में मेलोनी सरकार की यह योजना कई देशों का ध्यान आकर्षित कर रही है. इनमें ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भी हैं. यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी इस निर्णय को अभिनव सोच का नतीजा बताते हुए समर्थन किया है. हालांकि, कई मानवाधिकार समूह इसे खतरनाक उदाहरण कायम करने वाला समझौता कह रहे हैं. इटली की भौगोलिक स्थिति देखें, तो यह तीन ओर- पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से समुद्र से घिरा है. विशाल समुद्री इलाका होने के कारण लीबिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों से होकर नाव से भूमध्यसागर पार करते हुए इटली पहुंचना, अनियमित प्रवासियों द्वारा लिये जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है. हाल के वर्षों में इन प्रवासियों की संख्या काफी बढ़ी है.

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

हर जीवन की शक्ति

भौतिक और आध्यात्मिक विविधताओं में सर्वोच्च एक ही है- इस जगत का अद्वैत कारण. एक ही मूल सत्ता स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगतों का निर्माण और नियंत्रण करती रही है. समय के साथ सभी सृजित सत्ताएं अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं. साथ ही वह प्रत्येक वस्तु की साक्षी शक्ति भी है. मनुष्य को उस परम एकात्म आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना चाहिए. परमपुरुष इस जगत का मूल आधार हैं. संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जायेगा. परमपुरुष की इच्छा से प्रकट हुई प्रकृति के प्रभाव से स्थूल कल्पना के प्रवाह में पांच मूल तत्व- आकाश, वायु, अग्नि, द्रव और ठोस- उत्पन्न हुए. प्राण या जीवन भौतिक संरचना के भीतर आंतरिक टकराव और सामंजस्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ. इसके बाद विकास के विभिन्न चरणों में जीव उत्पन्न हुए और अंत में मनुष्य का विकास हुआ. परंतु मूल कारण एक अनंत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ इकाई- परम पुरुष है. लोग सोचते हैं कि समय, प्रकृति, भाग्य, दुर्घटना, मूल कारक या इकाई चेतना सृष्टि का मूल कारण हैं. परंतु उनमें से किसी को भी सृष्टि के मूल कारण के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है. भौतिकवादी इस बोधगम्य सृष्टि को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं और इंद्रियों के दायरे से परे हर चीज को नकारते हैं. वे समझना नहीं चाहते कि पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए समय, स्थान और व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर है. पदार्थ ऊर्जा से उत्पन्न होता है और ऊर्जा विचार से उत्पन्न होती है. और परमपुरुष एक अतींद्रिय सत्ता है. वे उस परम कारण को पहचानना नहीं चाहते जिससे असंख्य स्पंदन निकल रहे हैं और जिसमें अंततः सभी सत्ताएं विलीन हो जाती हैं. वास्तव में हम जिसे भी सृष्टि का मूल भौतिक कारण मानते हैं, वह केवल ऊर्जा की अभिव्यक्ति है. ऊर्जा कोई मूल सत्ता नहीं है, परमपुरुष के मूल तत्व प्रकृति के स्थिर प्रभाव की एक विशेष अभिव्यक्ति है. इसलिए, किसी वस्तु के मूल तत्व को जानने के लिए, शिव व शक्ति के मिश्र ब्रह्म को जानना होगा.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

प्रबंध सूत्र

जिस विषय की समझ नहीं, उससे रहें दूर

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

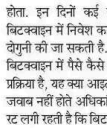

जिंदगी सहज हो सकती है, अगर सहज बुद्धि से काम लिया जाए, पर सहज बुद्धि कई बार सहज नहीं मिलती. सहज बुद्धि या कॉमन सेंस किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता. सहज बुद्धि तब आती है, जब खुली आंखों से दुनिया को देखो. यह काम भी आसान नहीं होता. इन दिनों कई लोग कहते हैं कि बिटक्वाइन में निवेश कर एक साल में रकम दोगुनी की जा सकती है. उनसे पूछा जाए कि बिटक्वाइन में पैसे कैसे कमाये जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, यह क्या आइटम है. इन सवालों के जवाब नहीं होते अधिकांश के पास. बस यही रट लगी रहती है कि बिटक्वाइन से पैसे कमाये जाते हैं. तमाम स्कीमों से बहुत तेज गति से पैसे कमाने की बात कही जाती है, तो कॉमन सेंस के तहत कान खड़े होने चाहिए. शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड से कैसे कमाया जाता है, इन सवालों के जवाब कॉमन सेंस से तलाशे जाने चाहिए.

शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदे-बेचे जाते हैं, कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, तो उनके शेयरों के भाव बढते हैं. तर्क समझ में आता है. म्यूचुअल फंड भी शेयरों में निवेश करते हैं, अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, तो फंड के निवेश की वैल्यू बढ़ती है. यह बात भी समझ में आती है, पर बिटक्वाइन में कौन-सा धंधा होता है, यह समझ नहीं आता है. बिटक्वाइन की कमाई को कॉमन सेंस से समझना मुश्किल है. इसलिए सहज बुद्धि से बिटक्वाइन से दूरी बनानी चाहिए. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की बुनियादी जानकारी न हो, तो इससे भी दूर रहें. कॉमन सेंस यही कहता है कि जिस विषय की समझ न हो, उसे या तो समझें या दूर रहें. आफत यह है कि सहज बुद्धि की जगह इंसान की बुद्धि में लालच आ जाता है. सहज बुद्धि जब लालच की जगह ले ले, तो जिंदगी चौपट हो जाती है.

कॉमन सेंस का होना जरूरी होता है. रुपये-पैसे के मामले में बहुत पढ़े-लिखे लोग भी सहज बुद्धि से नहीं, लालच से चलते हैं. लालच बुरी बला है, यह सामान्य कहावत हम सबने सुनी है, पर हम उस पर अमल नहीं करते. जो निवेश बहुत जटिल हो, उससे दूर रहिए. कई बार होता यूं है कि अर्द्धज्ञानी डूब जाते हैं, अज्ञानी पार चले जाते हैं. ऐसे कई लोग हैं, जो अपने प्रोविडेंड फंड वगैरह की रकम बैंक में लगा देते हैं और ब्याज से उसे बढ़ाते जाते हैं. दूसरी तरफ ऐसे ज्ञानी मिलते हैं, जो रोज शेयर बाजार से लाखों कमाने की कोशिश करते हैं, फिर सारी रकम डूब जाती है. अज्ञानी को पता है कि उसे शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता, तो वह सुरक्षित रास्ते पर निकल जाता है. यह कॉमन सेंस की सीख है. अर्द्धज्ञानी डूब जाता है क्योंकि वह कॉमन सेंस पर नहीं, अर्द्धज्ञान पर टिका होता है.

आपके पत्र

उमर अब्दुल्ला के सामने बड़ी चुनौती

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों ली. इसके साथ ही वहां चल रहा राष्ट्रपति शासन का काल खत्म हो गया. लेकिन, उनके सामने कई चुनौतियां हैं. इनमें कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों से निबटने के साथ वहां शांति बहाल करना प्रमुख है. अब्दुल्ला को यहां के विकास के लिए अलग से रणनीति बनानी होगी. अब यह भी देखना होगा कि अब्दुल्ला मौजूदा कानूनी ढांचे से प्रतिबंधित रहेंगे या अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली निर्वाचित सरकार के रूप में जम्मू-कश्मीर के सभी पहलुओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगे.

अंशु भारती, बेगूसराय

कुत्तों के आतंक से आमलोग परेशान

पिछले कुछ वर्षों से कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. आवारा कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं. कुत्ता एक वफादार जानवर है और आदमी के बीच रहता है. लेकिन, आजकल उसके स्वभाव में काफी परिवर्तन हुआ है. इनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ गयी है. ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण कुत्ते हिंसक हो गये हैं. आवारा कुत्तों के कारण हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं. आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण अभियान चलाना चाहिए.

हिमांशु शेखर, गया

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 21 अक्टूबर 2024

तालमेल का संकट

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. ब्लॉक को ज्यादा तालमेल और एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, तब झारखंड में सीट बंटवारे के सवाल पर उसमें बिखराव दिख रहा है। आलम यह है कि गठबंधन का पुराना सहयोगी दल RJD साफ शब्दों में कह रहा है कि उसके सभी विकल्प खुले हैं।

एकतरफा घोषणा | सीटों के बंटवारे पर घोषणा से पहले न केवल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बल्कि RJD प्रमुख तेजस्वी यादव भी रांची में थे। फिर भी, मीडिया में सीट बंटवारे पर सहमति का एलान करते हुए RJD या लेफ्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। एकतरफा घोषणा कर दी गई कि 81 में से 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) लड़ेंगे। बाकी सीटें अन्य दलों यानी RJD और CPI-ML को दी जानी हैं। मगर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर अभी अटकलें ही चल रही हैं।

झारखंड : I.N.D.I.A. में तकरार

I.N.D.I.A. में नया ट्रेंड | कुछ ही समय पहले यूपी में दस सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर दस में से छह सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। वैसे तो राज्यों के चुनावों में पार्टियों का ऐसा रुख पहले भी दिखता रहा है, लेकिन खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद I.N.D.I.A. के क्षेत्रीय घटक दलों की ओर से उसे दबाव में लाने की कोशिश देखी गई। ऐसे में क्या झारखंड में JMM के साथ मिलकर दिखाया गया यह रुख उन दलों को कांग्रेस का जवाब है?

बढ़ी हुई आकांक्षा | वैसे, अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों की कसौटी पर देखें तो सीट बंटवारे का JMM-कांग्रेस फॉर्मूला ज्यादा अटपटा नहीं लगता। पिछले विधानसभा चुनाव में RJD ने सात सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और एक सीट पर उसे जीत मिली थी। पांच सीटों पर वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। ऐसे में उसे छह सीटों की पेशकश एक स्तर पर तर्कसंगत ही कही जाएगी। RJD हालांकि इसे राज्य में अपने बढ़े हुए प्रभाव के आधार पर गलत करार दे रहा है।

सर्वसम्मति की राह | खास बात यह कि कोई सर्वसम्मत फॉर्मूला न निकाले जाने पर उसने 15 से 18 सीटें ऐसी बताई हैं जिन पर उसे भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी को हरा भी सकता है। अगर इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिया गया बयान मान भी लें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी इन सीटों पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की संभावनाएं बिगाड़ सकती है। आखिर, हरियाणा में कुछ हजार वोटों के अंतर से BJP के हाथ तीसरी बार सत्ता की चाबी लगी। इसलिए, अच्छा होगा कि I.N.D.I.A. ब्लॉक में आपसी तालमेल बेहतर हो।

चक्र-व्यू

सीने में जलन

राहुल पाण्डेय

हमारी ओर अव्वल तो पेड़ काटा नहीं जाता, सूख जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर काटना ही पड़े तो काटने से पहले पूजा जाता है। कोई-कोई पंडित बुला लेता है, नहीं तो कोई घरैतिन या खुद पेड़ काटने वाला पेड़ से उसे काटने की इजाजत और माफी मांगता है। बुआ बताती थीं कि हर पेड़ में कोई न कोई ब्रह्म होता है। वह सिर ना चढ़े, इसलिए उसकी विधि-विधान से पूजा की जाती है। बुआ यह भी बताती थीं कि जब भी कोई सांप-बिच्छू दिख जाए तो उसे प्रणाम करके अपना रास्ता बदल लो। वह कुछ नहीं करेगा। इसके पीछे खुद उनकी दर्जनों कहानियां थीं, जिसमें कभी किसी कोबरा या करैत या किसी धामिन को प्रणाम करके वह अपने रास्ते हुईं और सांप अपने रास्ते। हर जीव में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, यह दुनिया के कई आदिवासी समुदायों की मान्यता रही है और भारत में तो शायद सबसे ज्यादा। अपनी एक किताब में युवाल नोआ हरारी दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाले नायक समुदाय के बारे में बताते हैं। जंगल में भटकते हुए नायकों का जब किसी बाघ, हाथी या किसी और खतरनाक जानवर से सामना होता है तो वो कहते हैं कि तुम भी जंगल में रहते हो, मैं भी। तुम भी भोजन की तलाश में निकले हो और मैं भी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आश्चर्यजनक रूप से इस समुदाय में जंगली जानवरों के साथ कभी इतनी टेंशन ही नहीं हुई कि आत्मा की आत्मा से टकराहट हो।

लेकिन एक बार अकेले घूमने वाले एक हाथी ने नायक समुदाय के एक व्यक्ति को मार दिया। खबर वन विभाग वालों को मिली तो वे हाथी पकड़ने आए। नायकों ने वन विभाग की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस हाथी ने हमारे आदमी को इसलिए मारा क्योंकि कुछ दिन पहले वन विभाग के लोग उसके साथी को पकड़ ले गए थे। वन विभाग वालों ने हाथी को पकड़ने से पहले बेहोश किया। हाथी ने अपने साथी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और हिंसक हो उठा। नायकों ने पूछा कि यही चीज कोई आपके साथी के साथ करे तो? नायक ही नहीं, पूर्वोत्तर की नगा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया, न्याशी, अंगामी, भूटिया, कुकी, रेंगमा आदिवासी तो पत्थरों में ही नहीं, प्राकृतिक घटनाओं में भी वही आत्मा मौजूद मानते हैं, जो हम सबमें है। सरनावाद तो जंगल का धर्म ही है, जिसे मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उरांव आदि फॉलो करते हैं। लगभग सभी धर्मों में हर चीज में ब्रह्म होने की अवधारणाएं हैं, बस एक लालच नाम के धर्म को छोड़कर। धरती पर ब्रह्म हत्या का कारोबार इसी धर्म को मानने वाले कर रहे हैं। बुआ ने बताया था कि ब्रह्म छोड़ता नहीं है। नायकों को वन विभाग की कारस्तानी भुगतनी पड़ी थी, और बाकी खुद जानें कि उनके सीने में जलन, सांसों में तूफान सा क्यों है।

एकदा

रटवाने वाली शिक्षा

राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जब छपरा से कलकत्ता पढ़ने के लिए जाने लगे, तब हथुआ के स्कूल में उनका नाम लिखवा दिया गया। इस स्कूल में पढ़ाई का तरीका अलग था। बच्चों को पाठ कंठस्थ करने के लिए कहा जाता था और अगले दिन उन्हें सुनाने के लिए मजबूर किया जाता था। राजेंद्र प्रसाद की आदत विषय को पूरी तरह समझे बिना रटने की नहीं थी। इसलिए वह असहज महसूस करने लगे, क्योंकि कक्षा में न सुना पाने पर उनको अपमानित होना पड़ता। ऐसा नहीं था कि वह कोशिश नहीं करते थे। एक दिन तो किसी ने उनसे कहा कि विषय को यदि 120 बार पढ़ा जाए, तो वह याद हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने आधी रात को उठकर वैसा ही किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और अगले दिन इतिहास के अध्यापक के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आखिरकार, वह बीमार पड़ गए। उनके भाई जब कोलकाता से आए, तो उनकी दशा देखकर दुखी हुए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का नाम हथुआ से कटवा कर फिर छपरा में लिखवा दिया। वहां उनके व्यक्तित्व का विकास होने लगा। रटवाने वाले इस स्कूल में अपने छह महीने के जीवन के बारे में वह बहुत दुखी थे, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में दर्ज किया है। वह छपरा के स्कूल और अध्यापकों का बखान करने से नहीं थकते। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आज भी ऐसे अध्यापक हैं जो कक्षा में समझाने के बजाय बच्चों को रटने के लिए कहते हैं। कुछ शिक्षक तो बच्चों को एक उत्तर 15 बार लिखने के लिए कहते हैं। उन्होंने रटवाने वाली शिक्षा के बदले समझाने वाली शिक्षा की पैरवी की है।

संकलन : हरिप्रसाद राय

विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों, महायुति और आघाड़ी के दिग्गजों की साख दांव पर

महाराष्ट्र में होगी 'असली-नकली' की लड़ाई

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। छोटे-मोटे कोई 16 दल मैदान में हैं। इनमें से 6 प्रमुख दल दो गठबंधनों में बंटे हैं, जबकि बाकी 10 छोटे दलों का अपना अलग गठबंधन है। इसे तीसरी आघाड़ी कहा जाता है। इसमें से 7 तो दो बड़े गठबंधनों के साथ हो गए हैं, जबकि बचे 3 ने अपना अलग कुनबा बनाया है, जिसे परिवर्तन महाशक्ति आघाड़ी नाम दिया गया है। चौथा कुनबा भी है, जिसका नाम है वंचित आघाड़ी। भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश इसके नेता हैं। उन्होंने AIMIM के ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महायुति की ओर झुकती नजर आ रही है।

अस्तित्व की लड़ाई | इनमें से प्रमुख दो ही गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति का नेतृत्व BJP के पास है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। विभाजित शिवसेना और NCP के गुट इनके घटक दल हैं। इन दलों और उनके नेताओं के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। असली शिवसेना किसकी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की, या असली NCP अजित पवार की या शरद पवार की, यह भी साबित होना है। BJP के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के नाना पटोले के समक्ष भी अपने को साबित करने की चुनौती है। तीसरी या चौथी आघाड़ी को तो हाजिरी लगाने के लिए चुनाव लड़ना है। कुल वोटिंग में उन्हें एक से 1.5% वोट ही मिलते रहे हैं।

BJP का लक्ष्य | BJP के कोटे में लगभग 150 सीटें आ सकती हैं। पार्टी ने शत प्रतिशत जीत का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब कि इस चुनाव में अधिकाधिक सीटें जीतना और 2029 में अपने बलबूते सरकार बनाने का लक्ष्य। इससे शिवसेना का शिंदे गुट और NCP का अजित पवार गुट चौकन्ना हो गया है।

संघ का साथ | हरियाणा में BJP-संघ के विशाल नेटवर्क ने बाजी पलट दी थी। वोटर्स तक सीधी पहुंच के लिए ऐसा ही नेटवर्क महाराष्ट्र में भी तैयार है। संघ ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अतुल लिमये को जिम्मेदारी सौंपी है।

शिंदे का फायदा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता में होने का लाभ मिलेगा। वह लगभग 70 सीटों पर लड़ सकती है। मंत्रिमंडल की पिछली दो-तीन बैठकों में शिंदे ने जिस गति से फैसले लिए, उससे उनकी छवि चमक चुकी है। अंतिम बैठक में 10 मिनट में ही अजित पवार के उठकर चले जाने से साफ हो गया है कि उनकी कम चलती है। इस बैठक में 150 मिनट में रेवड़ियां बांटने वाले 50 से अधिक फैसलों से लोग चौंक गए। लाड़की बहीण (लाडली बहना) योजना, छोटे किसानों को मुफ्त बिजली, साल में तीन मुफ्त रसोई सिलिंडर, युवकों को अप्रेंटिस सहायता, लड़कियों को छात्रवृत्ति, मुंबई के पांच टोल नाकों पर टोल छूट वगैरह ऐसी रेवड़ियां हैं, जिन पर राज्य का सालाना कोई एक लाख करोड़ रुपये खर्च होगा।

अजित की मुश्किल | अजित पवार की बगावत से मतदाता खुश नहीं दिखते। संघ ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अजित पवार पर फोड़ा है। महायुति में अब उनका दम घुट रहा है, लेकिन शरद पवार ने उनकी वापसी की राह बंद कर दी है। अजित पवार के लिए अपना वजूद बनाए रखने का यही एक अवसर है।

हरियाणा का सबक | लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सर्वाधिक 13 सीटें जीती थीं। लेकिन सारा जोश और आत्मविश्वास हरियाणा में हार के साथ धुल गया। पार्टी को घटक दलों के साथ अधिक तालमेल से पेश आना होगा। गुटबाजी से बचना होगा। उसे शरद पवार जैसे परिपक्व दिग्गज के साथ मिलकर दांव-पेच बनाने होंगे। सही उम्मीदवारों का चयन मुख्य मुद्दा होगा।

उद्धव की कमजोरी | शिवसेना में फूट के बाद ठाकरे सेना में आई मायूसी अब दूर हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने शिंदे सेना से दो सीटें अधिक जीती हैं। उद्धव खुद महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम पद का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने उनकी मांग ठुकरा दी है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में उद्धव सेना का दबदबा है। वहां शिंदे सेना के साथ उनकी सीधी टक्कर हो सकती है।

पवार से आस | आघाड़ी में शरद पवार सबसे अनुभवी रणनीतिकार हैं। वह अपने बलबूते 60 से अधिक सीटें पा सकते हैं। लेकिन, केवल उनके बल पर महाविकास आघाड़ी सत्ता के करीब कितना पहुंच सकती है, यह सवाल है। NCP में फूट पड़ी, तब 41 विधायक अजित पवार अपने साथ ले गए। केवल 12 विधायक ही शरद पवार के साथ बचे थे। उन्होंने फिर से पार्टी संगठित की है। लोकसभा में अजित के मुकाबले उन्हें बहुत अधिक सफलता मिली। इससे अजित गुट के कई लोग अब फिर से शरद पवार के रास्ते पर हैं। उनके पुणे स्थित 'मोदीबाग' बंगले में नेताओं का आना-जाना बढ़ गया है। पाला बदलने के इच्छुक लोगों में अजित गुट, BJP और कांग्रेस के कई नेताओं के भी नाम हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

शरीर के अंदर ही छिपी है ख़ुशियों की केमिस्ट्री

लैब में पहले दिन की शुरुआत टीचर ने यहीं से की, 'बिल्कुल चाय बनाने की तरह है केमिस्ट्री। जिस तरह अच्छी चाय के लिए उसमें सब चीजें बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि कितना उबालना है, उसी तरह का मामला केमिस्ट्री के साथ है।' इसके बाद अगले तीन साल लैब में 'अच्छी चाय' बनाने की कोशिश में ही बीत गए। खैर, केमिस्ट्री केवल लैब तक सीमित नहीं। चाय की तरह उसका भी दायरा बहुत बड़ा है। परखनली से लेकर हमारे शरीर तक, हर जगह है केमिस्ट्री। बल्कि शरीर के भीतर चल रहा रसायनों का गणित कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारा मूड बस हमारे हाथ में नहीं रहा, जब लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है, और जब बाहरी कारण हमारी अंदरूनी सेहत पर ज्यादा असर डाल रहे हैं, तब जरूरी है कि शरीर की केमिस्ट्री को भी समझा जाए। यही सबसे अच्छा तरीका है खुशियों के नंबर बढ़ाने का।

हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने वाले चार हॉर्मोन बेहद अहम हैं- Dopamine, Oxytocin, Serotonin और Endorphins। Dopamine को 'रिवॉर्ड बूस्टर' कहा जाता है। हमें कामयाबी की भावना का अनुभव कराता है यह। इसे बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटिए। हर छोटा लक्ष्य पूरा होगा, तो संतुष्टि और खुशी मिलेगी, Dopamine बढ़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें और टायरोसिन से भरपूर खाना मसलन, पनीर, सोयाबीन वगैरह को डाइट का हिस्सा बनाएं। साथ ही, नींद बहुत जरूरी है इस हॉर्मोन के बैलेंस के लिए, जबकि सोशल मीडिया और जंक फूड उतने ही खराब।

AI Image

जीवन आनंद

एक बहुत ही पुराना वाक्य है और लगभग हर किसी ने पढ़ाई के दौरान कभी न कभी इस पर निबंध जरूर लिखा होगा कि, 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' सामाजिक बनना हमें अच्छा महसूस कराता है और इसके पीछे है Oxytocin (ऑक्सिटोसिन)। इसे बॉन्डिंग हॉर्मोन भी कहा जाता है। इसे बढ़ाने के लिए अपने करीबी रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें। अच्छा वक्त बिताएं, बातचीत करें। संवाद जितना आत्मीय होगा, उतना ही बेहतर। जादू की झप्पी बहुत काम करती है इस हॉर्मोन को बढ़ाने में।

खुशियों का अगला महत्वपूर्ण रसायन है Serotonin (सेरोटोनिन)। यह तनाव, अवसाद से बचाकर हमारे मूड को स्थिर रखता है। सोचिए, इस समय की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन, और इसकी काट Serotonin के लिए चाहिए हर दिन बस थोड़ी-सी धूप। सूरज की रोशनी में कुछ देर रहना काफी है इस हॉर्मोन का बैलेंस ठीक रखने के लिए। साथ में, रेगुलर एक्सरसाइज हो और उसमें भी एरोबिक तो फिर क्या ही बात है।

इस केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है Endorphin (एंडोर्फिन), प्राकृतिक दर्द निवारक। इसे बढ़ाने के लिए हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स मददगार साबित हो सकते हैं। हंसी-मजाक और पसंदीदा गतिविधियों में भाग लेने से भी Endorphin का स्तर बढ़ता है। डार्क चॉकलेट और थोड़ा मसालेदार भोजन भी अच्छा होता है।

इन चारों हॉर्मोन को कहा जाता है DOSE। ये दरअसल डोज हैं खुशियों के। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक हॉर्मोन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की कुर्बानी दे दी जाए। जो भी करें, सकारात्मक सोच के साथ। लैब में केमिकल्स पर हाथ साधना भले ही मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा-सा ध्यान दें तो जीवन की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल नहीं।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

कैसी रही है इस महान अभिनेता की ज़िंदगी

मृत्युंजय राय

यूं तो यह बात दिग्गज अमेरिकी अभिनेता ऐल पचिनो अपने इंटरव्यूज में पहले भी कह चुके हैं कि 'द गॉडफादर' में शुरुआती दौर में फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला उनके काम से इतने नाराज थे कि उन्हें निकालना चाहते थे। लेकिन लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हालात ऐसे थे तो फिर वे बदले कैसे। ऐल पचिनो ने अपने संस्मरण SONNY BOY में इस वाकये से परदा हटाया है और बताया है कि असल में हुआ क्या था। वह लिखते हैं कि एक रोज एक रेस्तरां में कोपोला ने उन्हें बुलाया और कहा कि वह अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। कोपोला की नाराजगी को यूं समझा जा सकता है कि उन्होंने पचिनो को बैठने तक को नहीं कहा।

लेकिन रेस्तरां वाले वाकये के बाद फिल्म का एक सीन सूट हुआ। इस सीन में माइकल कॉर्लियोन का किरदार निभा रहे पचिनो अपने पिता (अमेरिका के महान अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले मार्लन ब्रैंडो ने यह भूमिका अदा की थी) की हत्या की कोशिश करने वाले एक शख्स की जान ले लेते हैं। इसे न सिर्फ 'द गॉडफादर' बल्कि सिनेमा के इतिहास के चुनिंदा शानदार सीन में से एक माना जाता है। इस किताब में पचिनो ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि अभिनय की दुनिया ऐसी है कि कभी आप इसमें गिरते हैं तो कभी आपके सितारे बुलंदी पर होते हैं। पचिनो जैसे महान अभिनेता जब ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं तो इनसे उनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू सामने आता है, जिससे अक्सर फैन्स वाकिफ नहीं हैं।

'Sonny Boy' पचिनो का पुकारू नाम था, इसी वजह से किताब का भी उन्होंने यही नाम रखा है। वह जब 2 साल के थे, तभी उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपनी मां और नाना-नानी के साथ रहे। ऐल ने किताब में अपने बचपन के दोस्तों क्लिफ, ब्रुस और क्लिफी का जिक्र किया है। आगे चलकर उनके इन तीनों दोस्तों की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई। पचिनो लिखते हैं कि उनके घर वाले अगर ध्यान न देते तो शायद वह भी नशे के शिकार हो जाते। हालांकि, अभिनेता के रूप में करियर शुरू होने के बाद शुरुआती दिनों में वह काफी शराब पीते थे। पचिनो ने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद छिटपुट काम करके उन्होंने जीवन चलाया और थिएटर करते रहे। उन्हें बड़ी कामयाबी 70 के दशक में सिनेमा में मिली। गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, सर्पिको, स्कारफेस और डॉग डे आफ्टरनून जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें हॉलिवुड का बड़ा स्टार बना दिया और उनकी अभिनय क्षमता को भी सराहा गया।

विचार विंडो

किताब में वह फिल्मों में निभाए गए चरित्रों के अपने विश्लेषण के बारे में भी बताते हैं। फिर 1980 के दशक में उनकी कुछ फिल्में नाकाम हुईं। पचिनो लिखते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया, जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। वह बताते हैं कि अभिनय छोड़ने से भी उन्हें गुरेज नहीं था, लेकिन तब उनकी पार्टनर डाएन कीटन थीं। दोनों एक साथ रहते थे। कीटन ने उनसे कहा, 'अब तुम पीछे नहीं लौट सकते...तुम लंबे समय तक अमीरों की जिंदगी गुजार चुके हो।' खैर, पचिनो की जिंदगी में गुरबत का वक्त ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन संस्मरणात्मक लेखन में अक्सर जिस ईमानदारी की उम्मीद रहती है, उसे पचिनो पूरा नहीं कर पाए हैं। खासतौर पर उन्होंने इसमें अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लिखा है। खासतौर पर अपने अफेयर्स और रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में। जहां उन्होंने इन लोगों का जिक्र किया है, वहां भी तफसील से उन रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसके बावजूद पचिनो के फैन्स के लिए इस किताब में बहुत कुछ है।

शादी की पेनल्टी क्यों?

प्रणव प्रियदर्शी

साउथ एशियन डिवेलपमेंट से जुड़ी वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने इस धारणा की तथ्यों के आधार पर पुष्टि कर दी है कि भारत जैसे देशों में लड़कियां शादी करने और मां बनने की कीमत अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बलि देकर चुकाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शादी के बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में 12 फीसदी तक की कमी आ जाती है। ऐसी ही स्थिति उनके मां बनने पर भी होती है। रिपोर्ट में यह ट्रेंड इतने स्पष्ट तौर पर उभरता पाया गया कि इसे बाकायदा मैरिज पेनल्टी और मदरहुड पेनल्टी नाम दे दिया दिया गया है। यह स्थिति सीधे तौर पर समाज में पितृसत्तात्मकता के प्रभावों से जुड़ी है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे दक्षिण एशिया में हालात एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर, नेपाल में शादी करने या मां बनने के बाद लेबर फोर्सेज में लड़कियों की भागीदारी में गिरावट इतनी कम है कि जानकार इसे किसी ट्रेंड के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। भारत समेत ज्यादातर देशों में स्थितियां एकदम उलट हैं। चाहे मैरिज पेनल्टी हो या मदरहुड पेनल्टी, सही तो दोनों में से किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाज में आम तौर पर मदरहुड पेनल्टी को ज्यादा आपत्तिजनक नहीं माना जाता। इसके बचाव में यह दलील दी जाती है कि बच्चा चूंकि मां के शरीर से निकलता है, इसलिए कम से कम जन्म के कुछ समय बाद तक उसकी मां पर निर्भरता सबसे ज्यादा होती है। मगर मैरिज पेनल्टी के पक्ष में तो ऐसी कोई थोथी दलील भी नहीं। आखिर शादी के बाद किसी लड़की को पति की देखभाल में अपना पूरा समय क्यों देना चाहिए, खासकर तब, जबकि शादी से पहले पति ही पत्नी समेत अपने पूरे भावी परिवार की देखभाल करने का दावा कर रहा होता है? और बच्चे की देखभाल भी शुरुआत के कुछ हफ्तों से आगे मां की ही संपूर्ण जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं इसे परिवार और समाज के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की साझा जिम्मेदारी के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए?

AI Image

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

इंसान की सबसे बड़ी सफलता है संतुलित जीवन

श्री श्री आनंदमूर्ति

हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। लेकिन जब हम कुछ करते हैं, तो सफलता हमारे हाथों में नहीं होती। यह किसी काम के फल के रूप में आती है। जब हमारा काम सकारात्मक दिशा में होता है तो प्रतिक्रिया भी अच्छी होती है। अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में आया वह परिणाम ही सफलता है।

एक आध्यात्मिक व्यक्ति या साधक जो समाज की सेवा करता है, उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं और वह ठीक हो जाता है, तो वही आपका पुरस्कार है, वही आपकी सफलता है।

संस्कृत में सफलता के लिए तीन अलग-अलग शब्द हैं- प्रातिष्ठा, सर्वजिज्ञासा, सिद्धि)। मनुष्य जीवन के सभी तीन क्षेत्रों में सफलता चाहता है। साधारण व्यक्ति भौतिक स्तर पर सफलता चाहता । एक विकसित, बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक स्तर पर सफलता की तलाश करता है। एक भक्त हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर सिद्धि चाहता है। यदि आपके पास एक ऊंचा लक्ष्य है, पर आप उस दिशा में बढ़ने की मानसिक सहनशक्ति नहीं रखते, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उच्च विचारधारा और सहनशक्ति दोनों आवश्यक हैं।

भगवान शिव ने कहा है, 'फालिष्यति विश्वासः सिद्धिरप्रथमलक्षणम्।' इसका अर्थ है, मुझे अपने मिशन में सफल होना है। यही सफलता का पहला रहस्य है। 'द्वितीयं श्रद्धया युक्तम्।' श्रद्धा का अर्थ है सत्य की वास्तविकता के प्रति मानसिक गति। एक आध्यात्मिक साधक में अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यह सफलता का दूसरा रहस्य है। तीसरा तत्व है गुरु पूजा। एक साधक में अपने गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु वह होता है जो अंधकार को मिटाता है। चौथा तत्व है समता भाव, यानी मन में किसी भी प्रकार की हीनता या अहंकार न हो। जब साधक संतुलित रहता है, तो वह अपने विकास को सही दिशा में बढ़ा सकता है।

पांचवां महत्वपूर्ण कारक है इंद्रिय निग्रह। किसी भी कार्य में आपको अपने व्यवहार पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर के लिए आपको भोजन, हवा, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन शारीरिक भोजन का आध्यात्मिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन आपके भौतिक और मानसिक शरीर को प्रभावित करता है, इसलिए आपको संतुलित और उचित भोजन लेना चाहिए। जब भोजन संतुलित और प्रचुर होता है, तो उसे संस्कृत में प्रमिता आहार कहा जाता है। अत्यधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लंबे समय तक उपवास भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर की क्षमता के अनुसार उपवास एक प्रकार से प्रमिता आहार में शामिल होता है, क्योंकि यह पाचन अंगों को विश्राम देता है।

स्पष्ट है कि सफलता केवल बाहरी पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष और विकास में भी है। एक संतुलित जीवन, जिसमें मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वह सफलता है और हम सभी को इसी की तलाश है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

दोहरे मापदंड वाली राजनीति
आप पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन को 18 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके पहले मनीष सिसोदिया (17 माह), संजय सिंह (6 माह), अरविंद केजरीवाल (177 दिन) जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। दूसरी तरफ ईडी ने कौशल विकास घोटाले (371 करोड़) के आरोपी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। कहावत है कि जो बीजेपी से जुड़ गया, वह तर गया, जो शरण नहीं आया, वह सड़ गया। फेहरिस्त लंबी है, सब जानते हैं। लेकिन देश के लिए दोहरे मापदंड वाली राजनीति कोई शुभ संदेश और संकेत नहीं देती।
– हेमा हरि उपाध्याय, ईमेल से

महंगाई रोकने मैकेनिज्म जरूरी
महंगाई चरम पर है, थोक और खुदरा महंगाई दर भी लगातार बढ़ रही है। सरकार महंगाई को रोकने में विफल रही है। देखा जाए तो त्योहारी सीजन में खाने-पीने की चीजें अक्सर महंगी हो जाती हैं। इसके पीछे जमाखोरी और कालाबाजारी प्रमुख कारण है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। स्थानीय बाजारों में खाने-पीने की चीजें महंगी क्यों बिक रही हैं, इसे जानने की सरकार ने कभी कोशिश ही नहीं की, जबकि फसल उत्पादक किसानों को उचित कीमत भी नहीं मिलती। लागत और लाभ का मैकेनिज्म सरकारी स्तर पर तय नहीं होने से मूल्यों पर नियंत्रण करना कठिन हो गया है। खाद्य महंगाई पर काबू पाना केवल नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक सजगता से ही संभव है।
–अंजनी कुमार दाधीच, ईमेल से

प्रकृति से छेड़छाड़ न करें
प्रकृति से छेड़छाड़ और मौसम में अप्रत्याशित बदलाव खतरे की घंटी है। अब तो बारहों महीने पंखे और एसी की जरूरत होने लगी है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और उसके साथ छेड़छाड़ का नतीजा ही है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। जंगलों का कम होना, ग्लेशियर का पिघलना, घरों में ज्यादा कांच लगाना भी प्रमुख कारण हैं। वृक्षारोपण ही तापमान कम करने में सहायक होगा, साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों के बीच जारी युद्ध पर भी अंकुश होना जरूरी है। गोलीबारी, बम और मिसाइल गिराने से भी तापमान बढ़ता है।
– संजय वर्मा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com
पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबर: बहराइच पर गरमाई राजनीति, अखिलेश बोले- सरकार के काम करने का नया तरीका है एनकाउंटर।
टिप्पणी: पुलिस की पकड़ से अपराधी भाग जाए तो प्रॉब्लम, एनकाउंटर हो तो भी प्रॉब्लम। प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम।
– सुभाष बुड़ावन वाला, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स: (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

सर्वोच्च 'जनता की अदालत'

भारत के लोकतन्त्र में न्यायपालिका की भूमिका को हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार निरुपित किया कि यह सरकार का अंग न होकर स्वतन्त्र रूप से देश में संविधान के शासन की गारंटी करती रहे। आजादी के बाद से हमारी न्यायपालिका यही भूमिका बहुत सफलता के साथ निभा रही है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यह समय-समय पर सरकारी फैसलों की समीक्षा संविधान की भावना के अनुरूप जनहित की रोशनी में करता रहा है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद की भूमिका में आ जाये और उसमें भी विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। न्यायालयों को किसी भी मुद्दे पर जन अवधारणाओं से निरपेक्ष रहते हुए संविधान की रुह के मुताबिक ही फैसला करना होता है। अत: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़ का यह कहना पूरी तरह सामयिक है कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जनता की अदालत के रूप में निर्दिष्ट रहनी चाहिए और इसका यह स्वरूप भविष्य के लिए भी संरक्षित रहना चाहिए। सामान्य नागरिक के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं और उसे न्याय मिलता है, यह अवधारणा भी स्थायी रहनी चाहिए जिसे विकसित करने में पिछले 75 साल लगे हैं। इस दिशा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को केवल इसके फैसलों के आधार पर नहीं परखा जा सकता बल्कि उसके काम के आधार पर ही परखा जा सकता है। क्योंकि अदालत में न्यायाधीश प्रत्येक मुकदमे का फैसला गुण-दोष के आधार पर करते हैं और जिस तरफ भी पलड़ा झुकता है वही फैसले में तब्दील होता है। इसके बावजूद न्यायालयों के फैसले की आलोचना की जा सकती है मगर दिक्कत तब आती है जब कुछ लोग फैसला उनके पक्ष में आने पर सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि न्यायालय एक विशेष दिशा की तरफ जा रहा है मगर जब फैसला उनके विरुद्ध आता है तो वे लोग ही न्यायालय की बखियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं।

श्री चन्द्रचूड़ के मतानुसार समाज बदलता रहता है और इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। इसमें समृद्धि आती रहती है अत: सर्वोच्च न्यायालय को केवल बड़े दर्जे के मुकदमों पर ही निगाह नहीं रखनी चाहिए बल्कि सामान्य समझे जाने वाले मामलों पर भी निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे न्यायालय जनता के न्यायालय हैं। अत: इसका यह स्वरूप बरकरार रहना चाहिए। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने ये उद्गार प्रकट करके साफ कर दिया है कि लोकतन्त्र में कोई भी संवैधानिक संस्थान अभिजात्य नहीं होता विशेषकर न्यायपालिका, क्योंकि इसे अन्तत: जनता के हितों की रक्षा ही करनी होती है परन्तु न्यायपालिका संसद में विपक्ष की तरह की भूमिका में कभी नहीं आ सकती। अत: जब फैसला किसी के पक्ष में आता है तो कुछ लोग न्यायपालिका की तारीफ करने लगते हैं और जब उनकी अपेक्षाओं के विरुद्ध आता है तो वे ही लोग उसकी कटु आलोचना करने लगते हैं। समाज में इस तरह के विभाजन को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि न्यायालय को अपना फैसला विधि के अनुसार ही करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को केवल इसके फैसलों के आधार पर नहीं परखा जा सकता बल्कि उसके काम के आधार पर ही परखा जा सकता है। क्योंकि अदालत में न्यायाधीश प्रत्येक मुकदमे का फैसला गुण-दोष के आधार पर करते हैं और जिस तरफ भी पलड़ा झुकता है वही फैसले में तब्दील होता है। इसके बावजूद न्यायालयों के फैसले की आलोचना की जा सकती है मगर दिक्कत तब आती है जब कुछ लोग फैसला उनके पक्ष में आने पर सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि न्यायालय एक विशेष दिशा की तरफ जा रहा है मगर जब फैसला उनके विरुद्ध आता है तो वे लोग ही न्यायालय की बखियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। किसी भी मुकदमे का फैसला न्यायाधीश पूरी तरह स्वतन्त्र रहते हुए देते हैं जिसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। उनका फैसला किसी के पक्ष में या विरुद्ध आ सकता है। सारे फैसले कानूनी स्थिति को देख कर ही होते हैं। अत: जब इस शर्त को लागू करते हुए हम फैसलों की समीक्षा करेंगे तो न्यायपालिका की भूमिका का सही आंकलन करेंगे और इसके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे।

न्यायालय अपने समक्ष पेश किये गये तथ्यों के अनुसार ही कानून दायरे में फैसला सुनाते हैं फिर यह फैसला किसी भी पक्ष की तरफ हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही सीधे टीवी चैनल पर दिखाये जाने पक्ष में अपना मत प्रकट किया है। उनका कहना है कि अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से आम लोगों को पता चलेगा कि यह किस तरह काम करती है। इससे आम जनता कानूनी दांव-पेंचों और इन्हें खेलने वाले वकीलों व न्यायाधीशों के बारे में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होगी क्योंकि अब यह मसला अदालत के कमरे में कुछ वकीलों व जज के बीच का नहीं रहा है बल्कि पूरे नजारे से टीवी चैनल के दो करोड़ उपभोक्ता भी वाकिफ होंगे। इससे समाज में अदालतों व कानून के बारे में नई चेतना जागृत होगी। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को समाज में हो रहे परिवर्तनों के प्रति भी संवेदनशील रहना होगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल विवाद निपटाने की सबसे ऊंची संस्था ही नहीं है बल्कि इसे समाज में हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनशील रहते हुए फैसले करने होंगे जिससे समूचे राष्ट्र को दिशा मिल सके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों जैसी नहीं है बल्कि न्याय पाने की उच्चतम सीढ़ी जैसी है। अत: जब भी सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य जन के मुकदमे पर कोई फैसला दिया जाता है तो वह राष्ट्रीय स्तर सभी निचली अदालतों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है जिससे पूरे देश में आ रहे सामाजिक बदलाव से उपजी समस्याओं का निदान हो सके और समाज विकसित होता रहे। श्री चन्द्रचूड़ के इस बयान से साफ है कि वह बदलते सामाजिक समीकरणों को भी अदालतों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। इसलिए आम भारतवासी को न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने दिशा दिखाने का काम किया है। ऐसा मानना संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का भी था जिन्होंने संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतन्त्र व निरपेक्ष रहने का किरदार दिया।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

काश अपनी इच्छा से हेलमेट लगाते

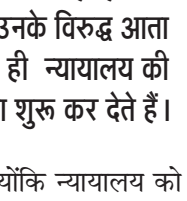

गीता पाढा

"काश! हम पुलिस के डर से नहीं अपनी इच्छा से हेलमेट लगाते,
तो कितने युवा यूं न सड़क हादसों में अपना जीवन गंवाते,,
बेवजह न लाल बत्ती पर भी बार-बार हौरन बजाते,
काश! यातायात के नियम हम केवल पढ़ते नहीं, बल्कि अपने जीवन में आत्मसात कर पाते...।।"

भारत-पाक: खिड़कियां तो खोलनी होंगी

डा. चन्द्र त्रिखा

chandertrikha@gmail.com

भारत व पाक के बीच लम्बी खामोशी के बाद एक खिड़की थोड़ी सी खुली है। संभावना है कि इस छोटी सी खिड़की के माध्यम से ताजा हवा के कुछ झोंके आ सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री और पाक प्रधानमंत्री के मध्य बातचीत के समय वहां के क्रिकेट बोर्ड के एक उच्चाधिकारी का चले आना महज कोई संयोग नहीं था। 'सिंगल-रन' की मशक्कत हुई है तो चौके-छक्के भी जड़े जा सकते हैं। वैसे भी आगामी फरवरी में चैम्पियन-ट्राफी में दोनों देशों की टीमों के आमने-सामने होने की संभावनाएं कायम हैं।

दरअसल यह भी एक हकीकत है कि जब से दोनों देशों के बीच व्यापार ठप्प हुआ है, तब से हमारा यह पड़ौसी भी संकट में है और मजा हमें भी नहीं आ रहा। श्रीकरतारपुर साहब-गलियारे के बाद उम्मीद थी कि कटासराज, श्री ननकाना साहब और सिंध वाली हिंगलाज माता के गलियारे भी खुल जाएंगे। मगर बात सिर्फ कुछ अरदासों तक सीमित रह गई।

दोनों देशों के सामान्य जन तो सहमत हैं कि 77 वर्ष पूर्व वाले विभाजन का बेताल अब तक हमारे कंधों से नहीं उतर पाया। कभी लाहौर की दरगाहों, गुरुद्वारों के बहाने तो कभी पुरानी दिल्ली की चंद संकरी हवेलियों के हवाले से या अजमेर शरीफ की दरगाह के बहाने पुरानी यादें चहकने लगती हैं। लाहौर का अलहमरा थियेटर अब भी उसी तर्ज पर चलता है, जिस तर्ज पर चंडीगढ़ टैगोर थियेटर या दिल्ली का 'त्रिवेणी' या 'कमानी' ओडिटोरियम चलते हैं। कभी अमृता के बहाने, कभी मंटो के बहाने तो कभी इकबाल, फैज़, गालिब के बहानों से बातें चल निकलती हैं। सरायकी व ठुमरी भी अक्सर कहरवा बजाने लगती हैं।

इन ताज़ा हवाओं के रास्ते में बांधा है तो सिर्फ चंद आतंकी संगठन, जिन्हें भारत बर्दाश्त नहीं करता और पाकिस्तानी आवाम भी उन्हें निरा सरदर्द मानते हैं। उनसे मुक्ति पाना पाकिस्तानी शासकों के लिए आसान न होने के बावजूद बेहद ज़रूरी है।

यह भी एक हकीकत है कि खिड़कियां जब भी खुलेंगी, किताबों व क्रिकेट के बहाने खुलेंगी। जयपुर का 'लिट फैस्ट', कसौली का 'खुशवंत सिंह फेस्टिवल' या चंडीगढ़ का 'लिट फैस्ट' ऐसे खूबसूरत बहाने हैं जिनके माध्यम से 'बंद अलमारी के शीशों से झांकने वाली किताबों' को भी 'सुकून' मिलेगा। इन किताबों का ब्यौरा जानने के लिए आपके 'गुलज़ार साहब' के घर तक दस्तक देनी होगी। उनकी एक लोकप्रिय नज़्म है-

'किताबें, झांकती हैं/
बंद अलमारी के शीशों से/'

वैसे भी यह सुकून भरी बात है कि पहली बार इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन के अपने भाषण में कश्मीर का राग नहीं अलापा। इस बात को लेकर उनके देश में हाय तौबा तो मची है, मगर उसका लाभ यह हुआ कि उसी मंच पर मौजूद भारतीय विदेश मंत्री को भी कश्मीर के बारे में भारतीय स्टेंड दोहराने की जरूरत महसूस नहीं हुई फिर भी श्री जयशंकर ने यह तो स्पष्ट कर ही दिया 'घात' और 'बात' या छुरे-छर्रे और संवाद साथ-साथ नहीं चल सकते।

इधर, एक नया सुखद बहाना भी उभरा है। पंजाब विश्वविद्यालय इन दिनों अपना 142वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका मूल लाहौर में है, जबकि 1947 में वहां से उखड़ने, उजड़ने के बाद एक विश्वविद्यालय (उसी नाम से) पहले सोलन व बाद में चंडीगढ़ में स्थापित हो गया।

पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की स्थापना वर्ष 142 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत-विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में इसकी स्थापना 'ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी' के नाम से सोलन (हिमाचल) के छावनी क्षेत्र में की गई थी। बाद में इसे चंडीगढ़ लाया गया और वही पुराना नाम 'पंजाब यूनिवर्सिटी' ही बहाल कर दिया गया। इसके वर्तमान स्वरूप का परिसर सेक्टर-14 व सेक्टर-25 में स्थापित किया गया है और पूरा परिसर लगभग 550 एकड़ भूमि में फैला है। इसमें 75 विषयों के अध्ययन-विभाग हैं और पंजाब के आठ जिलों के लगभग 201 महाविद्यालय इससे जुड़े हुए रहे। इन विषयों में शोध के भी प्रावधान हैं। यह बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि शुरुआती दौर में विभाजन के लिए गठित परिषद (पार्टीशन काउंसिल) ने विभाजन की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। दलील यह दी गई कि जब तक संस्थान के लिए अपना निजी विशाल परिसर भी नहीं हो, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। उसके लिए विश्वविद्यालय-प्रशासन ने विकल्प के रूप में होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर और दिल्ली में सभी विषयों के क्षेत्रीय शिक्षण विभाग खोले गए। वर्ष 1950 में यह विश्वविद्यालय, ला-कार्बूजिए और पियरे जैनरे के बनाए डिजाइन पर नवनिर्मित परिसर में स्थापित हो गया। इसका मुख्य परिसर 550 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें अत्याधुनिक केन्द्रीय पुस्तकालय, 19 छात्रावास (8 छात्रों के लिए और 11 छात्राओं के लिए) और साथ ही सेक्टर-25 में दक्षिणी परिसर भी है। इसका पूरा ढांचा ही अद्भुत है और इसकी अपनी डिस्पेंसरी व स्टाफ के लिए आवास भी बने हुए हैं। उत्तर भारत का यह एक विलक्षण शिक्षक संस्थान माना जाता है। इसका गांधी-भवन निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। इधर, लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ में नियमित रूप में 1006 प्राध्यापक हैं और 300 अंशकालीन हैं। यूनिवर्सिटी कैम्पस में 45678 छात्र प्रात:कालीन व 16552 छात्र-छात्राएं सांध्यकालीन कक्षाओं में शिक्षारत हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न कॉलेजों के तीन लाख 63 हज़ार 416 छात्र भी इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसका वर्तमान कैम्पस, जिसे कायदे आज़म-कैम्पस भी कहा जाता है, कैनाल रोड़ पर स्थित है। ब्रिटिश काल में इसके गुजरांवाला, जेहलम व खानपुर में भी कैम्पस थे। शिमला में इसी विश्वविद्यालय का उच्चशिक्षा केंद्र अक्तूबर 1882में स्थापित किया गया। लेकिन अब स्थितियां और भी बदल चुकी हैं। नए-नए केंद्र खुल गए हैं। अल्लामा इकबाल के नाम से भी 1800 एकड़ में एक कैम्पस स्थापित हो चुका है।

क्या विकास के पैसे सही दिशा में खर्च होते हैं ?

विनीत नारायण

www.vineetnarain.net

बन्जर भूमि, मरूभूमि व सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंन्द्र सरकार हजारों करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारों को देती आई है। जिले के अधिकारी और नेता मिली भगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े प्रान्त सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेज दिये जाते हैं पर इस विषय के जानकारों को कागजी आंकड़ों से गुमराह नहीं किया जा सकता। आज हम उपग्रह कैमरे से हर राज्य की जमीन का चित्र देख कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहां-जहां सूखी जमीन को हरी करने के दावे किये गये, वो सब कितने सच्चे हैं। दरअसल यह कोई नई बात नहीं है। विकास योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपया इसी तरह वर्षों से प्रान्तीय सरकारों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह जुमला अब पुराना पड़ गया कि केन्द्र के भेजे एक रुपये में से केवल 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सूचना का अधिकार कानून भी जनता को यह नहीं बता पायेगा कि उसके इर्द-गिर्द की एक गज जमीन पर, पिछले 70 वर्षों में कितने करोड़ रुपये का विकास किया जा चुका है। सड़क निर्माण हो या सीवर, पौधारोपण हो या कुण्डों की खुदाई, नलकूपों की योजना हो या बाढ़ नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा का अभियान की अरबों-खरबों रुपया कागजों पर खर्च हो चुका है। पर देश के हालात कछुए की गति से भी नहीं सुधर रहे। जनता दो वख्त की रोटी के लिए जूझ रही है और नौकरशाही, नेता व माफिया हजारो गुना तरक्की कर चुके हैं, जो भी इस क्लब का सदस्य बनता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल व अदालतें उसका बाल भी बाकां नहीं कर पाते। जिले में योजना बनाने वाले सरकारी कर्मी योजना इस दृष्टि से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और कमीशन तगड़ा मिल जाये। इन्हें हर दल के स्थानीय विधायकों और सांसदों का संरक्षण मिलता है, इसलिए यह नेता आए दिन बड़ी- बड़ी योजनाओं की अखबारों में घोषणा करते रहते हैं, अगर इनकी घोषित योजनाओं की लागत और मौके पर हुए काम की जांच करवा ली जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा। यह काम मीडिया को करना चाहिए था। अफ़सरों और निर्माण कम्पनियों का भांडा तब फूटता है जब लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद अरबों रुपए की लागत से बने राजमार्ग या एक्सप्रेस-वे गुणवत्ता की कमी के चलते या तो धंस जाते हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी धांधली केवल सड़क मार्गों पर ही होती है। ऐसा भी देखने को मिला है जब रेल की पटरियां भी धंस गई और रेल दुर्घटना हुई।

उधर जिले से लेकर प्रान्त तक और प्रान्त से लेकर केन्द्र तक प्रोफेशनल कन्सलटेन्ट का एक बड़ा तन्त्र खड़ा हो गया है। यह कन्सलटेन्ट सरकार से अपनी औकात से दस गुनी फीस वसूलते है और उसमें से 90 फीसदी तक काम देने वाले अफसरों और नेताओं को पीछे से कमीशन मे लौटा देते हैं। बिना क्षेत्र का सर्वेक्षण किये, बिना स्थानीय अपेक्षाओं को जाने, बिना प्रोजैक्ट की सफलता का मूल्यांकन किये केवल ख़ानापूर्ति के लिए डीपीआर (विस्तृत कार्य योजना) बना देते हैं। फिर चाहे जे.एन.आर.यू.एम. हो या मनरेगा, पर्यटन विभाग की डीपीआर हो या ग्रामीण विकास की सबमें फ़र्ज़ीवाड़े का प्रतिशत काफी ऊंचा रहता है। यही वजह है कि योजनाएं खूब बनती हैं, पैसा भी खूब आता है, पर हालात नहीं सुधरते। आज की सूचना क्रान्ति के दौर में ऐसी चोरी पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। उपग्रह सर्वेक्षणों से हर परियोजना के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखी जा सकती है और काफी हदतक चोरी पकड़ी जा सकती है पर चोरी पकड़ने का काम नौकरशाही का कोई सदस्य करेगा तो अनेक कारणों से सच्चाई छिपा देगा। निगरानी का यही काम देशभर में अगर प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों या व्यक्तियों से करवाया जाये तो चोरी रोकने में पूरी नहीं तो काफी सफलता मिलेगी। ग्रामीण विकास के मंत्री ही नहीं बल्कि हर मंत्री को तकनीकी क्रान्ति की मदद लेनी चाहिए। योजना बनाने में आपाधापी को रोकने के लिए सरल तरीका है कि जिलाधिकारी अपनी योजनाएं वेबसाइट पर डाल दें और उनपर जिले की जनता से 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव दर्ज करने को कहें। जनता के सही सुझावों पर अमल किया जाये। केवल सार्थक, उपयोगी और ठोस योजनाएं ही केन्द्र सरकार व राज्य को भेजी जाये। योजनाओं के क्रियान्वयन की साप्ताहिक प्रगति के चित्र भी वेबसाइट पर डाले जायें, जिससे उसकी कमियां जागरूक नागरिक उजागर कर सकें। इससे आम जनता के बीच इन योजनाओं पर हर स्तर पर नजर रखने में मदद मिलेगी और अपना लोकतन्त्र मजबूत होगा। फिर बाबा रामदेव या अन्ना हजारे जैसे लोगों को सरकारों के विरुद्ध जनता को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर सरकार की विश्वसनीयता, चाहें वो केन्द्र की हो या प्रान्तों की, जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है और अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़ जायेगी। देश और प्रान्त की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देशभर में जिस भी अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठन ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो, उसकी सूचना जनता के बीच, सरकारी पहल पर, बार-बार प्रसारित की जाये। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्विक शक्तियां बढ़ेंगी और देश का सही विकास होगा। अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लक्ष्य पूर्ति के साथ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन घोषणाओं के चलते किए गए ये दावे गुणवत्ता के पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं? चूंकि ऐसी योजनाओं में भ्रष्टाचार तो अपने पांव पसारता ही है? ऐसे में जनहित का दावा करने वाले नेता क्या वास्तव में जनहित करे पाएंगे?

घरेलू रोबोट विकसित किये जाने में अभी लग सकता है लंबा समय

हाल ही में टेस्ला की प्रदर्शनी में चलते-फिरते, बोलते-नाचते 'ऑप्टिमस' रोबोट ने काफी उत्साह पैदा किया था। लेकिन लोगों का उत्साह तब ठंडा पड़ गया जब यह जाहिर हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था, वह वास्तव में मानव द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा रहा था। भले ही यह अब भी भविष्य की एक आकर्षक झलक हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रोबोट उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं।

उदाहरण के लिए, 'सोफिया' को ही लें, जिसे 2016 में टेक्सास स्थित हैनसन रोबोटिक्स ने बनाया था। कंपनी ने उसे अनिवार्य रूप से एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे कई तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे उस समय हमारी क्षमताओं से परे बताया था। इसी तरह हमने बोस्टन डायनेमिक्स के 'एटलस' जिमनास्टिक्स, ब्रिटेन निर्मित अमेका रोबोट ''वेकिंग अप'' और हाल ही में टेस्ला के 'ऑप्टिमस' के सावधानीपूर्वक तैयार किये गए वीडियो देखे हैं। जाहिर है कि ये अभी अलग-अलग तरीकों से प्रभावशाली हैं, लेकिन वे पूर्ण 'पैकेज' के करीब नहीं पहुंचे हैं। ऑप्टिमस या एटलस को किसी गैर पूर्व निर्धारत स्थान पर छोड़ दें और आप बहुत कुछ अलग देखेंगे।

हमारे घरों में काम करने में सक्षम एक मानव रोबोट को कई अलग-अलग कार्य करने, हमारे उपकरणों का उपयोग करने, हमारे वातावरण में गतिविधियां करने और मानव की तरह हमसे संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह केवल एक या दो साल में सच हो सकता है, तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है।

परदे के पीछे : टेस्ला की प्रदर्शनी की ''विजार्ड ऑफ ओज़'' रिमोट ऑपरेशन तकनीक इस क्षेत्र में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नियंत्रण विधि है, जो शोधकर्ताओं को एक मानक देती है जिसके आधार पर वे अपनी वास्तविक प्रगति का परीक्षण कर सकते हैं। टेलीमेट्रिक्स नियंत्रण के रूप में जाना जाने वाला यह कुछ समय से मौजूद है, और अधिक उन्नत होता जा रहा है। इस लेख को लिखने वालों में से एक, कार्ल स्ट्रैथर्न, इस साल की शुरुआत में जापान में एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। वहां शीर्ष रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं में से एक के मुख्य वक्ता ने एक उन्नत टेलीमेट्रिक्स प्रणाली का

प्रदर्शन किया। स्पष्ट रूप से, यह बहुत उपयोगी तकनीक है। टेलीमेट्रिक प्रणाली का उपयोग खतरनाक वातावरण, दिव्यांगता स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष में काम करने वाले रोबोट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मामले में मानव के अब भी शीर्ष पर होने का कारण यह है कि एटलस जैसे सबसे उन्नत मानवीकृत रोबोट भी अभी तक वास्तविक दुनिया में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं है।

एक और बड़ी समस्या सामाजिक एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) है। डीपमाइंड के जेमिनी और ओपनएआई के जीपीटी-4 विजन जैसे अग्रणी जेनरेटिव एआई कार्यक्रम भविष्य में मानवीकृत रोबोट के लिए रचनात्मक स्वायत्त एआई प्रणाली की नींव रख सकते हैं। लेकिन हमें यह विश्वास करके गुमराह नहीं होना चाहिए कि ऐसे मॉडल का मतलब है कि रोबोट अब वास्तविक दुनिया में अच्छी तरह से काम करने में सक्षम है।

डेटा की कमी : दूसरी मुख्य चुनौती एआई प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया के डेटा की कमी है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा हमेशा हमारे रोबोट को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक वास्तविक दुनिया की स्थितियों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमें अभी तक इस वास्तविक दुनिया के डेटा को पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं मिला है, ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। हालांकि, अगर हम इसे एलेक्सा और मेटा रे-बैन जैसी तकनीकों से जोड़ सकें तो यह स्थिति जल्द ही बदल सकती है। फिर भी, वास्तविकता यह है कि हम उन्नत सामाजिक एआई के साथ मल्टीमॉडल मानवीकृत रोबोट विकसित करने से शायद दशकों दूर हैं जो घर के कामकाज में मदद करने में सक्षम हों। हो सकता है कि इस बीच हमें दूर से नियंत्रित किये जाने वाले रोबोट की पेशकश की जाए। लेकिन क्या हम उन्हें चाहेंगे? इस बीच, यह भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रयासों को उन भूमिकाओं के लिए रोबोट निर्मित करने पर केंद्रित करें जो उन लोगों की सहायता कर सके जिन्हें अभी तत्काल मदद की आवश्यकता है। इनमें स्वास्थ्य सेवा शामिल की जा सकती है, जहां मरीजों की प्रतीक्षा सूची लंबी है और अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है। शिक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है, जहां अशक्त बच्चों को कक्षाओं में दूरस्थ माध्यम से शामिल किया जा सकता है। हमें बेहतर पारदर्शिता, कानून और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परीक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि हर कोई तथ्य को कल्पना से अलग कर सके और जब रोबोट अंतत: विकसित हो जाएंगे, तो लोगों का विश्वास बनाने में मदद मिलेगी। **(द कन्वरसेशन)**

'डिजिटल इंडिया' दुनिया के लिए मिसाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारत आए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने देश की 'डिजिटल क्रांति' की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में 'डिजिटल क्रांति' ने लोगों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है। प्रोफेसर रोमर ने भारत के हर कोने में 'डिजिटल क्रांति' को आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की 'डिजिटल क्रांति' की कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। 'डिजिटल इंडिया' को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना और डिजिटल साक्षरता में सुधार करना था। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है - प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936 सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

डेंगू और हवा

बदलते मौसम के साथ मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज इलाज लाभ ले रहे हैं। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि सरकार के पास दर्ज मामलों से कहीं अधिक लोग बीमार हैं। साफ-सुथरा कहलाने वाले एनडीएमसी क्षेत्र में भी मच्छरों का प्रकोप सोचने पर मजबूर करता है। पूरे देश का अनुमान कुछ बड़े शहरों को देखकर लगाया जा सकता है। बेंगलुरु जैसा शहर भी परेशान है। केरल में सर्वाधिक मामले हैं और मरने वालों की संख्या भी वहां ज्यादा है। डेंगू के मामले मुंबई को भी चिंतित कर रहे हैं और कोलकाता में भी चिंता है। वैसे, यह जाते मानसून और सूखते पानी का मौसम है, तो मच्छरों की संख्या का बढ़ना स्वाभाविक है, अतः जहां भी प्रकोप अधिक है, वहां प्रशासन को ज्यादा मुस्तैदी से बचाव के कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? पंचकुला और उसके आसपास के शहरों में तो 1,800 से ज्यादा डेंगू मरीज हैं, यहां तक कि स्थानीय अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। क्या देश में बाकी जगहों पर भी स्थानीय प्रशासन तभी जागेगा, जब अदालतों की फटकार पड़ेगी?

ऐसा नहीं है कि डेंगू से केवल उत्तर या दक्षिण भारत ही ज्यादा परेशान है। मणिपुर के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मणिपुर में डेंगू के मामलों में बहुत वृद्धि देखी गई है। वहां लगभग दो हजार लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं और चार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ भी चिंतित है और पटना भी। वैसे यह गौर करने की बात है कि पिछले वर्ष ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में आए थे, लेकिन इस बार क्या इन राज्यों में मामले ढंग से दर्ज नहीं हो रहे हैं? आंकड़ों और अस्पतालों में वास्तविक निगरानी की जरूरत है। डेंगू या मच्छर जनित अन्य बीमारियां छिपाने का विषय नहीं हैं। पूरी दुनिया में प्रकोप देखा जा रहा है। पिछले दो दशकों में इस बीमारी से चीन भी बहुत परेशान है। यह बीमारी लोगों की उत्पादकता को प्रभावित कर रही है और सुधार में लंबा समय ले रही है। अगर पूरी दुनिया की बात करें, तो 40 प्रतिशत आबादी पर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। प्रतिवर्ष करीब 40 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं और 21,000 लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। वैसे, चीन के पास साल 2005 से ही डेंगू का विस्तृत रिकॉर्ड है, क्या भारत के पास भी पूरा रिकॉर्ड है? किसी बीमारी से लड़ने के लिए उसके पुख्ता आंकड़ों का होना सबसे जरूरी है। आंकड़े ही इशारा करते हैं कि अगर किसी इलाके में ज्यादा प्रकोप हो रहा है, तो समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं।

डेंगू के मरीज इतने हो गए हैं कि अदालत को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या सभी मामले दर्ज हो रहे हैं? ऐसे में भी क्या हम बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सजग हैं?

दुर्भाग्य, अपने यहां अदालतों को बोलना पड़ रहा है कि बारिश में उग आई घास को साफ कीजिए, जल भराव को तत्काल दूर कीजिए, गंदगी को बिना समय गंवाए ठिकाने लगाइए। सफाई रखने का रास्ता सबसे आसान है। मच्छरों की आबादी जब बढ़ती है, तब उसे नियंत्रित करना कतई आसान नहीं होता। कितनी ईमानदारी से कीटनाशकों का छिड़काव होता है, क्या इसका अध्ययन हुआ है? क्या कीटनाशकों की गुणवत्ता का सही अध्ययन मौजूद है? एक नजर प्रदूषण पर भी फेरिए। पराली जलने से प्रदूषण की मात्रा और बढ़ गई है। हवा ज्यादा जहरीली हो चली है। मरीजों को बीमारियों से लड़ने में भी परेशानी हो रही है। साफ हवा बीमारियों से लड़ने का बल देती है। वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं कि हवा साफ कीजिए, वरना रोग बढ़ते चले जाएंगे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 अक्तूबर, 1949

विश्व-राजनीति और भारत

न्यूयॉर्क, २० अक्तूबर। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल रात वाल्डर्फ-एस्टोरिया होटल में अपने सम्मान में आयोजित एक प्रीति-भोज में भाषण करते हुए भारत और अमरीका में घनिष्ठतर सम्बन्ध की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा- ''अब वह समय आ गया है जब भारत और अमरीका को एक-दूसरे की कठिनाइयों को समझते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में परस्पर सहयोग करना चाहिए। जब तक भारत एक दास राष्ट्र था, तब तक तो उसके लिए अमरीका जैसे महान राष्ट्र के साथ सहयोग करना सम्भव नहीं था, किन्तु अब वह स्वतंत्र हो गया है और अमरीका के साथ पूरा सहयोग करने की स्थिति में है। अब हम अलग-थलग नहीं रह सकते और न भारत केवल छोटी-मोटी भूमिका में बन्द रह सकता है।''

नेहरू जी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से भय की भावना को निकाल फेंकने पर भी जोर दिया और बताया कि महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को अभय रहने का अमर मंत्र दिया है। प्रीति-भोज में २००० से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। होटल का कोना-कोना भरा हुआ था, यद्यपि वहां प्रतिव्यक्ति के भोजन का व्यय लगभग ६० रुपये पड़ता है। यह घोषणा करते हुए कि भारत और अमरीका को एक-दूसरे को दिन पर दिन अधिक समझने की चेष्टा करनी चाहिए, नेहरू जी ने कहा कि अमरीकी जनता के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्पर्क ने मुझमें एक भावुकतापूर्ण चेतना भर दी है और उससे मेरा अमरीका-संबंधी समस्त पूर्व ज्ञान आच्छन्न हो गया है।

भाषण आरम्भ करने से पूर्व और समाप्त करने पर भी नेहरू जी के लिए इतनी तीव्र हर्ष-ध्वनि की गई कि उनका हृदय गद्‌गद् हो उठा। उन्होंने कहा- ''पिछले आठ दिनों में मेरे जीवन के लिए बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। अनुभूतियां और भावनाएं इस प्रकार एक पर एक होती गई हैं कि मुझे ऐसा लगता है मानो मैं यहां बहुत दिनों से हूं। इन आठ दिनों का मुझ पर केवल गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ा है बल्कि एक ऐसी गहरी छाप पड़ी है, जिसे मैं बहुत दिनों तक संजोये रखूंगा।'' नेहरू जी ने कहा कि मैं भारत पहले की अपेक्षा अधिक धनवान होकर लौटूंगा- अनुभव में धनवान और इस महान देश की जनता को समझ सकने की शक्ति में धनवान।

चुनावी मैदान में मशीनी झूठ बेलगाम

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इन दिनों हर तरफ एआई के झूठ की ही चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ अब भी पहले नंबर पर हैं। उन्हें झूठ बोलने की मशीन कहा भी जाता है।

यहां स्कैन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव का दौर झूठ बोलने का मौसम होता है। चुनाव में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, तो झूठ ही उनका असली सच बन जाता है। यह वह मौसम है, जब सभी लोकतांत्रिक देशों में सच पर परदा डालने की परंपराएं उत्सवपूर्वक निभाई जाती हैं। भारत में इसकी बहार तो हम अक्सर देखते रहते हैं, इन दिनों अमेरिकी चुनाव में जो हो रहा है, उससे भारत समेत दुनिया के तमाम देश बहुत कुछ सीख सकते हैं।

वैसे, इस बात की आशंका बहुत पहले से थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला चुनाव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे ही लड़ा जाएगा। झूठ का उत्पादन भी इसी से होगा और उसके भंडाफोड़ का जरिया भी यही बनेगा। यही हो भी रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। एआई को चुनावी झूठ तैयार करने की मशीन बना दिया गया है। जब तक आप पिछले झूठ का सच जान पाते हैं, आपके सामने तब तक सौ नए झूठ आ चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एआई इस काम को इतनी प्रामाणिकता से अंजाम देता है कि लोग सच और झूठ में अक्सर फर्क ही नहीं कर पाते।

इस बार के चुनाव में राष्ट्रपति पद की एक प्रमुख दावेदार कमला हैरिस महिला हैं। महिलाओं को लेकर झूठ बोलना और उनका चरित्र-हनन करना बहुत आसान होता है। अगर आप किसी जहीन महिला को मूर्ख साबित करने की कोशिश करें, तो उसे सही मानने वाले या उस पर चुटकी लेने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। अमेरिका में इन दिनों इस सबके लिए एआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है।

पिछले दिनों एआई से तैयार कमला हैरिस का एक ऐसा वीडियो जारी हुआ, जिसमें वह एक सभा में बेसिर-पैर की बातें कर रही हैं। यह वीडियो इतने अच्छे ढंग से तैयार किया गया था कि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। बहुत से लोग इसके झांसे में आ गए। झांसे में आने वाले इन लोगों में अमेरिका के ख्यात उद्योगपति एलन मस्क भी थे, जिन्होंने इसे सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर भी किया। एलन मस्क एक्स के मालिक भी हैं और उन्होंने इसे उस समय शेयर किया, जब यह कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया को चुनावी झूठ से आम लोगों को बचाना चाहिए। प्रसंगवश यहां इसका जिक्र कर देना जरूरी है कि एलन मस्क कमला हैरिस के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं।

बात सिर्फ इतनी नहीं है। सोशल मीडिया पर आपको कमला हैरिस की बहुत सी ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी, जो नितांत आपत्तिजनक हैं और सब की सब एआई से तैयार की गई हैं। हालांकि, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि हैरिस समर्थक उनके खिलाफ तरह-तरह की सामग्री तैयार करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है। चुनावी झूठ की ताली अक्सर एक हाथ से नहीं बजा करती।

इन सबका यह अर्थ नहीं है कि अमेरिकी चुनाव में इन दिनों हर तरफ एआई के झूठ की ही चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ अब भी पहले नंबर पर हैं। उन्हें झूठ बोलने की मशीन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए तो उन्होंने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अमेरिकी अखबार *वाशिंगटन पोस्ट* ने तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठों का बाकायदा ऑडिट ही कर डाला है। अखबार के अनुसार, अपने चार साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 ऐसी बातें कहीं, जो या तो झूठी थीं या फिर भ्रामक। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 21 झूठ। काश, कोई ऐसा ही ऑडिट भारतीय नेताओं के बयानों का भी करता।

डोनाल्ड ट्रंप अब जब एक बार फिर अमेरिका की सत्ता को दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, झूठों का यह सिलसिला रुका नहीं है। अमेरिकी मीडिया के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं- एक तो वह एआई के झूठ गिने और दूसरी, नेताओं के परंपरागत झूठों का हिसाब रखे।

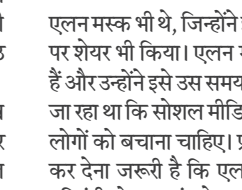

अमेरिकी मीडिया इसे अपने ढंग से कर भी रहा है। पिछले कुछ साल से मीडिया ने वहां एक तरीका अपनाया है, जिसे 'रियल टाइम फैक्ट चेक' कहा जाता है। इसमें जब किसी नेता का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो साथ-साथ तथ्यों की जांच भी चल रही होती है कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत। इंटरव्यू के दौरान ही नेता के सामने उसके झूठ भी रख दिए जाते हैं। पिछले दिनों उप-राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस जब *सीबीएन न्यूज* की एक बहस में भाग ले रहे थे और उन्हें यह बताया गया कि उनके तथ्य गलत हैं, तो उन्होंने इस तरीके का ही विरोध किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस चैनल के एक कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें फैक्ट चेक का तरीका अपनाया जाता है। पिछले दिनों पत्रकारों के एक समूह को डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के लिए समय दिया। फिर पता चला कि वे पत्रकार तथ्यों की जांच का काम भी साथ-साथ करेंगे, तो वह इंटरव्यू रद्द कर दिया गया।

अब पार्टी ने जेडी वेंस को यह काम सौंपा है कि वह उन झूठों की तुरपाई का काम करें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं। मसलन, चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कई बार यह कहा कि ओहियो में हैती के जो प्रवासी रह रहे हैं, वे अपने पड़ोसियों के कुत्ते-बिल्ली तक मारकर खा जाते हैं। जब वेंस से इसके बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था, ट्रंप दरअसल बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आ जाने से जो हालात पैदा हुए हैं, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।

अमेरिका में इन दिनों एक और शब्द प्रचलन में आया है- 'जस्टिफाइड लाई', यानी वाजिब झूठ। ऐसी बात जो झूठ तो है, लेकिन उसे बोलने का कोई वाजिब तर्क है। पोस्ट ट्रुथ एरा या सत्योत्तर काल में झूठ अब कई रंगों और विश्लेषणों में उपलब्ध है।

वैसे, दुनिया के तकरीबन सभी लोकतंत्र चुनावी झूठ की इस समस्या से किसी न किसी तरह जूझ रहे हैं। जब तक चुनाव लड़ने के लिए झूठ का सहारा लेना जरूरी माना जाता रहेगा, झूठ का सिक्का हर चुनाव में चलता रहेगा। तब तक मशीनें भी झूठ बोलेंगी, नेता भी झूठ बोलेंगे और कार्यकर्ता भी झूठ बोलेंगे। समस्या यह है कि चुनाव प्रक्रिया और संपूर्ण राजनीति को झूठ के बोलबाले से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसे लेकर पूरी दुनिया में कहीं कोई विमर्श नहीं चल रहा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

गंगा की निर्मल धारा को चाहिए देसी मछलियों का सहारा

यहां स्कैन करें

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

देश की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवीं सबसे लंबी नदी गंगा भारत के अस्तित्व, आस्था और जैव-विविधता की पहचान है। कोई नदी केवल जल की धारा नहीं होती, उसका अपना तंत्र होता है, जिसमें उसके जलचर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गंगा जल की पवित्रता को बरकरार रखने में अहम मछलियों-कछुओं की संख्या में यदि गिरावट आने लगी है, तो निश्चित ही यह नदी की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। एक तरफ, केंद्र सरकार गंगा की जल-धारा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, तो वहीं यह चिंतनीय है कि गंगा में मछलियों की विविधता को खतरा पैदा हो रहा है और इनकी 29 से अधिक प्रजातियों को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। गंगा में 143 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। मगर बनारस के आसपास देसी मछलियों की संख्या व उनकी प्रजनन दर में गिरावट आना नदी और उसके किनारे बसे समाजों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणी विभाग के एक ताजा शोध में बताया गया है कि घातक रसायनों के कारण गंगा, वरुणा और असि नदियों में सिंघी और मांगुर समेत कई देसी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अधिक गंभीर बात यह है कि मछलियों की प्रजनन क्षमता 80 प्रतिशत तक घट गई है। शोध बताता है कि वैसे तो जो मछली जितनी वजनदार होती है, उसके अंडे उतने ही अधिक होते हैं। एक मछली औसतन तीन से पांच लाख तक अंडे देती है, लेकिन गंगा में अब यह घटकर 50 से 70 हजार हो गई है।

गंगा में मछलियों की विविधता को खतरा पैदा हो रहा है और इनकी 29 से अधिक प्रजातियों को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पत्रिका *स्प्रिंगर* और पुणे से प्रकाशित होने वाली भारतीय शोध पत्रिका *डायमेंशन ऑफ लाइफ साइंस ऐंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट* के ताजा अंक में प्रकाशित शोधपत्र बताता है कि रासायनिक दवाओं, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक उत्पादों, पेंट, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक खादों में प्रयुक्त एल्काइल फिनोल व टर्ट-ब्यूटाइल फिनोल आदि का गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में मछलियों के अंडे देने पर बुरा असर पड़ा है। बीएचयू के प्राणी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर राधा चौबे और सहायक प्रोफेसर डॉ गीता गौतम का शोध बताता है कि विषाक्त रसायनों के कारण मछलियों की भ्रूणावस्था में मौत हो जा रही है। उनमें विभिन्न तरह के रोग भी पनप रहे हैं। इससे मछलियों की आबादी तेजी से घट रही है।

बनारस का शोध तो एक उदाहरण है, दरअसल समूची गंगा में ही देसी प्रजाति की मछलियों पर संकट मंडरा रहा है। आज से छह साल पहले राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा करवाए गए सर्वे में पता चला था कि गंगा की पारंपरिक रीठा, बागड़, हील समेत छोटी मछलियों की 50 देसी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। मतलब साफ है, जैव-विविधता के इस संकट का कारण हिमालयी नदियों पर बने बांध तो हैं ही, मैदानी इलाकों में तेजी से घुसपैठ कर रही विदेशी मछलियों की प्रजातियां भी हैं।

गंगा और इसकी सहायक नदियों में पिछले अनेक वर्षों के दौरान थाईलैंड, चीन व म्यांमार से लाए गए बीजों से मछली की पैदावार बढ़ाई जा रही है। ये मछलियां कम समय में बड़े आकार की हो जाती हैं, इसलिए मत्स्य-पालक अधिक मुनाफे के चक्कर में इन्हें अधिक पालते हैं। हकीकत में ये मछलियां स्थानीय मछलियों का चारा हड़प जाने के साथ ही छोटी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। किसी भी नदी के मूल जलचरों के समाप्त होने का असर उसके समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर इतना भयानक होता है कि जल की गुणवत्ता, प्रवाह आदि तक प्रभावित हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) पहले से ही नील तिलापिया, अफ्रीकी कैटफिश और कॉमन कार्प को मीठे पानी की जैव-विविधता के लिए बड़ा खतरा बता चुका है।

गंगा में मछलियों के लिए बड़ा खतरा गंगा घाटी क्षेत्र में सालों-साल बढ़ता तापमान भी है। गंगा नदी घाटी के 25 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्रीय जलवायु मॉडल के तहत किए गए शोध से पता चला कि 2010 से 2050 के बीच पानी के तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस की औसत बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में, आक्रामक विदेशी मछलियों की संख्या बढ़ रही है, जो नए पर्यावास व कठोर परिस्थितियों में भी विस्तार की क्षमता रखती हैं। इसलिए इस मामले में एक सुचिंतित पहल बहुत जरूरी हो गई है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

चॉकलेट जैसी कहानियां

एक जमाना था, जब लोग कहानियों और मुहावरों में बातें करते थे। उनमें ज्यादा तर्क-कुतर्क करने की जरूरत नहीं होती। थोड़े से शब्दों में गहरी बात कही जा सकती थी और परोक्ष रूप से बात दिल में पहुंच जाती थी। इसलिए उस जमाने के लोग कम बोलते थे, आज की तरह बातूनी नहीं होते थे। वे विज्ञान और तर्क से अप्रभावित दिन थे। लोग किस्से-कहानियां सुनना-सुनाना पसंद करते। हर कृत्य के पीछे कोई न कोई पुराण कथा जरूर होती। जैसे, बाहर से घर आने पर पांवों को आगे-पीछे से धोना बहुत जरूरी था। ऐसा किसी 'हाइजीन' या स्वच्छता के ख्याल से नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह कहानी थी कि हजारों साल पहले राजा बलि ने अपनी एड़ियां नहीं धोई थीं, इसलिए उनके शरीर में कलि प्रवेश कर गया। अब आप पूछेंगे, कलि वहां क्या कर रहा था? उसकी भी कहानी है।

राजा बलि बहुत पुण्यशाली थे और कलि को उनके द्वारा ही मनुष्य लोक में प्रवेश करना था, इसलिए वह बलि के आसपास चक्कर काटता रहता। लेकिन बलि ऐसे दूध के धुले थे कि एक भी गलत काम नहीं करते थे, इसलिए कलि को मौका नहीं मिल पाता। आखिरकार इस छोटी सी गलती से कलि को मौका मिला और वह झट से प्रवेश कर गया। उसके बाद कलियुग शुरू हुआ। इसका इतना गहरा संस्कार मेरे मन में खुदा हुआ है कि आज भी मैं पैर धोने के वक्त एड़ियों को पहले धोती हूं।

अभी मैंने धनतेरस की प्यारी सी कहानी पढ़ी। हीम नाम का राजा था, उसके सोलह साल के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि विवाह होने के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी पत्नी को इसका पता चला, तो उस चतुर नव-विवाहिता ने क्या किया? उसने राजकुमार के शयन कक्ष के बाहर द्वार पर ही ढेर सारे सोने-जवाहरात और आभूषण रखे और पूरे महल में हजारों दीप जलवाए। स्वर्ण की चमक से दीपक ऐसे जगमगाए, जैसे सूरज निकल आया हो। उसने रात भर पति को सोने न दिया, एक से एक मधुर गीत गाती रही। पूरा वातावरण इतना सम्मोहक था कि जब यमराज सांप बनकर राजकुमार को डसने आए, तो वहां की चकाचौंध से उनकी आंखें चुंधिया गईं और युवती के मधुर संगीत से मंत्रमुग्ध होकर वह स्वर्ण के ढेर पर कुंडली मारकर बैठ गए। जब उन्हें होश आया, सूरज ऊग आया था, सो वह चुपचाप वापस चले गए।

ये कहानियां आकर्षक आवरण में लिपटी ज्ञानियों की सीख हैं। इनके आवरण को छोड़ दें और सार निकाल लें, तो हर दिन दिवाली मनाने का मन करेगा।

ये सारगर्भित कहानियां चॉकलेट की तरह हैं। ये आकर्षक आवरण में लिपटी ज्ञानियों की सीख हैं। इनके आवरण को छोड़ दें और सार निकाल लें, तो हर दिन दिवाली मनाने का मन करेगा। सार यह है कि दिवाली पर जिस तरह आंगन में दीप जलाते हैं, उसी तरह मन में भी दीप जलाते रहें। साल में एक दफा नहीं, हर दिन।

अमृत साधना

डोनाल्ड ट्रंप | पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका

यदि कमला हैरिस को चार वर्ष और मिल गया, तो अश्वेत समुदाय (अमेरिका में) अपनी राजनीतिक शक्ति हमेशा के लिए खो देगा, क्योंकि उसके पड़ोस में बहुसंख्य प्रवासियों का दबदबा कायम हो जाएगा।

अनुलोम-विलोम
विवाह में दुष्कर्म

जागरूकता से ही थमेगा ऐसा दुष्कर्म

वैवाहिक दुष्कर्म कानून को लेकर समाज में उभरती बहस न केवल संवेदनशील है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक आयाम भी काफी जटिल हैं। साल 2012 के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून में कई सुधार किए गए, लेकिन वैवाहिक दुष्कर्म एक ऐसा क्षेत्र है, जहां अब भी संशोधन और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर चर्चा करते समय सभी पक्षों के हितों व अधिकारों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि न्याय की वास्तविक परिभाषा कायम रह सके। वैवाहिक संबंधों में सहमति और विश्वास का महत्व अत्यधिक होता है। मगर यदि पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे दुष्कर्म क्यों न माना जाए? इसी तर्क के आधार पर महिलाओं के लिए एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच की वकालत की जाती है। मगर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे अपराध मानने से निर्दोष पतियों पर झूठे आरोप लगने की आशंका बढ़ सकती है। दहेज-विरोधी कानून का सच तो हमारे सामने है ही।

इस परिप्रेक्ष्य में यह समझना आवश्यक है कि कानून का उद्देश्य न्याय की स्थापना होना चाहिए। वैवाहिक दुष्कर्म कानून के सही क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक मामले की गहन जांच आवश्यक होगी। मौजूदा व्यवस्था में ऐसा होना मुश्किल जान पड़ता है। ऐसे में, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी या समिति का गठन सही दिशा में उठा कदम हो सकता है, जो न केवल मामले की बारीकी से जांच करे, बल्कि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की आशंका को समाप्त करे। हालांकि, ऐसे मामलों का समाधान सिर्फ कानूनी प्रावधानों से नहीं हो सकता। वैवाहिक दुष्कर्म के खिलाफ आम लोगों में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। लोगों को यह समझना होगा कि विवाह के भीतर भी सहमति का महत्व है और इसे नकारा नहीं जा सकता। जब तक लोग नहीं समझेंगे, इसे रोकना मुश्किल होगा।

जाहिर है, कानून से ज्यादा समाज को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार इसमें उत्प्रेरक का काम कर सकती है। सामाजिक संगठनों की मदद से वह वैवाहिक संबंधों में सहमति व सम्मान के महत्व को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर अभियान चलाए। इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अपने देश में विवाह नामक संस्था की काफी अहमियत है। इसकी शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। पति-पत्नी, दोनों के अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय की भावना तभी बनी रह सकती है, जब इस संस्था पर समाज की उचित नजर हो। इस तरह का सामाजिक दबाव पूर्व में कई तरह के अपराधों को रोकने में मददगार साबित हो चुका है।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

रोकथाम के लिए सख्त कानून चाहिए

चर्चा गरम है कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए या नहीं? वैवाहिक दुष्कर्म का मतलब है, पति द्वारा पत्नी के साथ जबर्दस्ती बनाया गया संबंध। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में वैवाहिक दुष्कर्म पर ज्यादा बात नहीं की जाती और शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाना पति अपना हक समझता है। मगर यह समझना चाहिए कि हरेक इंसान के अधिकार होते हैं, जिनका हनन नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी के अधिकारों का भी नहीं। इसी बात को लेकर *पिंक* फिल्म में एक प्रसिद्ध डायलॉग है, 'नो मिन्स नो', यानी अगर महिला मना कर रही है, तो उसके साथ संबंध नहीं बनाए जा सकते, फिर चाहे वह पत्नी ही क्यों न हो। यही वजह है कि वैवाहिक दुष्कर्म को पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है।

भारत में भले ही इस बाबत महज बहस चल रही हो, पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वैवाहिक दुष्कर्म को सबसे पहले सोवियत संघ ने 1922 में अपराध घोषित किया था। उसके बाद 1932 में पोलैंड, 1991 में ब्रिटेन, 1993 में अमेरिका और 2019 तक दुनिया के लगभग 150 देशों में इसे अपराध घोषित किया जा चुका था। अमेरिका के सभी राज्यों में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना गया है। हां, यह बात अलग है कि हर राज्य की अपनी सीमा है, जिसमें सजा देने का उनका तरीका अलग-अलग हो सकता है। भारत में भी कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाकर इस अपराध पर रोक लगाई जा सकती है।

वैवाहिक दुष्कर्म जैसे विषयों पर विचार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। हरेक हाल में उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। 'न' का मतलब 'न' ही समझना महिला का सम्मान है। समाज में एकता और समानता लाने के लिए महिलाओं का सम्मान आवश्यक है। वास्तव में, कानूनी कार्रवाई ही उन लोगों को सुधार सकती है, जो शादी को जबर्दस्ती संबंध बनाने का एक सर्टिफिकेट समझते हैं। अपराधी के मन में भय होना ही चाहिए। अगर सख्त कानून बन सका, तो वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़े मामलों में काफी कमी आ सकती है। 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि 30 फीसदी भारतीय महिलाएं कभी न कभी अपने पति की यौन हिंसा का शिकार हुई हैं, जबकि एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया है कि 50 फीसदी से अधिक महिलाओं ने सामाजिक कलंक और डर के कारण पति द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ कदम नहीं उठाया। स्पष्ट है, आंकड़े सख्त कानून की गवाही दे रहे हैं। सरकार और समाज, दोनों को आगे आना चाहिए। यही मौजूदा समय की दरकार है।

माधुरी, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

जगत विचार का ही ठोस रूप है

चुनावी दौर की खटपट

गठबंधन के घटकों के बीच खटपट होते रहना कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह खटपट तब और अधिक बढ़ जाती है जब चुनाव आते हैं और यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन दल कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। इस पर हैरानी नहीं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से सीटों का जो बंटवारा किया गया, वह राष्ट्रीय जनता दल को पसंद नहीं आया। उसने अपनी नाराजगी भी जता दी है। आश्चर्य नहीं कि वह इसका बदला बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में ले और कांग्रेस को वांछित सीटें न दे। जो भी हो, राजद को यह समझना होगा कि उसका प्रभाव बिहार में ही है और झारखंड में उसकी कोई विशेष राजनीतिक अहमियत नहीं है। यह बात जनता दल (यू) को भी समझनी होगी, जो झारखंड में दो सीटें मिलने से नाखुश दिख रही है। चूंकि गठबंधन राजनीति के कोई नियम-कानून नहीं बने हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी के घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। फिलहाल सत्तारूढ़ महायुति में खटपट नहीं दिख रही, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि सब कुछ सुगम तरीके से हो जाएगा।

सीटों के बंटवारे के बाद जब विभिन्न दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे तब भी असंतोष और विद्रोह की खबरें आएंगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होते ही असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। कई बार असंतोष के ऐसे स्वर विद्रोह में बदल जाते हैं और चुनाव लड़ने के आकांक्षी उम्मीदवार या तो विद्रोही बन जाते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं अथवा भितरघात में लग जाते हैं। इस स्थिति से करीब-करीब सभी राजनीतिक दल दो चार होते हैं, लेकिन वे प्रत्याशी चयन की कोई तर्कसंगत और पारदर्शी व्यवस्था अपनाने से इन्कार कर रहे हैं। आखिर कुछ विकसित देशों की तरह से भारत में भी आंतरिक चुनाव के जरिये प्रत्याशी चयन की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती, जिससे सक्षम और योग्य नेताओं को ही चुनाव लड़ने का अवसर मिले। हमारे राजनीतिक दल लोकतंत्र की चाहे जितनी दुहाई दें, सच तो यह है कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की बात तो दूर रही, संबंधित दल के कार्यकर्ताओं की भी कोई भागीदारी मुश्किल से ही होती है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि प्रत्याशियों के चयन में संबंधित राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की आकांक्षाओं को भी महत्व दिया जाए। यह कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों सरीखी जैसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, उससे बचा जा रहा है। इन स्थितियों में उचित यह होगा कि चुनाव आयोग ऐसी कोई पहल करे जिससे राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में मनमानी न कर सकें। अभी तो वे जनता पर प्रत्याशियों को थोपने का काम करते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की भागीदारी एक ओर जहां योग्य जन प्रतिनिधियों को सामने लाने का काम करेगी, वहीं लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करेगी।

सराहनीय पहल

मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कला महोत्सव मनाने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल सराहनीय है। इस पहल के तहत झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के जाने-माने 81 चित्रकारों ने कैनवास पर कलाकृतियां उकेरकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया। इस दो दिवसीय आयोजन में मतदाताओं को जहां एक ओर झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की कला-संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का अवसर मिला, वहीं आसन्न विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की प्रेरणा भी मिली। खासकर शहरी क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता कहीं अधिक देखने को मिलती रही है। इसी वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव में भी रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर आदि शहरों का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। कला महोत्सव के लिए अगर रांची का चयन किया गया तो इसके पीछे का कारण यहां का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहना है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां 50 प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी झारखंड दौरे के क्रम में इस पर चिंता जताते हुए शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आवश्यक निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह उपायुक्तों को दिए थे। साथ ही 'मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी' के उद्देश्य को केंद्र में रखकर स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेने की अपील की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आसन्न विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदलेंगी और शहरी मतदाता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे।

प्रभावी सिद्ध हों न्याय की देवी

हृदयनारायण दीक्षित

न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा

सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में स्थापित की गई न्याय की देवी की नई प्रतिमा ● पीटीआई

न्याय आदिम अभिलाषा है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में न्याय व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं। उनमें न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर पट्टी है। एक हाथ में तलवार है। देवी का प्रतीक यूनानी सभ्यता से लंबी यात्रा करते हुए यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। औपनिवेशिक काल (17वीं सदी) में ब्रिटेन के एक न्यायिक अधिकारी न्याय की देवी की मूर्ति भारत लाए थे। भारत में कलकत्ता और बंबई हाई कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इसका सार्वजनिक प्रयोग होने लगा। बांग्लादेश में भी न्याय देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में थी। कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों ने इसे बुतपरस्ती बताया और तख्तापलट के आंदोलन में यह ध्वस्त कर दी गई।

स्वाधीन भारत ने न्याय की देवी के प्रतीक को अपना लिया। हाल में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में आंख की पट्टी हटा ली गई है। पट्टी कानून के अंधा होने का संकेत देती थी। कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा ने अंधा कानून विषयक कई फिल्में बनाईं। देवी के एक हाथ में तलवार सजा प्रतिबिंबित करती थी। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में तलवार की जगह संविधान है। देवी का यह प्रतीक संवैधानिक मूल्यों और विधि के समक्ष समता का संदेश देता है। देवी की यह प्रतिमा आकर्षक है। उन्हें साड़ी पहनाई गई है। सिर पर मुकुट, गले के हार से मूर्ति को सुंदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में यह स्थापित की गई है। साफ है देश औपनिवेशिक सत्ता के समय के कानूनों-प्रतीकों से छुटकारा पा रहा है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश काल में अधिनियमित हुए थे। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 2023 पारित किए। पुराने कानून कालबाह्य हो चुके हैं।

न्याय की देवी की प्रतिमा प्रेरक है। संशोधित प्रतिमा के हाथ में संविधान है तो इसीलिए कि भारत में संविधान का शासन है। न्याय की देवी का ताजा प्रतीक स्वागतयोग्य है। न्याय की देवी का इतिहास प्राचीन है। इसकी सबसे प्राचीन मूर्ति प्राचीन मिस्र में मिली थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने न्याय की देवी की मूर्तियां बनाईं। रोमन साम्राज्य में भी न्याय की देवी थी। यूनानी सभ्यता में गंभीर सृष्टि चिंतन हुआ था। होमर को कुछ विद्वानों ने यूनान का गुरु बताया है। उनके लिखे इलियड और ओडाइसी महाकाव्यों की विश्व प्रतिष्ठा है। जैसे भारत में वेदों और महाभारत के लिए वेद व्यास के प्रति श्रद्धा है, वैसे ही इलियड और ओडाइसी के लिए होमर की ख्याति है। यूनानी अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करते रहे हैं, पर सुकरात को यूनानी अदालत ने ही मृत्यु दंड दिया था। न्यायपालिका ने उनका पूरा पक्ष नहीं सुना। सुकरात के विरुद्ध युवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप था। सुकरात 70 वर्ष के वृद्ध थे। उन्होंने कहा था, 'शासक जल्दी न करते तो भी वह थोड़े दिन बाद स्वाभाविक मृत्यु से मरते।'

भारत में दुनिया की प्राचीन न्यायपालिका है। यहां प्राचीन काल में भी व्यवस्थित न्यायतंत्र था। राजा हरिश्चंद्र, रघु और शिवि आदि न्यायप्रियता के लिए देश में आज भी चर्चित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस धवन ने प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली का खूबसूरत अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश लेखकों पर प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में गलत और मनमाने विचार व्यक्त करने के आरोप लगाए। उन्होंने हेनरी मेने पर भारत की न्याय व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। यही स्थिति अनेक यूरोपवादी विद्वानों की है। धवन ने भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बताया। इसके ज्ञान के लिए प्राचीन साहित्य का अध्ययन जरूरी कहा। प्राचीन न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश कानून के अधीन थे। प्राचीन न्यायपालिका में भी न्यायधीशों का पदानुक्रम था। राजा मनमाना आचरण नहीं कर सकते थे। महाभारत के अनुसार जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेता है और बाद में वैसा नहीं करता, तो उसे दंडित करना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी कर्मचारी थे। न्याय व्यवस्था थी। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि ने प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था को सुंदर बताया है। न्यायाधीश के लिए निर्धारित आचार संहिता थी। निष्पक्ष काम करने वाला न्यायप्रिय राजा प्रशंसा का पात्र था। तब राजा आसन पर बैठते ही विवस्वान के पुत्र यम की शपथ लेकर काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में नचिकेता और राजा यम के बीच संवाद पठनीय है। यम ने नचिकेता को बताया, 'धरती पर जो लोग अन्याय और उत्पीड़न करते हैं, हे नचिकेता! मैं उन्हें बार-बार दंडित करता हूं।' यम न्याय व्यवस्था के उच्चतर देवता हैं। वह दोषियों को दंड देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार न्यायकर्ता के लिए उच्च प्रतिभा आवश्यक थी। कात्यायन ने लिखा है, 'न्यायाधीश को संयमी, निष्पक्ष और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।' बृहस्पति ने कहा है, 'व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए।' वैदिक साहित्य में राजव्यवस्था और न्यायतंत्र के विशेष उल्लेख हैं। पराशर ने कह है, 'कृतयुग के कानून कृतयुग के समय उपयोगी हैं। द्वापर के कानून अलग हैं। कलयुग के कानून पिछले युगों से अलग हैं।' प्रत्येक युग के कानून युग की विशेषता के अनुसार होते थे। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक न्याय प्रणाली का लगातार विस्तार हुआ है।

संप्रति भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है, लेकिन तमाम मामलों में न्यायपालिका से आशा के साथ निराशा हाथ लगती है। न्याय में देरी अन्याय है। यह सिद्धांत पुराना है। देश के न्यायालयों में विचारणीय मुकदमों की संख्या पांच करोड़ है। ऐसे में यह अपेक्षा है कि न्याय की देवी समय पर सुगम तरीके से सभी को न्याय देने में प्रभावी सिद्ध हों, क्योंकि न्याय में विलंब की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जन-जन का मिशन बनी स्वच्छता

रमेश कुमार दुबे

भारत में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि की तरह ही शौचालय क्रांति ने भी देश को एक नई दिशा दी है

खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हुआ भारत। फाइल

स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन को मिले अपार जनसमर्थन पर प्रकाश डाला और कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक ने इसे अपना मिशन बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाने वालों ने कभी गंदगी को समस्या माना ही नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो अब तक की सरकारों ने स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया और शौचालयों की कमी को कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं माना गया। देश में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि क्रांतियां तो हुईं, लेकिन शौचालय क्रांति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि आधुनिकता और विकास के तमाम दावों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाला भारत ऐसे देशों में अग्रणी रहा, जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे रहा। यूपीए सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी को शौचालय सुविधा मुहैया कराने के लिए देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही की सुस्ती और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लक्ष्य दूर ही रहा।

इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में जब स्वच्छ भारत का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे इससे बेपरवाह प्रधानमंत्री मोदी ने ''पहले शौचालय फिर देवालय'' के अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उसी साल महात्मा गांधी की जन्मतिथि अर्थात दो अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाने की योजना को 15 अगस्त से ही शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के लिए सफाई मित्रों, धार्मिक गुरुओं, एथलीटों, प्रसिद्ध हस्तियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी सहयोग देने के लिए आह्वान किया कि उन्हें सामाजिक दायित्व के तहत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शौचालय क्रांति में नवविवाहिताओं की जिद ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय क्रांति के आह्वान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में नवविवाहिताओं ने ससुराल के उन घरों में रहने से साफ इन्कार कर दिया, जिनमें शौचालय नहीं थे। इससे न केवल संबंधित परिवारों में, बल्कि समाज में भी शौचालय निर्माण के प्रति नई जागरूकता आई। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 10 वर्षों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात दो अक्टूबर, 2019 से पहले ही भारत खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हो गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में देश के 82.5 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा है, जबकि 2004-05 में मात्र 29 प्रतिशत परिवारों में ही शौचालय थे। इससे खुले में शौच में भारी कमी के साथ ही बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट आई है। स्वच्छता अभियान हर साल 60-70 हजार बच्चों को डायरिया के कारण मौत के मुंह में जाने से बचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2014 से 2019 के बीच तीन लाख लोगों की जान बचाई गई, जो डायरिया के कारण गंवा दी जाती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अब देश की 90 प्रतिशत महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कारण महिलाओं में संक्रमण से होने वाली बीमारियों में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनने से उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार स्वच्छता के कारण परिवारों को आज हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत हो रही है, जो पहले बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाते थे।

स्वच्छता से जुड़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि से देश में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आया है। इसी का परिणाम है कि सफाई कार्य में शामिल लोगों को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया है। देश में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से राजमिस्त्री, प्लंबर, मजदूर जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान ने महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत घरों से निकलने वाले कचरे से अब खाद, बायोगैस, बिजली और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चारकोल जैसे पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। गोबरधन योजना के तहत गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जहां पशु अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जा रहा है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान देश को एक नई पहचान देने के साथ-साथ विकास को भी नई दिशा देने में सफल दिख रहा है।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संतोष साधना

मनुष्य की क्षुधा का अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि वह लाख रुपये पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो, क्या इतने रुपये पाकर वह सुखी है? वह कहेगा कि 'रुपया कहां है, किसी प्रकार दिन काट रहा है।' अधिक संपत्ति रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना उसका अपरिग्रह विरोधी भाव है। इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन को अत्याधिक लोभ-लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है। इसलिए मन विश्राम नहीं पाता है। प्रश्न है, शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है? चूंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज्यादा बोझ डालता है।

वहीं व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। 'तोष' शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए।

चूंकि मनुष्य अक्सर अपने सुख के लिए लोभ वृत्ति के वश में अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है। इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा होता है, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

ई-शासन की नई उड़ान

देवेंद्रराज सुथार

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हो गया है

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर एक नई मिसाल कायम की है। 'संपदा 2.0' के नाम से शुरू की गई यह पहल न केवल तकनीकी उन्नति का परिचायक है, बल्कि सुशासन की दिशा में अनूठा कदम भी है। डिजिटल युग में सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुलभ बनाना किसी भी सरकार के सुशासन के प्रयासों का प्रमुख हिस्सा है और मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत नागरिकों को किसी दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे ही अपनी जमीन, मकान या दुकान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नागरिक आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट रजिस्ट्रेशन की सुविधा पा सकते हैं या यदि चाहें तो स्लाट बुक कर कार्यालय जा सकते हैं। विदेश में रहनेवाले लोगों के लिए यह अधिक सुविधाजनक है।

यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सहायक सिद्ध होगी। पहले नागरिकों को कार्यालयों में कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी और भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ जाती थी। अब जब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और आधार, भू-अभिलेख एवं अन्य डिजिटल स्रोतों से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो गई है। पहचान के लिए गवाह की आवश्यकता नहीं होने से नागरिकों का वक्त और धन दोनों बचेंगे। सरकार का दावा है कि संपदा पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से नागरिक स्टांप ड्यूटी की गणना, भुगतान और माडल डीड तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं स्वयं कर सकेंगे। स्टांप शुल्क की जानकारी भी आनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे सुविधा के अनुसार लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

वास्तव में संपदा 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि तकनीकी उन्नति और सुशासन के माध्यम से नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। सुशासन का अर्थ केवल कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरलता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ मिलें। मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा 2.0 के जरिये सुशासन का एक नया मानदंड स्थापित किया है। उम्मीद है कि इस प्रकार की पहल देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी, ताकि समूचे देश में डिजिटल गवर्नेंस का दायरा बढ़ सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

नए नेता तैयार करने में पिछड़ती कांग्रेस

'अपने ही क्षत्रपों से पस्त कांग्रेस' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने क्रमबद्ध तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए उसके क्षत्रपों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा साधे जाने में विफल रहना बताया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस ने कभी जमीनी कार्यकर्ताओं में से विकल्प के तौर पर अपने नेताओं का दूसरा वर्ग तैयार ही नहीं किया, जबकि कांग्रेस के उलट भाजपा ने ऐसे नेताओं की अगली पंक्ति तैयार करने में कार्यकर्ताओं को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे दलों के नेताओं को भी खासा महत्व दिया। इसके जीवंत उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हैं। आखिर कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को भांपने में क्यों नाकाम रही? ऐसे में यह कहना उपयुक्त होगा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है। जब तक इस जिम्मेदारी को समझ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी संगठन के स्तर पर व्यापक परिवर्तन को तैयार नहीं होगा, तब तक वह हरियाणा और छत्तीसगढ़ की तरह जीती बाजी भी सदैव हारता रहेगा। यह तो कांग्रेस के पुराने नेताओं की सींची जमीन का चमत्कार है कि आज अकुशल संचालन के बाद भी पार्टी का थोड़ा-बहुत जनाधार कमोबेश हर राज्य में कायम है। यह जनाधार पूरी तरह खत्म हो जाए इससे पहले कांग्रेस हाईकमान को चेत जाना चाहिए।

mukeshkr.m7542@gmail.com

मेलबाक्स

बातचीत का माहौल तो बने

पाकिस्तान के साथ बातचीत की हर बार पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, लेकिन सार्थक बातचीत नहीं हो पाती। आखिर हो भी कैसे। दोनों पक्ष अपने अपने पथ पर अडिग हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान नेकदिली से हाथ बढ़ाए, भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करे। आतंकवाद और सद्भावना साथ-साथ नहीं चल सकते। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वह कश्मीर का मुद्दा और अब इसके साथ ही अनुच्छेद-370 का मुद्दा छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की जनता तो जानती है कि भारत से संबंध सुधारने में ही उसकी भलाई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केमिस्ट्री कुछ बनने लगी थी, लेकिन वह केमिस्ट्री उनके छोटे भाई के साथ नहीं बन पाई। भारत तो संबंध सुधारना चाहता है, तभी तो विदेश मंत्री को शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया। यह भी एक इतिहास रहा है, जब भी भारत और पाकिस्तान की कोई सकारात्मक बातचीत होने लगती है तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी आतंकी कार्रवाई हो जाती है, जिससे बातचीत पटरी से उतर जाती है। पाकिस्तान के नेता और जनता में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाक के संबंध कभी न सुधरें।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

कोटे में कोटा व्यवस्था

समाचार पत्र के 20 अक्तूबर के अंक में मुख पृष्ठ पर हरियाणा में कोटे में कोटा व्यवस्था पर नई प्रदेश सरकार का निर्णय प्रकाशित हुआ है। यह संपूर्ण देश में जातिगत आरक्षण की नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह अंत्योदय की संकल्पना को सार्थक करता है। जातिगत आरक्षण व्यवस्था राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और राजनीतिक दल भी यह समझ चुके हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के करोड़ों युवाओं को बहुत थोड़ी सी सरकारी नौकरियों के छलावे से बहुत समय तक नहीं बहलाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातिगत आरक्षण द्वारा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का लाभ बहुत सीमित वर्ग को ही मिला है। क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा देने से भी केवल सांकेतिक सुधार है, जिसका धरातल पर प्रभाव न्यूनतम है। विभिन्न चुनावों में आरक्षण का विषय हिंदुओं में विभाजन का सबसे प्रमुख आधार बन जाता है, जबकि आरक्षित समाज का इससे कोई भला नहीं होता।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चुनावी दौर की खटपट

गठबंधन के घटकों के बीच खटपट होते रहना कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह खटपट तब और अधिक बढ़ जाती है जब चुनाव आते हैं और यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन दल कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। इस पर हैरानी नहीं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से सीटों का जो बंटवारा किया गया, वह राष्ट्रीय जनता दल को पसंद नहीं आया। उसने अपनी नाराजगी भी जता दी है। आश्चर्य नहीं कि वह इसका बदला बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में ले और कांग्रेस को वांछित सीटें न दे। जो भी हो, राजद को यह समझना होगा कि उसका प्रभाव बिहार में ही है और झारखंड में उसकी कोई विशेष राजनीतिक अहमियत नहीं है। यह बात जनता दल (यू) को भी समझनी होगी, जो झारखंड में दो सीटें मिलने से नाखुश दिख रही है। चूंकि गठबंधन राजनीति के कोई नियम-कानून नहीं बने हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी के घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। फिलहाल सत्तारूढ़ महायुति में खटपट नहीं दिख रही, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि सब कुछ सुगम तरीके से हो जाएगा। सीटों के बंटवारे के बाद जब विभिन्न दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे तब भी असंतोष और विद्रोह की खबरें आएंगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होते ही असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। कई बार असंतोष के ऐसे स्वर विद्रोह में बदल जाते हैं और चुनाव लड़ने के आकांक्षी उम्मीदवार या तो विद्रोही बन जाते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं अथवा भितरघात में लग जाते हैं। इस स्थिति से करीब-करीब सभी राजनीतिक दल दो चार होते हैं, लेकिन वे प्रत्याशी चयन की कोई तर्कसंगत और पारदर्शी व्यवस्था अपनाने से इन्कार कर रहे हैं। आखिर कुछ विकसित देशों की तरह से भारत में भी आंतरिक चुनाव के जरिये प्रत्याशी चयन की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती, जिससे सक्षम और योग्य नेताओं को ही चुनाव लड़ने का अवसर मिले। हमारे राजनीतिक दल लोकतंत्र की चाहे जितनी दुहाई दें, सच तो यह है कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की बात तो दूर रही, संबंधित दल के कार्यकर्ताओं की भी कोई भागीदारी मुश्किल से ही होती है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि प्रत्याशियों के चयन में संबंधित राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की आकांक्षाओं को भी महत्व दिया जाए। यह कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों सरीखी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, उससे बचा जा रहा है। इन स्थितियों में उचित यह होगा कि चुनाव आयोग ऐसी कोई पहल करे जिससे राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में मनमानी न कर सकें। अभी तो वे जनता पर प्रत्याशियों को थोपने का काम करते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की भागीदारी एक ओर जहां योग्य जन प्रतिनिधियों को सामने लाने का काम करेगी, वहीं लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करेगी।

आत्मनिर्भरता की ओर

कृषि, पशुपालन के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि रोडमैप लागू होने से सब्जी, दूध, अंडा, पशुपालन, मछली पालन, फल सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ा है। कृषि व पशुपालन क्षेत्र में शोध व तकनीक का उपयोग कर आज प्रदेश में कई लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इतना ही नहीं वे दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कृषि के साथ मछली उत्पादन में दिए जा रहे अनुदान का लाभ लेकर कई लोग इसे मजबूत आर्थिकी की तरह विकसित कर रहे या कर चुके हैं। प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति के साथ निर्यात भी कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार, दो दशक पहले तक यहां मछली का उत्पादन दो लाख 88 हजार टन होता था, जो अब बढ़कर आठ लाख 73 हजार टन हो गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि है। मछली उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। इससे जुड़े लोगों के लिए अच्छी सूचना है कि जल्द ही तमाम दिक्कतों को तकनीकी रूप से दूर करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकेगा। यदि सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में और प्रयास करे तो बिहार इस मामले में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा दिखेगा। नवाचार को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, ताकि वह इसका लाभ उठा सकें।

बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मछली उत्पादन से जोड़ा जाए तो और सार्थक परिणाम मिल सकते हैं

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जब जमानत जब्त हो गई तब फिर सुरक्षा की क्या जरूरत है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर की सीमा को मौजूदा आठ लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या आप मानते हैं कि भारतीय टेस्ट टीम के लिए न्यूजीलैंड से मिली हार बड़ी चुनौतियों से पहले एक जरूरी झटका है?

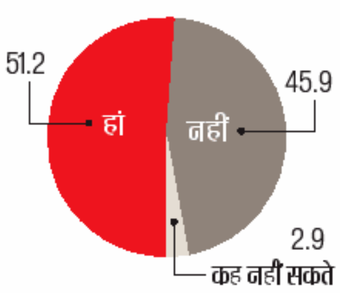

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

प्रभावी सिद्ध हों न्याय की देवी

हृदयनारायण दीक्षित

न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा

सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में स्थापित की गई न्याय की देवी की नई प्रतिमा ● ग्रेट

न्याय आदिम अभिलाषा है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में न्याय व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं। उनमें न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर पट्टी है। एक हाथ में तलवार है। देवी का प्रतीक यूनानी सभ्यता से लंबी यात्रा करते हुए यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। औपनिवेशिक काल (17वीं सदी) में ब्रिटेन के एक न्यायिक अधिकारी न्याय की देवी की मूर्ति भारत लाए थे। भारत में कलकत्ता और बंबई हाई कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इसका सार्वजनिक प्रयोग होने लगा। बांग्लादेश में भी न्याय देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में थी। कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों ने इसे बुतपरस्ती बताया और तख्तापलट के आंदोलन में यह ध्वस्त कर दी गई।

स्वाधीन भारत ने न्याय की देवी के प्रतीक को अपना लिया। हाल में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में आंख की पट्टी हटा ली गई है। पट्टी कानून के अंधा होने का संकेत देती थी। कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा ने अंधा कानून विषयक कई फिल्में बनाईं। देवी के एक हाथ में तलवार सजा प्रतिबिंबित करती थी। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में तलवार की जगह संविधान है। देवी का यह प्रतीक संवैधानिक मूल्यों और विधि के समक्ष समता का संदेश देता है। देवी की यह प्रतिमा आकर्षक है। उन्हें साड़ी पहनाई गई है। सिर पर मुकुट, गले के हार से मूर्ति को सुंदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में यह स्थापित की गई है। साफ है देश औपनिवेशिक सत्ता के समय के कानूनों-प्रतीकों से छुटकारा पा रहा है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश काल में अधिनियमित हुए थे। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 2023 पारित किए। पुराने कानून कालबाह्य हो चुके हैं।

न्याय की देवी की प्रतिमा प्रेरक है। संशोधित प्रतिमा के हाथ में संविधान है तो इसीलिए कि भारत में संविधान का शासन है। न्याय की देवी का ताजा प्रतीक स्वागतयोग्य है। न्याय की देवी का इतिहास प्राचीन है। इसकी सबसे प्राचीन मूर्ति प्राचीन मिस्र में मिली थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने न्याय की देवी की मूर्तियां बनाईं। रोमन साम्राज्य में भी न्याय की देवी थी। यूनानी सभ्यता में गंभीर सृष्टि चिंतन हुआ था। होमर को कुछ विद्वानों ने यूनान का गुरु बताया है। उनके लिखे इलियड और ओडाइसी महाकाव्यों की विश्व प्रतिष्ठा है। जैसे भारत में वेदों और महाभारत के लिए वेद व्यास के प्रति श्रद्धा है, वैसे ही इलियड और ओडाइसी के लिए होमर की ख्याति है। यूनानी अपनी न्याय व्यवस्था को लेकर गर्व करते रहे हैं, लेकिन प्रख्यात दार्शनिक सुकरात को यूनानी अदालत ने ही मृत्यु दंड दिया था। न्यायपालिका ने उनका पूरा पक्ष नहीं सुना। सुकरात के विरुद्ध देवताओं को न मानने और युवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप था। सुकरात 70 वर्ष के वृद्ध थे। उन्होंने कहा था, 'शासक जल्दी न करते तो भी वह थोड़े दिन बाद स्वाभाविक मृत्यु से मरते।'

भारत में दुनिया की प्राचीन न्यायपालिका है। यहां प्राचीन काल में भी व्यवस्थित न्यायतंत्र था। राजा हरिश्चंद्र, रघु और शिवि आदि न्यायप्रियता के लिए देश में आज भी चर्चित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस धवन ने प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली का खूबसूरत अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश लेखकों पर प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में गलत और मनमाने विचार व्यक्त करने के आरोप लगाए। उन्होंने हेनरी मेने पर भारत की न्याय व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। यही स्थिति अनेक यूरोपवादी विद्वानों की है। धवन ने भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बताया। इसके ज्ञान के लिए प्राचीन साहित्य का अध्ययन जरूरी कहा। प्राचीन न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश कानून के अधीन थे। प्राचीन न्यायपालिका में भी न्यायधीशों का पदानुक्रम था। राजा मनमाना आचरण नहीं कर सकते थे। महाभारत के अनुसार जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेता है और बाद में वैसा नहीं करता, तो उसे दंडित करना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी कर्मचारी थे। न्याय व्यवस्था थी। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि ने प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था को सुंदर बताया है। न्यायाधीश के लिए निर्धारित आचार संहिता थी। निष्पक्ष काम करने वाला न्यायप्रिय राजा प्रशंसा का पात्र था। तब राजा आसन पर बैठते ही विवस्वान के पुत्र यम की शपथ लेकर काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में नचिकेता और राजा यम के बीच संवाद पठनीय है। यम ने नचिकेता को बताया, 'धरती पर जो लोग अन्याय और उत्पीड़न करते हैं, हे नचिकेता! मैं उन्हें बार-बार दंडित करता हूं।' यम न्याय व्यवस्था के उच्चतर देवता हैं। वह दोषियों को दंड देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार न्यायकर्ता के लिए उच्च प्रतिभा आवश्यक थी। कात्यायन ने लिखा है, 'न्यायाधीश को संयमी, निष्पक्ष और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।' बृहस्पति ने कहा है, 'व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए।' वैदिक साहित्य में राजव्यवस्था और न्यायतंत्र के विशेष उल्लेख हैं। पराशर ने कह है, 'कृतयुग के कानून कृतयुग के समय उपयोगी हैं। द्वापर के कानून अलग हैं। कलयुग के कानून पिछले युगों से अलग हैं।' प्रत्येक युग के कानून प्रत्येक युग की विशेषता के अनुसार होते थे। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक न्याय प्रणाली का लगातार विस्तार हुआ है।

संप्रति भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है, लेकिन तमाम मामलों में न्यायपालिका से आशा के साथ निराशा हाथ लगती है। न्याय में देरी अन्याय है। यह सिद्धांत पुराना है। इस समय देश के न्यायालयों में विचारणीय मुकदमों की संख्या लगभग पांच करोड़ है। यह एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह अपेक्षा है कि न्याय की देवी समय पर सुगम तरीके से सभी को न्याय देने में प्रभावी सिद्ध हों, क्योंकि न्याय में विलंब की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जन-जन का मिशन बनी स्वच्छता

रमेश कुमार दुबे

भारत में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि की तरह ही शौचालय क्रांति ने भी देश को एक नई दिशा दी है

खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हुआ भारत ● फाइल

स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन को मिले अपार जनसमर्थन पर प्रकाश डाला और कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक ने इसे अपना मिशन बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाने वालों ने कभी गंदगी को समस्या माना ही नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो अब तक की सरकारों ने स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया और शौचालयों की कमी को कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं माना गया। उल्लेखनीय है कि देश में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि क्रांतियां तो हुईं, लेकिन शौचालय क्रांति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि आधुनिकता और विकास के तमाम दावों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाला भारत ऐसे देशों में अग्रणी रहा, जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे रहा। यूपीए सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी को शौचालय सुविधा मुहैया कराने के लिए देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही की सुस्ती और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लक्ष्य दूर ही रहा।

इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में जब स्वच्छ भारत का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे इससे बेपरवाह प्रधानमंत्री मोदी ने ''पहले शौचालय फिर देवालय'' के अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उसी साल महात्मा गांधी की जन्मतिथि अर्थात दो अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाने की योजना को 15 अगस्त से ही शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के लिए सफाई मित्रों, धार्मिक गुरुओं, एथलीटों, प्रसिद्ध हस्तियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी सहयोग देने के लिए आह्वान किया कि उन्हें सामाजिक दायित्व के तहत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शौचालय क्रांति में नवविवाहिताओं की जिद ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय क्रांति के आह्वान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में नवविवाहिताओं ने ससुराल के उन घरों में रहने से साफ इन्कार कर दिया, जिनमें शौचालय नहीं थे। इससे न केवल संबंधित परिवारों में, बल्कि समाज में भी शौचालय निर्माण के प्रति नई जागरूकता आई। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 10 वर्षों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात दो अक्टूबर, 2019 से पहले ही भारत खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हो गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में देश के 82.5 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा है, जबकि 2004-05 में मात्र 29 प्रतिशत परिवारों में ही शौचालय थे। इससे खुले में शौच में भारी कमी के साथ ही बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट आई है। स्वच्छता अभियान हर साल 60-70 हजार बच्चों को डायरिया के कारण मौत के मुंह में जाने से बचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2014 से 2019 के बीच तीन लाख लोगों की जान बचाई गई, जो डायरिया के कारण गंवा दी जाती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अब देश की 90 प्रतिशत महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कारण महिलाओं में संक्रमण से होने वाली बीमारियों में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनने से उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार स्वच्छता के कारण परिवारों को आज हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत हो रही है, जो पहले बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाते थे।

स्वच्छता से जुड़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि से देश में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आया है। इसी का परिणाम है कि सफाई कार्य में शामिल लोगों को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया है। देश में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से राजमिस्त्री, प्लंबर, मजदूर जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान ने महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत घरों से निकलने वाले कचरे से अब खाद, बायोगैस, बिजली और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चारकोल जैसे पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। गोबरधन योजना के तहत गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जहां पशु अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जा रहा है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान देश को एक नई पहचान देने के साथ-साथ विकास को भी नई दिशा देने में सफल दिख रहा है।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संतोष साधना

मनुष्य की क्षुधा का अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि वह लाख रुपये पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो, क्या इतने रुपये पाकर वह सुखी है? वह कहेगा कि 'रुपया कहां है, किसी प्रकार दिन काट रहा है।' अधिक संपत्ति रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना उसका अपरिग्रह विरोधी भाव है। इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन को अत्याधिक लोभ-लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है। इसलिए मन विश्राम नहीं पाता है। प्रश्न है, शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है? चूंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य स्वाभाविक परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज्यादा बोझ डालता है।

वहीं व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। 'तोष' शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए।

चूंकि मनुष्य अक्सर अपने सुख भोग के लिए लोभ वृत्ति के वश में आकर अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है। इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा होता है, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

नए नेता तैयार करने में पिछड़ती कांग्रेस

'अपने ही क्षत्रपों से पस्त कांग्रेस' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने क्रमबद्ध तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए उसके क्षत्रपों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा साधे जाने में विफल रहना बताया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस ने कभी जमीनी कार्यकर्ताओं में से विकल्प के तौर पर अपने नेताओं का दूसरा वर्ग तैयार ही नहीं किया, जबकि कांग्रेस के उलट भाजपा ने ऐसे नेताओं की अगली पंक्ति तैयार करने में कार्यकर्ताओं को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे दलों के नेताओं को भी खासा महत्व दिया। इसके जीवंत उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को भांपने में क्यों नाकाम रही? ऐसे में यह कहना उपयुक्त होगा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है। जब तक इस जिम्मेदारी को समझ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी संगठन के स्तर पर व्यापक परिवर्तन को तैयार नहीं होगा, तब तक वह हरियाणा और छत्तीसगढ़ की तरह जीती बाजी भी सदैव हरता रहेगा। यह तो कांग्रेस के पुराने नेताओं की सींची जमीन का चमत्कार है कि आज अकुशल संचालन के बाद भी पार्टी का थोड़ा-बहुत जनाधार कमोबेश हर राज्य में कायम है। यह जनाधार पूरी तरह खत्म हो जाए इससे पहले कांग्रेस हाईकमान को चेत जाना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय दल सरीखा बनकर रह जाएगी।

mukeshkr.m7542@gmail.com

अमेरिका भरोसेमंद नहीं

'भारत के खिलाफ जाते कनाडा-अमेरिका' शीर्षक से लिखे लेख में संजय गुप्त ने उचित कहा है कि भारत का हितैषी बताने वाला अमेरिका अब भरोसे का मित्र नहीं रह गया है। वह भी कनाडा के सुर में सुर मिलाते हुए भारत विरोधी कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका को भारत द्वारा घोषित आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय एजेंसी 'रा' के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव की तलाश है। कटु सत्य है कि भारत में तीसरी बार लगातार सत्ता में आने पर मोदी सरकार से अमेरिका सहित कई अन्य विकसित देश भीतर ही भीतर घबराहट में हैं। उन्हें डर है कि कहीं आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भारत की ही तूती ना बोलने लगे। तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर भारत को अस्थिर करने के लिए पश्चिमी देश हर तरीके अपना रहे हैं, ताकि मोदी सरकार गिर जाए। गौर करने पर पता चलता है कि भारत विरोधी विदेशियों की भाषा और देश के भीतर बैठे कतिपय नेताओं की भाषा एक जैसी होती है। कनाडा और अमेरिका को सोचना चाहिए कि आतंकवादियों का समर्थन कर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश को कठघरे में खड़ा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। पश्चिमी देश इस भ्रम में न रहें कि भारत में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। अब जरूरत है कि भारत के सभी विपक्षी दल एक स्वर में अमेरिका सहित उन अन्य देशों का जोरदार विरोध करें, जो भारत को समय-समय पर आंखें दिखाते हैं।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पारिवारिक अविश्वास

'परिवार में भरोसे का दरकता आधार' शीर्षक से प्रकाशित लेख में लेखिका क्षमा शर्मा ने सच ही कहा है कि जब परिवार के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो ऐसे में आदमी कहां और किसके पास जाएगा। परिवार में छोटी-छोटी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा यहां तक कि लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। परिवार में भरोसे का होना सबसे अहम है। जब परिवार में भरोसे की कमी होती है तो यह हर संबंधों को कमजोर कर देता है, लेकिन भरोसा बने कैसे, क्योंकि लोग अधिकतर मामले में केवल अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं। परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो सभी लोगों को आपस में गंभीर विचार कर उसका हल करना चाहिए, क्योंकि समस्या को न जानने से ही बहुत तरह की गलतफहमी होती है और लोग किसी भी बात को दूसरे ढंग से समझकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। परिवार में लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास का न होना एक गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसे दूर नहीं किया जा सकता। विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए ईमानदारी, आपस में सुदृढ़ विचार-व्यवहार और एक-दूसरे का समर्थन आवश्यक है, क्योंकि एक मजबूत और सहयोगी परिवार ना केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक योगदान देता है। पारिवारिक रिश्तों में विश्वास का सबसे बड़ा स्थान है। यदि विश्वास खत्म हो जाएगा तो रिश्ते भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।

मोहित शर्मा, दुंदीचक, गया

पोस्ट

भारत की सबसे बड़ी समस्या खराब शासन है। जैसे-जैसे आप निचले स्तर पर जाते हैं, यह इतना बद से बदतर हो जाता है कि इसका अस्तित्व ही नजर नहीं आता है। पिछले हफ्ते मैंने महाराष्ट्र के एक गांव में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

ट्रेन की पटरियों पर आए-दिन कुछ न कुछ रख कर उन्हें पटरियों से उतारने की साजिश करना और यात्रियों में दहशत फैलाना। अब एक के बाद एक कई हवाई जहाजों में बम की अफवाहें फैला कर यात्रियों, एयरलाइंस और देश को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना। देश इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

इन दिनों चुनावों में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। पहले राजनीतिक दल वोट पाने के लिए रेवड़ी बांटने की घोषणा करते हैं। चुनाव जीतने के बाद अगर केंद्र में समान दल या गठबंधन की सरकार है तो वे चुप रहते हैं और काम चला लेते हैं। विपरीत स्थिति में केंद्र पर धन आवंटित न करने का आरोप लगाते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक परेशान करने वाली मिसाल है।

हर्ष गोयनका@hvgoenka

जनपथ

धमकी मिले विमान को पटरी पर अवरोध,
कैसे हो अब यात्रा जरा कराओ बोध।
जरा कराओ बोध क्रोध आता है सुनकर,
रह जाते हैं लोग किंतु मन में जल भुन कर।
रोज-रोज अफवाह सुनाई देती बम की,
खुराफात यह कौन कर रहा देकर धमकी!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 188

****

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नई दिल्ली ■ सोमवार, 21 अक्तूबर 2024

न्याय का उद्देश्य हर किसी को उसका हक दिलाना है।
- सिसेरो

त्योहारों से ऐन पहले हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबोहवा के बिगड़ने की रिवायत विचलित करने वाली है। उम्मीद करनी चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर सरकारें असंवेदनशीलता छोड़, दीर्घकालीन विजन के साथ इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगी।

हवा में जहर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त तापमान में लगातार कमी से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दीवाली से ठीक पहले यहां हवा की गुणवत्ता जिस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, उससे पर्यावरण व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चिंता की बात अलबत्ता यह भी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इससे जल्द राहत मिलने के संकेत नहीं दिए हैं। दरअसल, जैसे-जैसे ठंड नजदीक आती है, दिल्ली की हवा भी जहरीली होने लगती है, जिसके लिए स्थानीय सरकार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को वजह बताती आ रही है। हालांकि तथ्य कुछ और ही कहते हैं। दरअसल, दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान अक्तूबर की शुरुआत में एक फीसदी से भी कम था, जो अब जाकर ढाई फीसदी के आसपास पहुंचा है। जबकि, यहां गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषकों का प्रतिशत दस फीसदी से भी ज्यादा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, राजधानी में निर्माण गतिविधियों व सड़कों पर जमी धूल का प्रदूषण में योगदान तकरीबन एक से दो फीसदी के बीच है। उल्लेखनीय है कि ठंड का मौसम आते-आते कोहरे की वजह से हवा भारी होने लगती है और उस पर प्रदूषित कण भी जमने लगते हैं, जिससे वह वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती और प्रदूषण बढ़ने लगता है। लेकिन अभी जब वायु में नमी भी उस तरह से नहीं आई है, तब दिल्ली और उससे सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का बढ़ना सवाल पैदा करता है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में धूल विरोधी अभियानों के तहत जुर्माने लगाए जा रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण के नियमों को लागू किया जा रहा है, जो जरूरी भी है, लेकिन वायु प्रदूषण की समस्या का हर साल दीवाली के वक्त विकराल रूप से सामने आना इससे निपटने की रणनीतियों में दीर्घकालिक विजन के बजाय फौरी उपायों पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यमुना के झाग पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन आसन्न

छठ को देखते हुए यह स्थिति डराने वाली तो है ही। एक स्थानीय सर्वे की रिपोर्ट भी चिंतित करने वाली है, जिसके मुताबिक इस वक्त दिल्ली के छत्तीस फीसदी परिवार प्रदूषण संबंधी शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ठंड और बढ़ेगी, दीवाली के वक्त जब प्रदूषक कण वातावरण में स्थिर हो जाएंगे, और अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जाहिर है कि स्वास्थ्य संकट विकराल रूप ले सकता है। प्रदूषण की वार्षिक हो चुकी समस्या प्रशासनिक असंवेदनशीलता को ही दिखाती है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारें गंभीर हों, नागरिकर जागरूक हों और नियमों का सख्ती से पालन हो।

अदालतों का बोझ कम करने की यही राह है

देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्याय मिलने में देरी और वर्षों चलने वाले मुकदमों के खर्च को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया पर जोर देने की बात करते रहे हैं, जिससे सच्चे न्याय की उम्मीद बंधती है।

यह बिल्कुल सही है कि न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। न्याय मिलने में विलंब कई अवसरों पर अन्याय का कारण बनता है। यह भी विदित है कि सामाजिक स्तर पर लोगों या समूहों के बीच विचारों का आदान-प्रदान नहीं होना संघर्षों का कारण है। इसी संदर्भ में कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का महत्व बढ़ जाता है, जिनके जरिये अंतःक्रियात्मक वातावरण बनाकर विवादों का समाधान किया जा सके और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। कदाचित इसी उद्देश्य से हाल ही में देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया पर जोर देने की बात कही है।

सीबीपी श्रीवास्तव
अध्यक्ष, सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली

राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों और प्रधान न्यायमूर्ति द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, जिला और तालुका स्तर पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 4.1 करोड़ है, जबकि उच्च न्यायालय में यह संख्या 59 लाख है। हालांकि उच्चतम न्यायालय सबसे कार्यकुशल न्यायालय है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष लगभग 45,000-50,000 मामलों का निपटारा करता है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 71,000 मामले इसमें भी लंबित हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच सभी अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में औसतन 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है।

न्याय तंत्र की दूसरी बड़ी समस्या वादियों और प्रतिवादियों द्वारा खर्च होने वाली राशि है। ऐसा देखा गया है कि मामलों का निपटारा होने तक कई परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान एक मितव्ययी प्रक्रिया है। विशेषकर पारिवारिक विवादों के मामले में गोपनीयता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों की स्वायत्तता का संरक्षण भी होता है। इसी पृष्ठभूमि में वैकल्पिक समाधान प्रक्रियाओं को समझना समीचीन होगा। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान का

सांविधानिक आधार अनुच्छेद 39-ए है, जो अनुच्छेद 21 से सीधे संबंधित है। अनुच्छेद 39-ए में समान और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान हैं। दूसरी ओर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के तहत मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), सुलह (कॉन्सिलिएशन) मध्यस्थता / और न्यायिक समाधान अथवा लोक अदालत को स्वीकार किया गया है। इनकी प्रक्रियाओं को नियमित करने के लिए इन्हें कानून के तहत शामिल किया गया है।

जैसे, मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 (2021 में संशोधित) के तहत क्रमशः बाध्यकारी निर्णय या प्रस्ताव के जरिये सिविल और शमनीय अपराधों (कम संगीन अपराधों, जैसे चोरी, आपराधिक अतिचार, व्यभिचार आदि) का समाधान किया जाता है। इसी प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम 2021 में एक भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का उल्लेख है, जो मध्यस्थता समझौते को कानूनी आधार देगा।

सबसे बड़ी बात है कि इस कानून में विवाद समाधान के लिए अधिकतम अवधि 180 दिनों की तय की गई है। इससे त्वरित न्याय उपलब्ध कराना सरल होगा। कई अवसरों पर ऐसे समाधान के बाद भी किसी पक्षकार को संतुष्टि नहीं होती। इसलिए यह प्रावधान भी है कि कोई भी पक्षकार मध्यस्थता के दो सत्रों के बाद प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। सिविल और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए वाद-पूर्व मध्यस्थता जहां लंबित मामलों की संख्या पर रोक लगाएगी, वहीं यह सामाजिक स्तर पर अंतःक्रिया बढ़ाकर आपसी संबंधों को मजबूत भी बनाएगी।

जहां तक लोक अदालतों का प्रश्न है, इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39-ए से प्रेरित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किया गया है। स्थायी लोक अदालत (अधिनियम की धारा 22-बी) के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत और ई-लोक अदालत का प्रावधान न्यायतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है। भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन गुजरात में 1999 में किया गया था। लोक अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निर्णय अंतिम होंगे और इनके विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी। इसका अर्थ इन अदालतों का निरपेक्ष होना नहीं है। अपील का प्रावधान नहीं होने का कारण यह है कि ये अदालतें वाद-पूर्व विवाद समाधान करती हैं। इनकी निरपेक्षता को सीमित करने के लिए यह उल्लेख है कि असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में वाद संस्थापित कर सकता है।

न्याय तंत्र तक पहुंच भी भारत में एक बड़ी समस्या रही है। इस तंत्र में तकनीकों के प्रयोग के बाद ई-अदालतों की भूमिका बढ़ी है। यदि ई-लोक अदालतों की भूमिका बढ़ाई जाए, तो न्याय उपलब्धता की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने से ही ऐसा हो सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में आयोजित मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निपटान समझौते के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत द्वारा शीघ्र ही इसे अनुमोदित करने की आशा है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली मध्यस्थता केंद्र में 31 जुलाई तक मध्यस्थता के लिए उपयुक्त 2,86, 631 मामलों में से कुल 2,81,474 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है, जो कुल मामलों का 98.2 प्रतिशत है। यह निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है और न्याय तंत्र में वैकल्पिक प्रक्रियाओं के महत्व का प्रतीक है।

मध्यस्थता के विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, मध्यस्थता सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, जहां विचारों के आदान-प्रदान और सूचना के प्रवाह के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप लाया जाता है। मध्यस्थता के दौरान अमूल्य चर्चा से प्राप्त समाधान व्यक्तियों और समूहों के लिए उनकी शर्तों पर, उनकी समझ में आने वाली भाषा में सच्चा न्याय सुनिश्चित करता है और एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जो उनकी भावनाओं की रक्षा करता है और जो उनके अस्तित्व और आत्मा के करीब होता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नेल्सन मंडेला

मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे कभी मार सकती है, तो वह है उन लोगों के हिस्से में खुशी नहीं दे पाना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है।

मानवीय करुणा हमें एक-दूसरे से जोड़ती है

मैंने आजादी की ओर जाने वाले उस लंबे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है और कोशिश की है कि लड़खड़ाऊं नहीं। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे कभी मार सकती है, तो वह है उन लोगों के हिस्से में खुशी नहीं दे पाना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर मैं अपने जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा उन्हें खुश करने में लगा सकता हूं, तो मैं खुशी महसूस करूंगा। यह बात मेरे जेहन में हमेशा रहती है कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक मजबूत संयोजन होता है। मानवीय गरिमा की कमी का परिणाम है कि आज बच्चे कस्बों की सड़कों पर भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके माता-पिता परिवार चलाने के लिए सुबह ही काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं। इस तरह उनके पास कोई भी नहीं होता, जो उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करे। इससे नैतिक मानकों में गिरावट आती है, अवैध कार्यों में खतरनाक वृद्धि होती है और हिंसा बढ़ती है। इन सबको रोकने के लिए समाज में शांति स्थापित करनी होगी। इसके लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना होगा, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग हम दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा के बिना आपके बच्चे कभी भी उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, जिनका उन्हें सामना करना है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देना और यह समझाना बहुत जरूरी है कि उन्हें अपने देश के लिए भूमिका निभानी चाहिए।

हम हर तरह की परिस्थितियों से ऊपर उठ कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज मैं हमेशा से ही जानता हूं कि हर इन्सान के दिल की गहराई में दया और उदारता होती है, उसे स्वयं को शिक्षित करके उन्हें बाहर लाना चाहिए। हमारी मानवीय करुणा हमें एक-दूसरे से जोड़ती है-दया या संरक्षण के भाव से नहीं, बल्कि ऐसे इन्सानों के रूप में, जिन्होंने सीखा है कि कैसे अपने साझा दुख को भविष्य की आशा में बदला जाए। एक दिन, मैं अपने घर के सामने वाले बगीचे के पास खड़ा था और मैंने एक पेड़ पर बैठी गौरैया पर बंदूक तान दी। वहीं मौजूद आर्थर की पत्नी हेजल मुझे देख रही थीं और मजाक में बोलीं कि मैं निशाना नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अभी उन्होंने अपनी बात पूरी ही की थी कि गौरैया जमीन पर गिर पड़ी। मैं उनकी ओर मुड़ा और शेखी बघारने ही वाला था कि हेजल का बेटा पॉल, जो तब लगभग पांच साल का था, आंखों में आंसू लिए मेरी ओर मुड़ा और बोला, आपने उस चिड़िया को क्यों मारा? उसकी मां दुखी होगी। मेरा भाव तुरंत गर्व से शर्म में बदल गया। मुझे लगा कि इस छोटे लड़के में मुझसे कहीं ज्यादा इन्सानियत है।

दयालु बनें

जीवन एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है। कई चीजों में से एक, जो इसे सार्थक बनाती है, वह है दूसरों के प्रति दयालुता और खुद के प्रति भी वही दयालुता और करुणा दिखाना। दयालुता बाधाओं को तोड़ सकती है, किसी व्यक्ति के पूरे भाव को बदल सकती है और एक चिरस्थायी रिश्ता बना सकती है। हमेशा याद रखें, दयालुता का सबसे छोटा कार्य सबसे बड़े इरादे से भी अधिक मूल्यवान है।

सूत्र

दूसरा पहलू

लंदन स्थित 'द इंडिया क्लब' को शायद ही कोई भारतीय भुला पाए। वह हमारी स्मृतियों का भंडार था।

लंदन में बंद हुआ भारतीयों का प्रिय 'इंडिया क्लब'

प्रवासियों के आने की राह देखने वाला लंदन स्थित 'द इंडिया क्लब' को शायद ही कोई भारतीय भुला पाए। वह हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलनकारियों और राष्ट्रवादियों का मात्र गढ़ ही नहीं था, बल्कि हमारी स्मृतियों का भंडार था, जिसे अब बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। यह क्लब प्रवासी भारतीयों को परदेश में अपनेपन का एहसास करवाती थी। क्लब के बंद होने से भारतीय संस्कृति की तमाम भूली-बिसरी यादें भी धूमिल हो गईं। इसे वर्ष 1951 में वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने स्थापित किया था। बीते 70 वर्षों से यह क्लब स्वतंत्रता की लड़ाई, सांस्कृतिक इतिहास और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का केंद्र बना हुआ था।

रमेश ठाकुर

'द इंडिया क्लब' बीते 70 वर्षों से स्वतंत्रता की लड़ाई, सांस्कृतिक इतिहास और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का केंद्र बना हुआ था।

लंदन पहुंचने वाला कोई भी हिंदुस्तानी क्लब का दीदार करना नहीं भूलता था। क्लब में भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ी बेशुमार निशानियां हैं। क्लब के मालिक वहां होटल बनवाना चाहते हैं।

भारत से लंदन पहुंचने वाला कोई भी हिंदुस्तानी उस क्लब का दीदार करना नहीं भूलता था। पिछले वर्ष सितंबर-2023 में क्लब को बंद करने का निर्णय उसके मालिकों ने लिया था। हालांकि क्लब को उसके मालिक नहीं चलाते थे, बल्कि उसके प्रोपराइटर भारतीय मूल के यॉर्कर मार्क और उनकी बेटी फिरोजा किराए पर चलाते थे। बीते एकाध दशक से क्लब के मालिक लगातार किराया बढ़ाते जा रहे थे और क्लब को खाली करने का कानूनी नोटिस भी भिजवा रहे थे। हालांकि फिरोजा ने क्लब को बचाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः पिछले महीने मालिकों के पक्ष में ही फैसला सुना दिया गया।

क्लब में भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ी बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। वह टेबल-कुर्सी, जिस पर पंडित नेहरू आकर अक्सर तुलसी पत्ती की चाय पिया करते थे। उनके लिखे खत, उनके इस्तेमाल किए बर्तन इत्यादि भी क्लब में मौजूद हैं। क्लब में नेहरू, माउंटबेटन, वीके मेनन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, दादाभाई नौरोजी के अलावा शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे मौजूदा पीढ़ी के अनगिनत नेताओं का आना-जाना हमेशा रहा। ब्रिटेन के कुछ कट्टरपंथी दशकों से इस क्लब को बंद करवाने की मांग कर रहे थे। क्लब मालिक वहां आलीशान होटल बनवाना चाहते हैं। क्लब में कुल 26 कमरे थे, भीतर एक बड़ा गार्डन और लॉन था। वहां एक साथ पांच सौ लोग समा सकते थे। क्लब पॉश इलाका 'चेरिल क्रॉस के नजदीक भूखंड संख्या-143 के स्टैंड कॉन्टिनेंटल' में स्थित है, जिसका कभी कृष्ण मेनन के नेतृत्व में इंडिया लीग के सदस्यों ने अपने करकमलों से श्रीगणेश किया था। आज उनकी आत्माएं भी रोती होंगी। उनकी तमाम यादें क्लब से जुड़ी थीं।

आंकड़े

इलेक्ट्रॉनिक निर्यात

तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो निर्यात के कुल हिस्से का लगभग 33 फीसदी है।

तमिलनाडु	32.84%
कर्नाटक	15.78%
उत्तर प्रदेश	15.32%
महाराष्ट्र	10.62%
गुजरात	9.43%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। स्रोत : Eco. Survey

संत सुंदरमूर्ति विवाह की शर्त का उल्लंघन करने के चलते अंधे हो गए। लेकिन भगवान की भक्ति से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई।

संत सुंदरमूर्ति की भक्ति

तमिल प्रांत के एक छोटे से गांव में संत सुंदरमूर्ति का जन्म हुआ। इनके माता-पिता हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते और समाज सेवा में ही अपना मन लगाते थे। एक समय बाद संत सुंदरमूर्ति ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव जाकर भगवान का गुणगान करेंगे। संत सुंदरमूर्ति कभी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगते थे। प्रभु स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

एक बार एक व्यक्ति ने संत सुंदरमूर्ति को अपने घर पर आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने अपनी दो लड़कियां उन्हें अर्पित कर दीं। सुंदरमूर्ति ने अपने उदात्त व्यक्तित्व एवं चरित्र के कारण उन्हें अपनी कन्या मानकर स्वीकार कर लिया।

मद्रास के एक गांव में एक कन्या ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी संत से ही विवाह करेगी या हमेशा के लिए अविवाहित रहेगी। एक दिन संत सुंदरमूर्ति उसी गांव में पहुंचे और उस कन्या से विवाह किया। शर्त यह थी कि उस गांव की सीमा से उन्हें बाहर नहीं जाना है। लेकिन संत सुंदरमूर्ति एक दिन किसी कारण गांव से बाहर चले गए। नतीजतन वह अंधे हो गए और उन्हें अन्य कई तरह के कष्ट भी झेलने पड़े। तब उन्होंने भगवान की भक्ति की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान संत सुंदरमूर्ति की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी दोनों आंखों में पुन रोशनी लौट आई। उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग अड़तीस हजार पद लिखे।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 जनवरी,1961

चीन के कारखानों में अच्छे माल का उत्पादन नहीं हो रहा

चीन के कारखानों में अच्छे माल का उत्पादन नहीं हो रहा
कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार किया

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव में यह स्वीकार किया है कि देश में भारी उद्योगों में बनने वाला माल अच्छा नहीं बन रहा। उन्होंने आगे कहा कि इन कारखानों के उत्पादन के स्तर में सुधार करना जरूरी है।

अश्लील वीडियो और कठघरे में नैतिकता

जब भी कोई दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में आता है, कुछ लोग उससे जुड़े तथाकथित वीडियो इंटरनेट पर खोजने में जुट जाते हैं।

मुकुल श्रीवास्तव

मुद्दा

इस बदलते दौर में तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाया है, पर इसके साथ ही मानवीय संवेदनाओं पर गहरे घाव भी किए हैं। जैसे-जैसे तकनीकी प्रगति हो रही है, हमारे समाज में संवेदनहीनता, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों का एक नया चेहरा उभर रहा है। अब अपराधियों के पास डिजिटल तकनीक के रूप में एक ऐसा हथियार है, जिसे वे अपनी घिनौनी मंशाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तकनीक की आड़ में अश्लील वीडियो खरीदने-बेचने का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है।

समाज का एक बड़ा तबका ऐसे वीडियो को इंटरनेट पर खोजते और देखते हुए इसे बढ़ावा दे रहा है। जब भी कोई दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में आता है, कुछ लोग उससे जुड़े तथाकथित वीडियो इंटरनेट पर खोजने में जुट जाते हैं। पब्लिका द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट इस घिनौनी प्रवृत्ति को उजागर करती है। हाल में हुई कोलकाता की एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या

और दुष्कर्म की खबरों के सुर्खियों में आने के बाद गूगल ट्रेंड्स पर पीड़िता के नाम से अश्लील वीडियो की खोज में वृद्धि देखी गई। इससे पहले जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में भी ऐसा ही देखा गया था। ऐसे वीडियो देखने वाले पीड़िता के दर्द को महज मनोरंजन का साधन समझते हैं।

भारत में दुष्कर्म और असहमति से बनाए गए सेक्स वीडियो का बड़ा कारोबार है। पहले ये वीडियो गोपनीय ढंग से सीडी और पेन ड्राइव के माध्यम से बेचे जाते थे। लेकिन इंटरनेट के आने के साथ यह काला कारोबार अब इन्क्रिप्टेड ऐप्स पर चला गया है, जहां इन वीडियो क्लिप्स को रोकना संभव नहीं है।

फैक्ट चैकिंग संस्था बूम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम से ये अपराधी लिंक के जरिये सामग्री को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ले जाते हैं, जहां से यह काला कारोबार होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया साइट्स पर यदि आप ऐसे एक आपत्तिजनक पेज को फॉलो करते हैं, तो एल्गोरिदम और भी ऐसे अकाउंट आपको सुझाता है। लिंक के लिए यूपीआई, इंस्टेंट पे से भुगतान करने के बाद इच्छुक ग्राहक को टैराबॉक्स और क्लाउड एग्रीगेटर ऐप्स की ओर ले जाया जाता है। जहां वे इन अवैध और अमानवीय सामग्री तक पहुंच कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोडिंग के बाद इसका पता लगाना या रोकना लगभग असंभव हो जाता है।

अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में बाल यौन शोषण सामग्री का सबसे बड़ा निर्माता है। पॉक्सो ऐक्ट जैसे कठिन प्रावधानों और सजा के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री भरी हुई है। यह व्यापार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इसे रोकने में असमर्थ नजर आ रही हैं। इन चैनलों को बंद करना भी एक अस्थायी समाधान ही है, क्योंकि नए चैनल्स कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाते हैं। इस अनैतिक व्यापार ने न केवल कानून को चुनौती दी है, बल्कि समाज की नैतिकता और संवेदनशीलता को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। एआई जैसी तकनीक आने से अपराधियों के हौसले और बढ़ गए हैं, जहां तकनीक की मदद से सामान्य तस्वीर को फेक न्यूड तस्वीरों और डीपफेक वीडियो में बदला जा सकता है।

साल 2023 में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद यूट्यूब ने अपनी नई कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक, अक्तूबर से दिसंबर के बीच करीब 25 लाख वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया था। वहीं, टेलीग्राम पर 'स्टॉप चाइल्ड अब्यूज' चैनल के डेटा के मुताबिक, इस साल अब तक करीब छह लाख 70 हजार चैनल्स को बैन किया जा चुका है। पॉर्नोग्राफी और इस तरह की यौन हिंसा के वीडियो देखने की आदत के बीच गहरा ताल्लुक है। मनोचिकित्सक मानते हैं कि ऐसी सामग्री देखने से व्यक्ति की यौन और हिंसा के प्रति सामान्य दृष्टि विकृत हो गई है। यौन शिक्षा की कमी वाले भारत जैसे देश में यह समस्या को और गंभीर बना देती है। मंकी इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, पॉर्न वीडियो देखने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, जिनमें 18 से 24 साल के युवाओं की संख्या 24 प्रतिशत है।

जाहिर है, इस समस्या का समाधान हम सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाकर ही कर सकते हैं। हमें ऐसी सामग्री के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और समझना होगा कि ऐसे वीडियो पर हर क्लिक, हर शेयर किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

चिंतन

रेलवे के बाद विमानन में दहशत की कोशिश

विश्लेषण

अवधेश कुमार

इस समय भारतीय विमानन क्षेत्र को फियर टेरर का सामना कर रहा है। विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी जा रही है। 14 अक्टूबर से अब तक 90 विमानों को फेक धमकी दी जा चुकी हैं। हर फेक धमकी से एयरलाइंस को तीन करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, हजारों यात्री विमान परिचालन में हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। चूंकि यह धमकी रोज दी जा रही है, इसमें विमानों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह किसी सिरफिरे का काम नहीं हो सकता है। यह एक पैटर्न है, जिस पर सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। ऐसे ही कुछेक दिन पहले रोज किसी न किसी ट्रेन रूट को बाधित किया जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेन हादसा होते-होते बचा। भारतीय रेल विशाल नेटवर्क है और रोजाना दो करोड़ से अधिक लोग ट्रेन में सफर करते हैं, इसलिए रेलयात्री के मन में असुरक्षा का डर पैदा कर रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पहले रेल यात्रियों में डर, अब विमान यात्रियों में डर। यह डर आतंकवाद है, जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। रेल और विमानन क्षेत्र को असुरक्षित कर देने से इन पर गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को इस फियर टेरर को गंभीरता से लेना चाहिए। यह आतंक का नया मॉड्यूल हो सकता है। विमानों को धमकी पर गृह मंत्रालय ने जरूर रिपोर्ट मांगी है, सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है, लेकिन वास्तविकता में विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फौरी एक्शन से कुछ खास नहीं प्राप्त होगा। सरकार को इसकी तह में जाना चाहिए। क्या यह देश के अंदर किसी प्रतिबंधित ग्रुप की सुनियोजित हरकत तो नहीं है? क्या इसमें दुश्मन पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियों के हाथ तो नहीं हैं? देश के अंदर भी कई विध्वंसक, अलगाववादी, आतंकी, नक्सलवादी, उग्रवादी ताकतें हैं, जो दुश्मन मुल्कों की कठपुतलियां हैं और चंद टुकड़ों के लिए अपने मुल्क को अस्थिर करने में जुटे रहते हैं। सरकार को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। भारतीय रेल और विमानन क्षेत्र दुश्मनों के निशाने पर हैं। विमान व रेल यात्रा का सुरक्षित होना जरूरी है। ये भारत की लाइफलाइन हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों के सात एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। सरकार मेट्रो शहरों के साथ टियर दो और तीन श्रेणी के शहरों में भी विमान सेवा का विस्तार कर रही है। परिवहन के विभिन्न क्षेत्र को बढ़ावा देकर कनेक्टिविटी को तेज और मजबूत बनाया जा रहा है, इसके लिए सुरक्षा का माहौल बहुत जरूरी है। विमान में बम होने की झूठी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसके पैटर्न को समझना चाहिए और इसके पीछे के टेरर मॉड्यूल का पता लगाना चाहिए। सरकार के पास सभी तरह के सुरक्षा व जांच तंत्र हैं। इजराइल के साथ बेहतर संबंध के चलते भी भारत इजराइल विरोधी आतंकी गुटों के निशाने पर रहता है। उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक ने जरूर भरोसा दिलाया है कि भारतीय आसमान पूरी तरह से सुरक्षित है, यात्रियों को बिना डरे यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जिस मात्रा में धमकियां मिल रही हैं, आपात लैंडिंग हो रही हैं, उसमें यात्रियों व विमान कर्मियों में सुरक्षा का भाव पैदा होना कठिन है, क्योंकि फेक धमकी देने वाले पकड़े नहीं गए हैं, जिससे इसके पीछे का मकसद पता चले। रेल और विमान यात्रा को सुरक्षित बनाना सरकार की महती जिम्मेदारी है।

संगठित रहकर ही चुनौतियों का हल

आजकल घटनाएं इतनी तेजी से घटती और बदलती हैं कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर आवश्यक गहन चर्चा और विश्लेषण नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के महत्वपूर्ण विजयादशमी उद्बोधन के संदर्भ में हुआ। संघ का संगठन परिवार इस समय विश्व स्तर पर सबसे बड़े जन समूह और संगठनों वाला विचार परिवार है। सरसंघचालक का हर वक्तव्य उनके लिए मार्गदर्शन के समान होता है। विजयदशमी संघ का स्थापना दिवस है। इस कारण भी नागपुर से दिए भाषण का सर्वाधिक महत्व हो गया है। ऐसा पहली बार देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से डा. भागवत के भाषण का लिंक रिपोस्ट किया और आग्रह किया कि इसे अवश्य सुना जाए। इस नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है। डॉ. भागवत विजयादशमी के हर भाषण के आरंभ में भारत राष्ट्र के रूप में किस तरह सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और विश्व में इसकी महिमा, प्रतिष्ठा और साख कैसे बढ़ी है इसकी आवश्यक चर्चा करते हैं। स्वाभाविक ही इससे स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के अंदर भारत को लेकर सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना सशक्त होती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।

ऐसा पहली बार देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से डा. भागवत के भाषण का लिंक रिपोस्ट किया और आग्रह किया कि इसे अवश्य सुना जाए। इस नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है। डॉ. भागवत विजयादशमी के हर भाषण के आरंभ में भारत राष्ट्र के रूप में किस तरह सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और विश्व में इसकी महिमा, प्रतिष्ठा और साख कैसे बढ़ी है, इसकी आवश्यक चर्चा करते हैं। स्वाभाविक ही इससे स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के अंदर भारत को लेकर सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना सशक्त होती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।

आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर मैं बोलने नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस समय भारत और विश्व के लिए चुनौतियां एवं खतरे ऐसे खड़े हुए हैं जिनको समझाना और उनका सामना करते हुए समाप्त करना और अपरिहार्य हो गया है। इसमें उन्होंने हिंदू समाज को ही स्वाभाविक रूप से केंद्र में रखा। इसका कारण वह लगातार बताते रहे हैं कि हिंदुओं का संस्कार, चरित्र, जीवन मूल्य और जीवन दर्शन ही ऐसा है जिसमें संपूर्ण विश्व के समुत्कर्ष, कल्याण, शांति - सद्भाव के लिए जीने और काम करने का आधार होता है। इसलिए हिंदू संगठित रहें, खतरों के प्रति सतर्क और इसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हों जिससे भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने सही लक्ष्य को पहचानते हुए सशक्त रह पाएगा तभी यह संभव होगा। अगले दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी - 'डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को समझना होगा कि दुर्बल व असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देना है।' अगर देखें तो निस्संदेह यह उनके भाषण का प्रमुख सूत्र था किंतु ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने नवरात्र की चर्चा करते हुए बताया, उस पंक्ति को देखिए। 'इसी साधना से विश्व के सभी राष्ट्र अपना- अपना उत्कर्ष याद कर नए सुख, शांति व सद्भावनायुक्त विश्व को बनाने में अपना योगदान करेंगे। उस साधना में आप सभी आमंत्रित हैं।' उनकी उन्होंने एक गीत की पंक्ति दोहराई –हिंदू भूमि का कण-कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल -थल से अंबर से फिर हिंदू की जय - जयकार उठे, जग जननी की जयकार उठे। तो यह साधना कौन सी है? नवरात्रि में देवी वास्तव में देवताओं के शक्तियों की पुंज थीं लेकिन शक्तिशाधना शील के साथ। इसीलिए उन्होंने कहा कि संघ की प्रार्थना में कोई परास्त न कर सके ऐसी शक्ति और विश्व विनम्र हो, ऐसा शील भगवान से मांगा है। विश्व के, मानवता के कल्याण का कोई काम अनुकूल परिस्थिति में भी इन दो गुणों के बिना संपन्न नहीं होता। विश्व की मंगल साधना में मौन पुजारी के नाते संघ लगा है तो उसके पीछे यही सोच है। इसलिए संगठित होने का अर्थ दूसरे को डराना या हमलावर होना

नहीं बल्कि कल्याण के लिए शील संपन्न शक्ति साधना है। उनकी इस बात से हर भारतीय को सहमत होना चाहिए कि भारत विश्व में प्रमुखता पा रहा है तो ऐसी शक्तियां और देश हैं जिन्हें अपने निहित स्वार्थ पर खतरा नजर आता है और वह अनेक तरीकों से भारत को कमजोर और अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।

इसके दुनिया में उदाहरण हैं कि चाहे देश पर आक्रमण करना हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अवैध अथवा हिंसक तरीकों से उलट देना हो, अंदर विद्रोह करना हो, ऐसे प्रयास चलते रहे हैं और भारत के विरुद्ध चल रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसक तख्तापलट की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू समाज पर जिस तरह अकारण नृशंस अत्याचार हुए उसके विरुद्ध हिंदू समाज संगठित होकर स्वयं बचाव में घर के बाहर आया इसलिए बचाव हुआ किंतु वह समाप्त नहीं हुआ है। इससे भारत में कई प्रकार के खतरे बढ़े हैं, इसलिए विश्वभर के हिंदुओं और भारत सरकार के सहयोग की अल्पसंख्यक हिंदुओं को आवश्यकता है। यहीं पर उन्होंने कहा कि असंगठित रहना व दुर्बल रहना, यह दूसरों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है। चूंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान में भी मिलाने की बात हो रही है इसलिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरे खतरे के रूप में उन्होंने डीप स्टेट, वोकिजम, कल्चरल मार्क्सिस्ट की चर्चा करते हुए कहा कि यह सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित शत्रु हैं और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं तथा जहां-जहां जो भी भद्र मंगल है उसका पूरी तरह नाश इनकी कार्य प्रणाली का अंग है। सच है कि देश में कृत्रिम तरीके से मांग, आवश्यकता अथवा समस्या के आधार पर अलगाव के लिए प्रेरित करते हैं, असंतोष को हवा देते हैं और शेष समाज से अलग व्यवस्था के विरुद्ध उग्र बनाते हैं। समाज में टकराव की संभावनाओं को ढूंढ कर टकराव खड़े करते हैं और इस तरह चारों ओर अराजकता और भय का वातावरण पैदा किया जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत में यह स्थिति हमारे चारों ओर है। दुर्भाग्य से सत्ता के लिए स्पर्धा में अनेक दलों ने यही पद्धति अपनायी और इसकी क्षति देश को हो रही है। इसमें संस्कार युक्त परिवार और समाज परंपरा में दोष उत्पन्न हो गए हैं और हर स्त्री को माता के रूप में देखने का आचरण कमजोर हुआ है। इसके कारण बलात्कार और अन्य शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं।

सीमा क्षेत्र से लेकर चारों ओर संकट खड़ा करने तथा बिना कारण कट्टरपन को उकसाने की घटनाएं हमारे सामने हैं जब हिंदू धर्म यात्राओं पर अकारण पथराव और हमले हो रहे हैं तथा बिना कारण हिंसा व भय पैदा करने की घटनाएं जिसे डॉक्टर भागवत ने गुंडागर्दी कहा और यही सच है। चूंकि यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है इसलिए इसे तुरंत नियंत्रित करना, उपद्रवियों को दंडित करना प्रशासन का काम है लेकिन उन्हें हम तक पहुंचने से रोक कर अपने प्राण व संपत्ति की रक्षा का दायित्व तो समाज का ही है। लेकिन जब तक हिंदू समाज जातियों में बंटा रहेगा तब तक यह संभव नहीं होगा, इसलिए मोहन भागवत की यह बात बिल्कुल उचित है कि समाज के सभी वर्गों में कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए।इस तरह डॉ. भागवत ने भारत में व्याप्त सभी खतरों, उनके कर्म और यहां तक कि उनके निदान की भी बात की और अगर आपके अंदर कोई वैचारिक घृणा और दुराग्रह नहीं है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में सद्भावना व संतुलन लाकर शांति और बंधुता की ओर बढ़ना है तो भारत को विशेषकर हिंदुओं को अपने को शक्तिशाली बनाए रखना होगा । बलहीन को कोई नहीं पूछता। इसीलिए उन्होंने संगठित होने की बात की तथा असंगठित होने को अत्याचार बताया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

स्वास्थ्य

बाल मुकुन्द ओझा

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा रहा मोटापा

आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन ने देश के नौनिहालों से लेकर किशोर, युवा और बुजुर्ग तक को अपने आगोश में ले लिया है। इसके फलस्वरूप देश और दुनियाभर में मोटापे की समस्या गंभीर रूप से उत्पन्न हो गई है। विशेषकर व्यस्क आबादी इसकी चपेट में आ गई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें स्वाद को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कृत्रिम योजक या रसायन होते हैं। आप प्रत्येक पैकेज के पीछे लगे लेबल को पढ़कर किसी विशेष खाद्य उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की पहचान कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है 1990 के बाद से दुनियाभर के व्यस्कों में मोटापा दो गुना से अधिक बढ़ गया है। इस अवधि में किशोर आबादी में मोटापा चार गुना बढ़ा है। आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अधिक उपयोग से 2022 तक करीब 43 प्रतिशत व्यस्कों का अधिक वज़न बढ़ा है वहीं 16 प्रतिशत मोटापे के शिकार हुए हैं। विश्व मोटापा एटलस 2024 के अनुमानों के मुताबिक 2035 तक लगभग 330 करोड़ व्यस्क मोटापे से ग्रस्त होंगे। साथ ही 5 से 19 साल की आयु सीमा के 77 करोड़ से अधिक किशोर और युवाओं को मोटापा घेर लेगा। भारत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2022 तक सवा सात प्रतिशत से अधिक व्यस्क मोटापे की चपेट में थे। नेशनल फैमिली हेल्थ और मेडिकल पत्रिका लेसेन्ट आदि के अनेक प्रमाणिक सर्वेक्षणों में भी कहा गया है कि हमारे देश में पेट के मोटापे की समस्या सर्वाधिक है। यह समस्या महिलाओं में 40 और पुरुषों में 12 प्रतिशत पाई गई है। स्वास्थ्य के प्रति इस गंभीर खतरे को हमने समय रहते सख्ती से नहीं रोका तो यह देश में नशे से भी अधिक भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा और इसके जिम्मेदार केवल हम ही होंगे। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में देश में दबे पांव प्रवेश करने वाले जंकफूड जिसे फास्ट फूड भी कहते है, ने हमारे सम्पूर्ण पाचनतंत्र पर कब्जा कर स्वास्थ्य के जीवन तंत्र को बिगाड़ कर रख दिया है। फास्ट फूड आज घर-घर में अल्पाहार के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। जंकफूड में कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा होती है। इसमें अधिकतर तलकर बनाए जाने वाले व्यंजनों में पिज्जा, बर्गर, फ्रैंकी, चिप्स, चॉकलेट, पेटीज मुख्य रूप से शामिल हैं। एक आहार विशेषज्ञ अनुसार बर्गर में 150-200, पिज्जा में 300, शीतल पेय में 200 और पेस्ट्री, केक में करीब 120 किलो कैलोरी होती है जो आजकल लोगों पर मोटापे के रूप में हावी हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलू के चिप्स हों या कोक का वह गिलास जिसका आप दिन या रात के किसी भी समय आनंद लेते हैं, आप नहीं जानते होंगे कि आप जो नाश्ता करना पसंद करते हैं वह वास्तव में प्रसंस्कृत भोजन है।

कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें किसी न किसी तरह से बदलाव किया जाता है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आता है। आमतौर पर, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें उनकी शेल्फ लाइफ या उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए बदल दिया गया है, लेकिन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम भी होते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आधुनिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। इनको न्यूनतम प्रसंस्कृत, भारी प्रसंस्कृत या अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब किसी खाद्य उत्पाद के स्वाद, स्थिरता और बनावट को बढ़ाने के लिए कई सामग्रियों को जोड़ा जाता है, तो आप इसे भारी या अति-प्रसंस्कृत कह सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार, 33.66 फीसदी भारतीयों ने स्वीकारा है कि वे हफ्ते में कम से कम दो बार जंकफूड या रेडीमेड फ़ूड खाते ही हैं। भारत में रेडीमेड फूड का उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वार्षिक प्रगति दर 40 फीसदी बताई जाती है। तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण, व्यस्त जीवन-शैली और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे बदलाव ने भारत में लोगों के जीवन-यापन के तरीके को बदल कर रख दिया है। इन बदलावों के फलस्वरूप लोगों ने घर पर खाना पकाने और खाने की आदत में भी बदलाव किया है। महानगरों में रहने वाले परिवारों की तैयार भोजन, फास्ट फूड और जंकफूड पर निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है। अब तो इनकी पहुंच घर-घर में हो गई है। यह बच्चों के प्रिय नाश्ते में शुमार हो गया है। देखा तो यह गया है कि पूरा परिवार अल्पाहार में फास्ट फूड का उपयोग करने लगा है। आहार विशेषजों के अनुसार फास्ट फूड कभी-कभार तो ठीक है लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। स्वाद के पीछे के जहरीले रसायन को पहचान कर हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी, इसी में हम सबकी भलाई है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सारी जीवन-ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है

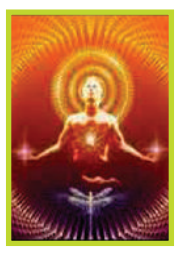

संकलित

दर्शन

हम दीपावली अमावस की रात को मनाते हैं! दीयों की पंक्तियां बाहर जला लेते हैं, पर दीये तो भीतर नहीं जा सकते। भीतर की अमावस तो अमावस ही रहेगी। धोखे छोड़ो! इसे स्वीकार करो कि तुम बुझे हुए दीपक हो। अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो। अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जागा। कहां चूक हो गई है? वस्तुतः हमारी सारी जीवन-ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। इस बहिर्यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े हैं। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। तुम्हारा सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है। सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो। जिसने स्वयं को न देखा, उसने कुछ भी न देखा। तुम्हारे भीतर का दीया कैसे जले, सच्ची दीपावली कैसे पैदा हो? उसके सूत्र हैं बड़े मधु-भरे! पीओगे तो जी उठोगे। ध्यान धरोगे इन पर, संभल जाओगे। डुबकी मारोगे इनमें, तो तुम जैसे हो वैसे मिट जाओगे और तुम्हें जैसा होना चाहिए, वैसे ही प्रकट हो जाओगे। सूत्र यह है कि जिस प्रकाश को तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारी खोज के कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े जाते हो। थकते हो, गिरते हो। जिसे तुम खोजने चले हो, उस मालिक ने तुम्हारे घर में बसेरा किया हुआ है। तुम जिसे खोजने चले हो, वह अतिथि नहीं है, आतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा है। वह जो गंतव्य है, कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था है। अगर उसे देखना हो, उसके प्रति चैतन्य से भरना हो तो आंखें उलटाना सीखना पड़ेगा। यही ध्यान है।

एक लकड़ी का कटोरा

संकलित

प्रेरणा

एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहु-बेटे के यहां शहर रहने गया। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका चार वर्षीया पोता एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन वृध्द होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। बहु-बेटे कुछ दिनों तक तो ये सब सहन करते रहे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिता जी आप यहां पर बैठ कर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वहीं अकेले में बैठ कर अपना भोजन करने लगा, यहां तक की उनके खाने-पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठ कर खाना खाते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता, और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले, उस छोटे बालक को उसके माता-पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखाः तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें, और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता-पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आये, और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया।

अंतर्मन

आज की पाती

दमघोंटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन?

हमारा देश जो सारी दुनिया में प्रकृति प्रधान और शस्य श्यामला वसुंधरा के सौंदर्य से प्रसिद्ध है, उसकी छवि को हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण बढ़ाकर खराब करने का काम किया है। माना कि सरकारों की गलत नीतियां प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हम खुद प्रदूषण से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते? अगर हमने स्वार्थी होकर पर्यावरण को संभालने के लिए अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई और हवा में प्रदूषण फैलाने वाले गलत कामों पर पाबंदी नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा सांस लेना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कुदरत ने तो हमें साफ-सुथरी हवा सांस लेने के लिए दी थी, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए इसमें जहर घोलकर इसे दमघोंटू बना लिया है। इस पर रोक लगनी चाहिए। *– रविंद्र जोशी, बिलासपुर*

ट्रेंड

ठीकरा अधिकारियों के सिर

भाजपा की ये पुरानी आदत है कि पहले सफेदपोश बनकर चुपचाप भ्रष्टाचार करती है और जब पोल खुल जाती है तो उसका ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ देती है। जनता पूछ रही है कि सरकार की लगाम क्या अधिकारियों के हाथ में है?

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

करुणा की परिभाषा

एक कॉलेज छात्र ने पूछा, "करुणा की पुरानी व नई परिभाषाओं में क्या अंतर है?" मेरा उत्तर था, "करुणा की पुरानी परिभाषा 'एक साथ पीड़ा सहना' और नई परिभाषा 'एक साथ मिलकर समाधान करना' है।

-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

बागडोर अपने हाथों में लें

आप जो भी भावना महसूस करते हैं, हर विचार जो आपके दिमाग में आता है, आप अपने आस-पास की दुनिया को कैसे देखते हैं, और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं - यह सब आपके नियंत्रण में है। अपने जीवन की बागडोर मजबूती से अपने हाथों में लें।

-हर्ष गोयनका, कारोबारी

विनम्रता सबसे खूबसूरत

विनम्रता रचनात्मकता की मूलभूत शक्ति है। अपने व्यक्तिगत अहंकार को निखारना सीखें और अपने रचनात्मक अहंकार को उभरते हुए देखें.. यह आपके पास मौजूद सबसे खूबसूरत चीज है..

-शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

वैक्सीन संबंधी भ्रांतियां रंगमंच के जरिए की दूर

लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अमित शर्मा ने वैक्सीन लेने में लोगों की हिचकिचाहट और इसे लेकर फैली भ्रांतियों को रंगमंच के जरिये जीवंत करके लंदन के किल्न थिएटर के कलात्मक निदेशक के रूप में अपनी पारी का आगाज किया। नाटक 'पिन्स एंड नीडल्स' का प्रदर्शन हाल ही में पूरी दुनिया में किया गया है और इसका प्रदर्शन अगले सप्ताहांत तक होगा। रॉब ड्रमंड द्वारा लिखित इस नाटक के जरिये कोविड के टीके और दुनिया भर में बच्चों से जुड़े अन्य टीकों को लेकर हुई राजनीति और फैलाई गई भ्रांतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता गवी सिंह चेरा मुख्य किरदार रॉब की भूमिका में हैं। शर्मा का कहना है, 'इस नाटक से निश्चित रूप से (टीकों के पक्ष और विपक्ष में) बहस को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ से इससे एक दर्शक के लिए अपने से विपरीत विचारों वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने और उसे समझने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'दर्शकों के लिए मेरा जुनून है कि वे खुद को और अपनी आवाज को प्रतिबिंबित होते देखें। यह उन लोगों को भी समझाने में मदद कर सकता है, जो समान पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन हमारे अभिनय से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।'

ऑफ बीट

घर के कामकाज करने वाले रोबोट बनाने में लगेगा समय

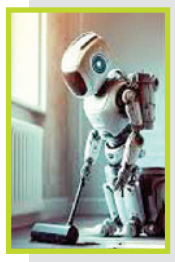

हाल ही में टेस्ला की प्रदर्शनी में चलते-फिरते, बोलते-नाचते 'ऑप्टिमस' रोबोट ने काफी उत्साह पैदा किया था। भले ही यह अब भी भविष्य की एक आकर्षक झलक हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रोबोट उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए, 'सोफिया' को ही लें, जिसे 2016 में टेक्सास स्थित हैनसन रोबोटिक्स ने बनाया था। इसी तरह हमने बोस्टन डायनेमिक्स के 'एटलस' जिमनास्टिक्स, ब्रिटेन निर्मित अमेका रोबोट 'वेकिंग अप' और हाल ही में टेस्ला के 'ऑप्टिमस' के सावधानीपूर्वक तैयार किये गए वीडियो देखे हैं। जाहिर है कि ये अभी अलग-अलग तरीकों से प्रभावशाली हैं, लेकिन वे पूर्ण 'पैकेज' के करीब नहीं पहुंचे हैं। ऑप्टिमस या एटलस को किसी गैर पूर्व निर्धारत स्थान पर छोड़ दें और आप बहुत कुछ अलग देखेंगे। हमारे घरों में काम करने में सक्षम एक मानव रोबोट को कई अलग-अलग कार्य करने, हमारे उपकरणों का उपयोग करने, हमारे वातावरण में गतिविधियां करने और मानव की तरह हमसे संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह केवल एक या दो साल में सच हो सकता है, तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।